हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2018 को अध्यक्ष, डॉ० राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

28.03.2018/1100/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 272

श्री नरेन्द्र बरागटाः अध्यक्ष महोदय, मैं खेल मंत्री जी का आभारी हूं लेकिन आपके माध्यम से मैं, मंत्री जी के ध्यान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं कि सरस्वती नगर का यह स्टेडियम माँ हाटेश्वरी के आँचल में है और काफी समय से निर्माणाधीन है लेकिन दुर्भाग्य से पिछले पांच साल के अन्दर जो कुछ काम उसमें पहले हुआ था, खिड़कियां टूट गई हैं, रेलिंग खत्म हो गई है और उस पर किसी की तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ। उसमें लाखों रूपया खर्च हुआ लेकिन युवाओं को आगे बढ़ाने का जो काम होना चाहिए था वह पांच साल में नगण्य रहा। मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हिमाचल के युवाओं को प्रांतीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उतारना है और अपने प्रदेश का नाम खेल जगत में ऊंचा करना है तो कुछ सुविधाओं का वहां पर आधुनिकीकरण किया जा सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र में बहुत सारी ज़मीन उपलब्ध है। मैं, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर 400 मीटर का सिंथैटिक रनिंग ट्रैक बनाया जाए और इसका तुरन्त विस्तार किया जाए, जो इसमें कमियां है उनको पूरा किया जाए। चूंकि यहां पर ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर के कैम्प भी लगाए जा सकते हैं और बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं वहां पर प्रोवाइड की जा सकती है। उससे सबसे बड़ा लाभ यह होने वाला है कि हमारा प्रदेश खेल जगत में सितारे की तरह चमक सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री जी मुझे आश्वस्त करेंगे कि जो ये 400 मीटर का ट्रैक तथा इसका विस्तार और भी जो सुविधाएं हैं, उनको कब तक पूरा करेंगे?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमें यहां पर खुले स्थान नहीं मिलते लेकिन राज्य के महाविद्यालय सरस्वती नगर जिला शिमला में 90 बीघा भूमि है जहां पर

28.03.2018/1100/जेके/एजी/2

स्टेडियम निर्माण के लिए 30 दिसम्बर, 2002 को तत्कालीन उद्यान एवं विधि राज्य मंत्री आप थे और आपके द्वारा ही उसका शिलान्यास किया गया था। उसके पश्चात् शायद बीच में सत्ता परिवर्तन के कारण वर्ष 2007-08 में वहां केवलमात्र 3 लाख रूपया आया, वर्ष 2008-09 में वहां के लिए 22 लाख रूपया आया, वर्ष 2011-12 में 60 लाख रूपया आया, वर्ष 2012-13 में 16 लाख और फिर वर्ष 2013-14 में 22 लाख रूपया आया, यानि 1 करोड़ 35 लाख रूपया उस पर खर्च किया जा चुका है।

28.03.2018/1105/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 272 क्रमागत

वन मंत्री क्रमागतः

और 2013 में वह काम भी पूरा हो गया लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके बाद इस सारे स्टेडियम की देख-रेख किसी ने नहीं की। अब लगभग इसकी हालत खंडहर जैसी है। एक तो अभी हमने उसके रख-रखाव के लिए 10 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। लेकिन माननीय सदस्य जैसा चाहेंगे, उसकी पूरी एक्सपेंशन करने के लिए, उसको अच्छा विस्तार देने के लिए जिन-जिन चीज़ों और धन की आवश्यकता होगी, पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते उसको उपलब्ध करवायेंगे।

एक अगली बात आपने कही कि 90 बीघे का बहुत बड़ा मैदान है और यदि आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों को वहां पर लाभ मिले, जो सिंथैटिक ट्रैक 400 मीटर का कह रहे हैं तो उसमें मैं माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आश्वस्त करूंगा कि सिंथैटिक ट्रैक के लिए कितना एस्टीमेट बनेगा, क्या उसकी मैपिंग होगी, सब कुछ करवा कर उस पर जितनी राशि लगेगी, वह सारी राशि उपलब्ध करवा कर उसे बहुत बढ़िया बनाकर देंगे। तत्पश्चात् शिक्षा विभाग इसको सम्भाले ताकि इसका रख-रखाव सही ढंग से हो सके और खेलों के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें।

28.03.2018/1105/SS-AG/2

प्रश्न संख्याः 273

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना एकत्रित की जा रही है, यह बात ठीक है। लेकिन कुछ सैद्धांतिक प्रश्न मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जितना भी हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है, किसी-न-किसी नियम/सिद्धांत से इनकी सेवा शर्तें गवर्न होती हैं। मेरा ख्याल है, मैं अगर गलत न हूं तो 45th लेबर कमिशन की सिफारिशें हैं जिसको देश के प्रधान मंत्री चेयर करते हैं, उसके भी कुछ डायरेक्शन्ज़ हैं और जो हमारा राज्य का मिनीमम वेज़ बोर्ड है वह भी इन कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सिद्धांत निर्धारित करता है। क्या सरकार इन शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है जहां तक उसका वेतनमान, ई0पी0एफ0 और दूसरी सेवा शर्तों का प्रश्न है? मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि आज हालात ये हैं कि 20000/- से अधिक न्यूनतम वेतन है। लेकिन ई0पी0एफ0 भी जो कम्पनी को डिपोजिट करना होता है वह आज कर्मचारी से डिपोजिट किया जा रहा है। जितनी भी कम्पनीज़ कर्मचारियों को आउटसोर्स कर रही हैं क्या सरकार निर्धारित न्यूनतम सिद्धांतों का पालन करवाने के लिए तैयार है या नहीं?

अध्यक्षः आपकी सप्लीमेंटरी आ गई, मूल प्रश्न का ही उत्तर नहीं है फिर भी अगर मुख्य मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत लम्बा है और अलग-अलग दिशा में इसमें चीज़ें जोड़ी गई हैं लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रश्न के "क" व "घ" भाग में विस्तृत सूचना मांगी है। उसमें बहुत सारे निगम, बोर्ड संलिप्त हैं, जिस तरह से आपने अंदेशा लगाया कि इनका नम्बर बहुत ज्यादा है उसकी वजह से सूचना एकत्रित करने में हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था। इस कारण से हमने कहा कि जब तक पूरी सूचना एकत्रित नहीं होती है तब तक इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है। जहां तक आपने उनके ई0पी0एफ0 से संबंधित बात कही है कि ई0पी0एफ0 का पैसा भी कम्पनी उनके खाते से ही ले रही है जिनके माध्यम से आउटसोर्सिंग हुई है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी नियम हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करेंगे और आउटसोर्सिंग के अन्तर्गत

जिन कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं उनका शोषण नहीं होने देंगे। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे।

28.03.2018/1110/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या 273 जारी---

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी इसकी सूचना एकत्रित नहीं की है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रदेश में करीब 25 हजार के लगभग कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर लगे हैं। सिंघा जी ने बात लम्बी खींच दी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का एक्सप्लॉइटेशन कॉंट्रैक्टर्ज़ के द्वारा किया जा रहा है। मिनिमम वेजिज़ पर, उदाहरण के लिए जैसे ड्राईवर है या चपरासी हैं, सरकार प्राइवेट कम्पनीज़ को 10 हजार दे रही है और वह आगे इम्प्लॉईज़ को पांच, छः या सात हजार रुपये दे रही है। मिनिमम जो वेजिज़ है किसी भी केटैगरी के इम्प्लॉईज़ के लिए चाहे ड्राईवर है, क्लास-iv है, डाटा ऑप्रेटर्ज़ हैं, जो सरकार द्वारा फिक्स किए गए हैं, सरकार कम से कम यह निर्धारित तो करें कि जिन कम्पनीज़ ने उनको लगाया है, वह मिनिमम वेजिज़ जो सरकार द्वारा निर्धारित किए हैं, कम से कम वो तो उनको दें। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, जैसे सिंघा जी ने कहा।

अध्यक्षः हर्षवर्धन जी, मूल प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया तो सप्लीमेंटरी कहां से आया?

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को जानकारी दे रहा हूं कि इस ओर सरकार ध्यान दें और इम्प्लॉईज़ की एक्सप्लॉइटेशन न हो।

अध्यक्षः चलो, सजैशन है । इसमें तो कोई उत्तर नहीं आएगा ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य का सुझाव है। जो इन्होंने बात कही यह हमारी जानकारी में भी है कि जो उनको निर्धारित वेतन तय होता है उससे भी कम राशि उनको मिल रही है लेकिन ये सुनी-सुनाई बातें हैं। जब तक इसकी फैक्चुअल पोजीशन नहीं आती है, इसीलिए हमने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब तक फैक्चुअल पोजीशन इसकी हमारे पास नहीं आ जाती, तब तक इसका सही उत्तर

हम नहीं दे सकते। कम्पनियां कितना पैसा काट रही है, क्यों काट रही है, किस बजट से काट रही है, इन सारी चीजों को लेकर डिटेल में हम तभी जानकारी दे पाएंगें जब इस प्रश्न का उत्तर हम देंगें। अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है।

अध्यक्षः विनोद जी, ऐसा है कि जब मूल प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया तो सप्लीमेंट्री किस चीज़ की करेंगें आप। यही मैं हर्षवर्धन जी को भी और यही आपको भी कह रहा हूं।

28.03.2018/1110/केएस/डीसी/2

प्रश्न संख्याः 274

श्री सुरेन्द्र शौरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बंजार विधान सभा के अंदर जो विद्युत परियोजनाएं हैं, उनमें पार्बती स्टेज-॥ 800 मैगावाट की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह परियोजना कब पूर्ण होनी थी और इसके इतने लेट होने के क्या कारण हैं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननयी सदस्य जी ने पार्बती स्टेज-॥ के बारे में जानना चाहा है, वह लगभग 800 मैगावाट की विद्युत परियोजना है। इसका जो शैड्यूल टारगेट हमें दिया गया है, जो एन.एच.पी.सी. के माध्यम से हमें जानकारी दी गई है, वह टारगेट 2020 तक का है, यह मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं।

28.03.2018/1110/केएस/डीसी/3

प्रश्न संख्याः 275

अध्यक्षः जिलालाल जी, क्या आप सप्लीमेंट्री नहीं पूछेंगें? आपका उत्तर आ गया?

श्री जिया लालः जी, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी, आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अधिकतर यह कार्य जो हमारी गद्दी ट्राइब है, उनके माध्यम से ही होता है। ये लोग जैसे भरमौर से चलते हैं तो इनका लास्ट स्टॉप नूरपुर में है। 15 हजार से ऊपर लोग हमारे क्षेत्र में अपना माल ले कर आते हैं और बसते हैं। रास्ते में बहुत से इन्सिडैन्सिज़ होते हैं जहां पर इनकी poaching होती है और रास्ते में जहां-जहां से गुज़र कर आते हैं, कई बार कोई ट्रक वाला इनकी भेड़-बकरियों पर चढ़ जाता है और 15-15, 20-20 इकट्ठी ही भेड़ें उनकी मर जाती है और जब उनके क्लेम के लिए वे जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इसका मैडिकल ले कर आओ। अब रात के अंधेरे में जब यह सारा कांड होता है, दो भेड़े मरती है या पांच मरती हैं एक तो उनका मैडिकल पॉसिबल नहीं होता और उनको कुछ क्लेम नहीं मिलता दूसरा ये बिल्कुल अनसिक्योर्ड है। इनकी poaching बहुत ज्यादा होती है और दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब ये हमारे क्षेत्र में आते हैं, ये जब तक हमारे जंगलों में नहीं घूमेंगें तब तक हमारी फसल नहीं होगी। हमारे बूटी मरती रहेगी । They are very useful to us. जब ये जंगलों में छोड़ते हैं वहां पर पोर्चिंग बड़ी होती है। इसके लिए बड़ा सख्त कानून लाना पड़ेगा ताकि इसको रोका जा सके।

28.3.2018/1115/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 275 -------- क्रमागत

श्री राकेश पठानिया जारी

हमारा छोटा ट्राइब जो प्रदेश के ऊपरी इलाके से अपनी भेड़-बकरियां ला रहा है उनका सारा कारोबार सड़क पर चल रहा है। वह सैक्योर नहीं है तो क्या सरकार इनके लिए कोई पोलिसी बनाने बारे सोच रही है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल रूप से बकरी की चोरी का है। मगर यह बात

सच है कि बीच-बीच में ऐसी घटनाएं भी होती है जब गद्दी लोग अपनी भेड़-बकरियों को सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इनका स्थान लगभग हर रोज बदलता रहता है क्योंकि इनके लिए एक जगह पर चारा उपलब्ध नहीं हो पाता तथा मौसम के हिसाब से भी गद्दी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए शिफ्ट होते रहते हैं। सड़क मार्ग से चलते हुए कई बार भेड़-बकरियां गाड़ी के नीचे आ जाती है जिससे इनको बहुत नुकसान होता है। यह प्रश्न अलग है और जैसे माननीय सदस्य ने बीमा करने के बारे में सुझाव दिया है तो इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस विषय को कैसे लागू कर सकते हैं हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन जो गद्दी लोगों का नुकसान होता है और उसमें जो मामला दर्ज होता है उसमें कानून के अंतर्गत कार्रवाई के प्रोविजन उपलब्ध है। अगर किसी गाड़ी की वजह से उनको कोई नुकसान होता है तो उस गाड़ी वाले के विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई होती है। इसके अतिरिक्त चोरी का विषय अलग है और मैंने उस बारे में आपको सारी डिटेल दे दी है।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भेड़ पालक हमारे समाज की बहुत सारी जरुरतों को पूरा करते हैं। जब गद्दी लोग लाहौल या दूसरे ऊपरी क्षेत्रों से माह अक्तूबर-नवम्बर में नीचे आते हैं या गर्मी के मौसम में माह मार्च-अप्रैल में अपने क्षेत्रों को लौटते हैं तो रास्ते में कई इंटीरियर एरियाज पड़ते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खोउरु-जोत और कपराणी जोत इत्यादि जगह पर भी गद्दी लोग स्टे करते हैं। वहां पर वे लोग अपनी भेड़-बकरियों के लिए बाड़े

28.3.2018/1115/av/dc/2

बनाते हैं। कई बार उसमें बाघ घुसकर भेड़-बकरियों को नुकसान पहुंचाते हैं जिसका उनको मुआवजा नहीं मिलता। इंटीरियर एरिया में वैटरिनरी फार्मासिस्ट गाड्र्ज और प्रधान इत्यादि जिन्होंने वहां देखना होता है वे मौके पर नहीं जाते। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी गर्दन से लेकर नीचे तक पूरा शरीर बचा होना चाहिए फिर क्लेम मिलेगा।

दूसरे, इंटीरियर एरिया में भी चोरी होती है और उस चोरी का मालूम नहीं पड़ता। पिछली बार लाहौल से एक भेड़ पालक आया और उसने मुझे फोन किया। मैंने आगे थाने में फोन किया तो वहां से उत्तर आया कि यह क्षेत्र हमारे थाना के अंतर्गत नहीं आता। यह बात सच्ची है क्योंकि वहां पर बड़ी-बड़ी हिल्स हैं और उनको आईडैंटिफाई ही नहीं किया गया है कि किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तीसरा, बीमारी के कारण हिल एरिया में भेड़ पालकों की भेड़ें या बकरियां मरती हैं तो उनको भी आईडैंटिफाई नहीं किया जाता। वहां पर जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को जाना चाहिए वे नहीं जाते हैं और भेड़-बकरी पालक मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस कमी को दूर करें ताकि उनको उचित मुआवजा मिल सके।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब गद्दी लोग अपनी भेड़-बकरियां लेकर के जंगल से गुजरते हैं तो उन पर जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। कई बार जंगली जानवर अंधेरे में अटैक करके उनकी भेड़-बकरियों को मार देते हैं जिसका कम्पनसेशन लेने में उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो जहां से गद्दी लोग चलते हैं वे एरियाज बहुत दुर्गम होते हैं। अगर इनको कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए एक लम्बे प्रोसिजर से गुजरना पड़ता है। उसके लिए पहले शिकायत करनी पड़ती है फिर वैटरिनरी डाक्टर से पोस्ट मोर्टेम रिपोर्ट आने के बाद उसमें कम्पनसेशन का प्रोविजन उपलब्ध होता है।

28.03.2018/1120/TCV/HK-1
प्रश्न संख्या.275... क्रमागत्
माननीय मुख्य मंत्री.... जारी

लेकिन वह कम्पनसेशन बहुत कम है। इस बात से हम सहमत है। उनको कम्पनसेशन बहुत कम मिलता है और नुकसान बहुत ज्यादा होता है। हम इस बारे में विचार करेंगे

कि इसमें क्या किया जा सकता है।

दूसरी बात आपने भेड़-बकरियों की चोरी के बारे में कही है। जब वे भेड़-बकरियों को ले जाते हैं, तो ये चोरी भी हो जाती है। लेकिन इस बारे में हमारे पास चोरी के मामले बहुत ज्यादा नहीं है। अभी तक 26 मामले पंजीकृत हुए है जिनमें से 11 अभी तक ट्रेस नहीं हो पाये हैं। वे अभी अनट्रेसेबल है और 10 दोषियों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किए गये हैं। इनमें से 5 मामलों की इन्वेस्टीगेशन चल रही है। लेकिन हम आपकी भावनाओं से सहमत है कि वे गरीब लोग होते है और उनकी आय का साधन वही होता है। वही उनकी सम्पत्ति हैं। ये लोग ऐसे लोग होते हैं, जिनका साल भर अपने घर जाना संभव नहीं होता है। ये लोग शिफ्टों में घर जाते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए इनके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है। हम इनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि इस तरह के जो अपराधी पकड़े जाते हैं, उनकी सूची थानों में रखी जाती है, ताकि कोई इस तरह की वारदात में लगातार शामिल रहे, तो उसको पकड़ने में आसानी होती है। पिछले 3 वर्षों में भेड़ की चोरी में संलिप्त 27 अरोपियों को गिफ़्तार किया गया। जिनके खिलाफ़ कोर्ट में चालान प्रस्तुत हुए हैं। चम्बा और जम्मू-कश्मीर सीमा पर पुलिस की 13 चौकियां स्थापित की गई है और 299 पुलिस कर्मचारी भी भेड़ पालकों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गये हैं। उनके पास और भी काम है, लेकिन उसमें इनकी सुरक्षा को भी शामिल किया गया है।

श्री जिया लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार भेड़ पालकों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है?

28.03.2018/1120/TCV/HK-2

दूसरा, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी आग्रह रहेगा कि भेड़ पालकों को

अपनी और भेड़ों की सुरक्षा के लिए गन लाईसैंस जारी किये जायें।

अध्यक्षः भेड़ पालकों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या किया जा रहा है, इसका उत्तर तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने दे दिया है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, भेड़ों की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण तो भेड़ पालकों की सुरक्षा है, ये बात आपकी ठीक है। जैसा मैंने बताया है कि हम दोनों की सुरक्षा के लिए कदम उठाते हैं। जहां तक हथियार देने की बात है, इसके लिए वे अप्लाई करते हैं और बहुत-सारे भेड़ पालकों ने भेड़ों और अपनी निजी हिफ़ाजत के लिए वैप्न भी लिए हैं। इसमें अगर और आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी तो इस पर सरकार विचार करेगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इन्होंने जम्मू-कश्मीर बाउंडरी की जो बात कही है, वह एक्चुअली मेरा और माननीय उपाध्यक्ष महोदय का ही चुनाव क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ये बताया कि 27 मामले पिछले वर्षों में पंजीकृत हुए हैं। लेकिन मैं मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि ये दो तरह के मामले हैं। एक तो जो गांव में भेड़ चोरी हो जाती है, वे तो ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन आपने जो जम्मू-कश्मीर सीमा की बात कही है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें जो जम्मू-कश्मीर के बकरवाल है, ये हमारे बाउंडरी में घुस करके यहां से भेड़-बकरियों को चारी करके ले जाते हैं। वे ट्रेस नहीं हो पाती हैं। अभी तक एक भी केस ट्रेस नहीं हुआ है। यहां पर ऑफिसर गैलरी में कमीश्नर और डिप्टी कमीश्नर बैठें है, ये भी आपको इसके बारे में बता देंगे। वे केस ट्रेस नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि बकरवालों को हम अपनी बाउंडरी में अंदर आने ही क्यों देते हैं? वे हमारी लैंड़ पर आकर they are grazing on our land and they don't have any permits. उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

28-03-2018/1125/NS/HK/1

प्रश्न संख्याः 275 ------क्रमागत

श्रीमती आशा कुमारी -----जारी।

अध्यक्ष महोदय, इसका मुख्य कारण है कि पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है और वन विभाग भी कार्रवाई नहीं करता है। क्या आप इस तरह के आदेश देंगे कि वन विभाग और पुलिस विभाग मिल करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? वहां पर जो grazing कर रहे हैं और bad intentions से आते हैं तथा हर साल चोरी करते हैं। इस भेड़ चोरी की संख्या भी ज्यादा होती है। गांव में चोरी होती है, उसमें तो एक भेड़ या दो भेड़ कहीं से ले गये, वह तो अलग बात है। मगर यह जो सीमावर्ती इलाके में चोरी होती है, यह 20, 25 या 50 भेड़ इक्ट्ठी ले जाते हैं। क्या ज्वाईंट ऑप्रेशन्ज़ करके जो लोग उस एरिया में grazing करने के लिए entitled ही नहीं हैं, उनको वहां अन्दर न घुसने देने के लिए पुलिस और वन विभाग कदम उठायेगी, क्या आप ऐसे आदेश देंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, चम्बा जिले के इस प्रकार के बहुत मामले तो नहीं हैं। सिर्फ वर्ष 2016 में एक मामला दर्ज़ हुआ है और यह मामल न्यायालय में चल रहा है। लेकिन जो आपने इस तरह की शंका और संभावना जाहिर की है, इस बात से हम भी सहमत हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोग/बकरवाल वहां से आते हैं। पहला प्रश्न तो यह भी है कि वे हमारे हिमाचल प्रदेश की बाउंडरी में आये ही क्यों? उनको नहीं आना चाहिए। हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि वे हिमाचल की बाउंडरी में न आयें। अगर आ करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दें तो यह और भी ज्यादा चिन्ता का विषय है। हम कोशिश करेंगे। आपने कहा कि पुलिस और वन विभाग को ज्वाईंट आप्रेशन के लिए आदेश करें। हम इस प्रकार की घटना के लिए सुनिश्चित करेंगे कि वे एक तो हिमाचल की सीमा में न आयें और अगर आयें तो यहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई प्रावधान के मुताबिक होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ अगर चोरी करने की बात आती है तो इसमें पुलिस और वन विभाग दोनों इक्ट्ठे मिल करके कार्रवाई कर सकते हैं और वे करेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है और यह जवाब इन्होंने लिखित में भी दिया है। जब हमारे भेड़-पालक winter or summer pastures में migrate करते हैं, उस समय यह कह रहे हैं कि पुलिस वाले अपने थाना क्षेत्रों या चौकियों का जो इलाका है, वहां पर गश्त बढ़ाते हैं। मैं इस बात से

28-03-2018/1125/NS/HK/2

बिल्कुल सहमत नहीं हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी जो बात आपने यहां पर रखी है, क्या आप इसको सुनिश्चित करेंगे कि जब भी हमारे भेड़-पालक winter grazing के लिए जाते हैं, जैसे सितम्बर और अक्तूबर में किन्नौर से निचले क्षेत्रों की तरफ आते हैं और भरमौर, लाहौल और स्पिति से आते हैं या गर्मियों में अप्रैल या मार्च में जाते हैं, उस समय जितने भी थाने या चौकियां हैं, क्या आप इनको लिखित में आदेश करेंगे कि भेड़-पालकों की भेड़ चोरी न हो, इसके लिये ये चौकसी बरतेंगे? दूसरी बात जो आपने कही कि पूरे प्रदेश के कुल 26 केस चोरी के आये हैं। ये केस इसलिए कम हैं क्योंकि आप जानते हैं कि भेड़ पालक दो या तीन लोग होते हैं और 300-400 बकरियों के साथ जाते हैं। अगर रास्ते में चोरी हो गई तो जो बची हुई बकरियां हैं, वे भी चली जायेंगी। पिछले कुछ अर्से से चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। बाहरी सीमा से आ करके चोरी करने वाले अलग हैं। लेकिन रास्ते में जो चोर आ रहे हैं, उनसे इन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि इन चोरियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठायेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सहयोग की दृष्टि से अभी तक ऐसा है कि जब यह सीज़नल मूवमैंट होती है, अभी तक इस प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वे पुलिस वालों को सूचना दें। उनकी ओर से इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन आने वाले समय के लिए जो आपने बात कही है तो इस बात पर विचार किया जा सकता है कि जब इनकी मूवमैंट का सीज़न होता है और जो इनका रूट होता है तो पुलिस इनको सहयोग करे। इस दृष्टि से इनकी मदद हो सकती है। इस बात पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है? यह कठिन काम है। क्योंकि इनका रूट बहुत लम्बा होता है और यह लोग दिन-रात चलते हैं। हमारे पास पुलिस फोर्स भी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम भेड़ की रक्षा के लिए पुलिस को वहां पर भेजें तो कामकाज़ की दृष्टि से भी दिक्कत आयेगी। इसके बावजूद भी आपने कहा है तो यह अच्छा सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है? यह बात ठीक है कि

28.03.2018/1130/RKS/YK-1

प्रश्न संख्याः 275... जारी

माननीय मुख्य मंत्री... जारी

सचमुच में जो भेड़-पालक होते हैं उनके साथ ज्यादा लोग नहीं होते हैं। 500 या हजार माल के साथ कुल मिलाकर दो या तीन आदमी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कोई माल चोरी हो जाए या कोई घटना हो जाए और उसके लिए पुलिस स्टेशन में एफ.आर.आर. दर्ज़ करने के लिए जाना पड़े तो बाकी भेड़/बकरियों की देखभाल कौन करेगा? यह सचमुच में एक विकट परिस्थिति है। यदि भेड़-पालक ऐसी जगह से गुजर रहे हों कि वहां पर थाना नज़दीक हो, वहां पर तो इसकी शिकायत की जा सकती है। लेकिन जंगल में भेड़-बकरियों को छोड़कर थाने में चले जाना ज्यादा व्यावहारिक नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कठिनाई है। लेकिन इन सारी चीजों के लिए हम कोई हल निकालेंगे। चोर कोई दूर से नहीं आते हैं। वे पास के गांव से ही आते हैं और वहीं से वे भेड़ या बकरी को उठा कर ले जाते हैं। जब भेड़- पालक को चोरी की भनक लगती है, तब तक वे बकरा साफ कर देते हैं। इसको रोकने की दृष्टि से जो किया जा सकता है, वह हम करेंगे। आपने व्यावहारिक चीजें बताई है और सरकार की ओर से जो हो सकता है, वह हम करेंगे।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी, वैसे विषय चोरी का था परन्तु इसके अंदर वन विभाग से एक स्टडी जरूर करवानी चाहिए कि इनकी मुवमैंट से कितने सैप्लिंग्स और जंगल में जो नये पौधे निकलते हैं उन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। उन जंगलों को प्रोटैक्ट करने के लिए कुछ योजना बननी चाहिए। जिन जंगलों में भेड़ पालक जाएं वे अलग हो (...व्यवधान...)। उस चीज़ को स्टडी किया जाए। (...व्यवधान...)।

28.03.2018/1130/RKS/YK-2

<u>प्रश्न संख्याः276</u>

श्री पवन नैय्यरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ खिलाड़ी आए थे। उन्होंने चिंता जाहिर की कि जब वे पंजाब में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनसे ग्रेडिंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जबकि यह हिमाचल में लागू नहीं है और इसका खिलाड़ियों को कोई फायदा नहीं मिलता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि यह सिस्टम यहां लागू किया जाए ताकि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, उनको बैनिफिट मिल सके।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने अपने प्रश्न में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के रैंकिंग सिस्टम के बारे में पूछा है। अभी यहां पर रैंकिंग सिस्टम लागू नहीं हुआ है और न ही इसके लिए कोई योजना बनी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण है। जिसे हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओलम्पिक गेम्स, कॉमनवैल्थ गेम्स या एशियन गेम्स में जो भी मैडल विजेता होगा उसे कैटेगरी नम्बर-1 में रखा जाएगा। इसी प्रकार से कैटेगरी 2, 3 और 4 बनाई गई है। लेकिन जो आपने पंजाब के बारे में कहा इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। पंजाब सरकार के साथ इसके बारे मे बातचीत करेंगे और जो भी इसमें सम्भव होगा उसे हम निश्चित रूप से करेंगे। दूसरा, अभी कॉमनवैल्थ गेम्स होने वाली है और कॉमवैल्थ गेम्स में प्रदेश के किसी भी राज्य ने पैसे की कोई घोषणा नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार आने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश का जो भी खिलाड़ी कॉमनवैल्थ गेम्स में गोल्ड मैडल लेकर आएगा उसको हम 30 लाख रुपये देंगे। जो सिल्वर मैडल लेकर आएगा उसको 20 लाख रुपये तथा जो ब्रौंज़ मैडल लेकर आएगा उसको 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ में उसी के मुताबिक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।

28.03.2018/1135/बी0एस0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्याः 276 क्रमागत

वन मंत्री.....जारी

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम स्पोर्टस के मामले में हरियाणा की तर्ज पर विचार कर रहे हैं क्योंकि यह कहा जाता है कि देश में हरियाणा की खेलों में सबसे अच्छी नीति है। उस पर भी हम काम कर रहें है और बाकी प्रदेश में भी हम अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे।

श्री विक्रमादित्य सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि खेलों का जो विषय है यह बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली सरकार द्वारा भी दो खिलाड़ियों को डी.एस.पी. पद से नवाजा गया था। कए कबड्डी में और एक क्रिकेट में सुषमा वर्मा जो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र से हैं। मैं हिमाचल प्रदेश स्पोर्टस राईफल एसोशिएशन का अध्यक्ष हूं। अभी जो इसमें दिक्कत आ रही है वह यह है कि राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी, कॉमनवैल्थ पर भी और ओलोंपिक्स पर भी और शूटिंग में भी, बहुत सारे मैडल्स हिमाचल प्रदेश को और भारत को आते हैं। मगर अभी जो हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, कॉलेजिज हैं इसमें इनके लिए कोटा नहीं रखा गया है। इसकी वजह से जो खिलाड़ी हैं उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे खिलाड़ी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सरकार के सामने हमारी मांग रखी जाए कि यूनिवर्सिटी में इसके लिए अलग से कोटा रखा जाए। ताकि शूटर्स आने वाले समय में इससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि आने वाले समय में इन्डविजवल इवेंट्स हैं उसको हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उसमें राईफल शूटिंग है या स्कीट है, ट्रैप है ये ऐसी खेलें है जिनमें प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकते हैं।

अध्यक्षः कृपया आप प्रश्न करें।

श्री विक्रमादित्य सिंह : मेरा यह निवेदन रहेगा कि इसको यूनिवर्सिटी लैवल पर कोटा रखा जाए तो अच्छा रहेगा।

28.03.2018/1135/बी0एस0/वाई0के0-2

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार मात्र इन्डविजवल खेलों में ही नहीं, बल्कि हमने विचार किया है कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश में हर तर की खेलें हु जैसे फुटबॉल, बॉलिबाल है, कुश्ती है और कबड्डी है यह सारी खेलें हैं। लेकिन उसके साथ हमारे पास ऐडवेंचर गेमज हैं, शीतकालीन खेले हैं, वाटर स्पोर्टस हैं। हमरे देश से जो जुड़ी हुई खेलें हैं उन सब के बारे में हमने एक विचार किया है कि हम प्रदेश की जो खेल नीति है यह सन् 2002 की बनी है। हम इस स्पोर्टस पॉलिसी को संशोधन करके जो 16 साल पहले की बनी है, उसको भी ठीक कर रहे हैं। दूसरा स्पोर्टस कोंसिल में जो वेलफेयर फंडस हैं उसके बारे में जो गाइड लाइन 1983 की हैं । मैं आपकी जानकारी के लिए कहूंगा कि इसीलिए सारी दिक्कतें आती है। अब हम उसको भी नए सिरे से बनाएंगे ताकि 2018 के माध्यम से वह सारी कमियां पूरी की जा सकें। बाकी जैसा आपने कहा जो शिक्षा विभाग से संबंधित मामला भी है, हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी चर्चा करके जो भी सही होगा निश्चित रूप से हम करेंगे। हर तरह के खेल और खिलाड़ी के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी पहले की तरह पलायन न कर जाएं, उनको संभालने का पूरा जिम्मा हिमाचल प्रदेश सरकार लेगी।

अध्यक्ष : अंतिम सप्लीमैंटरी श्री सुख राम जी।

श्री सुख राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारी खेल नीति बहुत पुरानी है, क्या हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में अच्छी खेल नीति बनाने पर प्रदेश सरकार विचार करेगी? ताकि खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल सके। हमारे जो अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं उनको यहां पर प्रोत्साहन नहीं मिलता और वे पंजाब और हरियाणा आदि बाहरी स्टेटों में खेले खेलते हैं और हिमाचल प्रदेश इस बात से प्रोत्साहित नहीं होता है।

28.03.2018/1135/बी0एस0/वाई0के0-3

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुख राम जी ने जो कहा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार खेल नीति भी बना रही है और हमने एक बात निश्चित की है कि अब ये सरकार हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी स्पोर्टस यूनिवर्सिटी और स्पोर्टस एकेडमी प्रदेश में स्थापित करेंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक बात पक्का है। इस सरकार ने यह भी कहा है कि हमारे सरकारी अधिकारी भी हमारी स्पीड से चलने का काम करें। हमारी सरकार ने जो- जो कहा है और जो-जो तय किया है वह हम सब करेंगे। आप कतई चिंता न करें।

28.3.2018/1140/DT/AG/-1

<u>प्रश्न संख्याः 277</u>

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो की राजनीतिक राजमार्ग है, क्योंकि चुनावों से पहले मंत्री जी को बुलाकर 69 राष्ट्रीय उच्च मार्ग अनाउंस करवा दिए गये। ...व्यवधान... यह वही है जो माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि अस्पताल खोल दिए या शिक्षा संस्थान खोल दिए। यह इससे भी बड़ा केस है क्योंकि 69 हाईवे अनाउंस करवा दिए गए। जो गांव का रूट भी नहीं था, डिस्ट्रिकट रूट भी नहीं था, जो स्टेट रूट भी नहीं था उसको राष्ट्रीय उच्च मार्ग अनाउंस करवा दिया गया।...व्यवधान... माननीय मंत्री जी को जवाब देने की ज्यादा जल्दी है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए। आप मुझसे बात कीजिए।

मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से

प्रश्न पुछ रहा हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ सम्बोधन कीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से 69 राजमार्ग इन्होंने अनाउंस करवाए और पूरे प्रदेश में एक ववंडर मचा दिया की साठ हजा़र करोड़ रूपये आ गया, 65 हज़ार करोड़ रूपये आ गया। इनके सारे लोग यह बोलने लग पड़े कि इतना पैसा आ गया है। क्योंकि इसमें आपके सांसदों की शाख का भी सवाल था। यह राजमार्ग कुछ उन्होंने और कुछ विधायकों ने डलवाये और सभी नोटिफाई कर दिए। अध्यक्ष महोदय, यह 42 सौ किलोमीटर की लाइन है और यह अगले 50 सालों में भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पुछना चाहता हूं कि यह कन्सलटैंसी कब तक ऑवर हो जाएगी? दूसरा, इसकी डी0पी0आर0 कब तक बन जाएगी? तीसरा, यह आवार्ड कब तक हो जाएंगे। चौथा, क्या यह 4210 किलोमीटर की लैंथ आपके इस कार्यालय में बनकर तैयार हो जाएगी?

28.3.2018/1140/DT/AG/-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य इस प्रश्न के संदर्भ में जाना चाह रहे हैं, वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे केन्द्र में जो मंत्री है,जो वे कहते हैं, उसे वे करके छोड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय,यह काम चुनाव के दिनों में नही किया गया है। जब हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए लगभग डेढ़ वर्ष था उस वक्त हमारे केन्द्रीय मंत्री माननीय नितन गडकरी जी धर्मशाला आए और धर्मशाला में उस वक्त के मंत्री श्री जी0एस0 बाली जी ने धौलाधार में उनके साथ प्रैस कॉफ्रैंस की और उस प्रैस कॉफ्रैंस में 17 नैशनल हाईवे की घोषणा की। इस बात का मुझे सचमुच में दुःख है जिस बात का हिसाब आप हमसे मांग रहे हैं अगर हम ही इस संदर्भ में आपसे बात कर लें कि उस घोषणा के बाद लगभग ड़ेढ वर्ष का कार्यकाल आपकी सरकार का

गुजरा है। उसके बाद वक्त गुजरता गया। केन्द्र से यह कहा गया कि आप डी0पी0आर्ज0 बनाओ और केंन्द्र से यह भी कहा गया डी0पी0आर्ज0 का पैसा भी हम देने के लिए तैयार है।

28.03.2018/1145/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 277....जारी

माननीय मुख्य मंत्री ...जारी

लेकिन क्या वजह रही कि इस डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में मात्र 8 डी.पी.आर्ज़. की आऊटसोर्सिंग का ही टैंडर हुआ । अगर यह डी.पी.आर्ज़. तैयार होतीं तो आज हम ज़मीन पर काम करने की स्थिति में आ जाते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें अनावश्यक विलंब हुआ है जो अब नहीं होने दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद मैंने विभाग की रिवियु मीटिंग में जब विस्तृत जानकारी ली तो चर्चा करने के पश्चात पता लगा कि अभी इनके टैंडर्ज की आऊटसोर्सिंग का प्रोसैस बाकी जगह शुरू ही नहीं हो पा रहा है। हमने उसी दिन आदेश किए कि हम चाहते हैं कि 31 मार्च तक 69 नेशनल हाईवेज के जो आऊटसोर्सिंग के टैंडर्ज़ हैं, उसके लिए जो प्रोसैस होना है उसे पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पूछा है, मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे आऊटसोर्सिंग के 43 टैंडर प्रोसैस हो गए हैं। अगर इनका योग करें तो यह कुल 51 बन रहे हैं। कुल 69 में से 51 हमारे प्रौसैस हो चुके हैं। अभी मेरा 3 महीने का कार्यकाल पिछले कल ही पूरा हुआ है। ...(व्यवधान)... डेढ़ सालों में आपकी 8 डी.पी.आर्ज़. की आऊटसोर्सिंग होती है जबकि उसके बाद 3 महीनों के हमारे कार्यकाल में 43 की होती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गति सही है और हम सही दिशा में आगे जा रहे हैं।

इन्होंने यह भी पूछा कि इसके टैंडर कब तक पूरे हो जाएंगे, मैंने कहा कि हम जल्दी-

से-जल्दी करेंगे। इसमें समय सीमा और दिन बताना उचित नहीं है लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत जल्दी डी.पी. आर्ज़. के आऊटसोर्सिंग प्रोसैस को कंपलीट करने के पश्चात, डी.पी. आर्ज़. को मुक्कमल करने के पश्चात उसी गति से हम आगे काम करेंगे। डी.पी. आर्ज़. बनने के बाद ज़मीन पर यह काम हो, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। हिमाचल प्रदेश में हमको टूरिस्ट्ज के हिसाब से सबसे बड़ी कठिनाई कनैक्टिविटी के इसु की आ रही है। ...(व्यवधान)... जब डी.पी. आर्ज़. का

28.03.2018/1145/SLS-AG-2

प्रोसैस पूरा होगा तो लैंड एक्युजीशन का प्रोसैस भी उसके बाद शुरू होगा। लेकिन डी.पी.आर्ज. बने, उसके बाद फिर हम तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। आप 50 साल की बात कह रहे हैं जबकि हम कह रहे हैं कि आप 5 सालों में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर देखेंगे। यह सड़कें जिनका कागज़ों में होने का आप ज़िक्र कर रहे हैं, यह कागज़ों में नहीं बल्कि ज़मीन पर दिखेंगी।

श्री सतपाल सिंह रायजादा : महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो ऊना-बसोली-बड़सर-सनोली एन.एच. घोषित हुआ है उसमें नाबार्ड से ऊना से बसोली के लिए सड़क निर्माण हेतु पैसा आ चुका है। आपका यह राजमार्ग पता नहीं कब बनेगा लेकिन क्या वह जो टूटी हुई सड़क है; वहां से बहुत से श्रद्धालु जाते हैं और वहां मेले लगते हैं लेकिन वहां सड़क की हालत खस्ता होती है जबकि पैसा मंजूर हो चुका है, क्या लोक निर्माण विभाग उस सड़क पर उस पैसे को लगाएगा?

अध्यक्ष : यह इससे संबंधित नहीं है। आप अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री सतपाल सिंह रायजादा : यह इसी से संबंधित है क्योंकि एन.एच. होने के कारण वहां पैसा नहीं लगाया जा रहा है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो 72

किलोमीटर की यह ऊना-बसोली-बड़सर-सनोली सड़क सड़क है, इसको 14 मई, 2015 को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि इसका काम जल्दी करवाया जाएगा।...(व्यवधान)...

श्री सतपाल सिंह रायजादा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इसके लिए नाबार्ड से पैसा आ चुका है। ...(व्यवधान)...

28/03/2018/1150/RG/DC/1
प्रश्न सं. 277---क्रमागत
श्री सतपाल सिंह रायजादा के पश्चात

अध्यक्ष : श्री सतपाल सिंह जी एक मिनट आप बैठिए। माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री सतपाल सिंह जी यह जानना चाहते हैं कि नाबार्ड का पैसा इसमें आया है, तो जब तक एन.एच. का काम नहीं होता तब तक आप इसको इम्प्लीमंट कराएंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ठीक है जो नाबार्ड का पैसा आया है और यह विधायक प्राथमिकता में है। **मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि जल्दी-से-जल्दी इसका काम शुरू कर देंगे और जब हमारा पैसा आएगा, तो उससे भी काम करेंगे। जब नेशनल हाइवे की फाईनल स्वीकृति आ जाएगी और इसकी डी.पी.आर. बन जाएगी, तो उसके माध्यम से भी इस पर काम करेंगे, लेकिन फिलहाल जैसा इन्होंने कहा है, तो विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत जो पैसा है, उससे भी काम करेंगे और नाबार्ड के पैसे से भी इस पर काम किया जाएगा।**

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर जो जवाब दिया है, इन्होंने उसमें फिर से राजनीति करने का प्रयास किया है। क्योंकि इन राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा ही राजनीति करने के लिए की गई थी कि प्रदेश में किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया जाए और किस ढंग से इसकी अधिसूचना जारी की जाए----(व्यवधान)---बिल्कुल कर रहे हैं,

आप चिन्ता न करें।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय यह बताएं कि इसके कन्सलटेन्सी के टैण्डर किसने करने थे? घोषणा के मुताबिक ऐस्टीमेटिड कॉस्ट 65,000 करोड़ रुपये हैं और 4,210 किलोमीटर लैन्थ बढ़नी है और इसके लिए मात्र 270 करोड़ रुपये आया है। 'खोदा पहाड़, निकली चुहिया।' ----(व्यवधान)---अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय हमें यह तो बता दें कि 4,210 किलोमीटर के नेशनल हाइवेज़ पर जो 65,000 करोड़ रुपये व्यय होने हैं, तो क्या इनको केन्द्र सरकार ने इस पैसे के लिए कमिटमेंट कर दी है? क्योंकि ये 10-12 बार इसके लिए दिल्ली जाकर आए हैं।

28/03/2018/1150/RG/DC/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय कांग्रेस विधायक दल के नेता ने पूछा कि यह टैण्डर कौन करेगा? तो ये प्रदेश सरकार द्वारा किए जाते हैं और उसके बाद भारत सरकार की सहमति इसके लिए आवश्यक होती है। दूसरी बात, इन सड़कों की इन-प्रिंसीपल स्वीकृति मिली है और जो इन-प्रिंसीपल स्वीकृति होती है, वह प्रेलिमिनरी ऐस्टीमेट के हिसाब से होती है जिस अमाउन्ट का ये जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में इन पर कितना पैसा खर्च होगा, यह आकलन डी.पी.आर. बनने के पश्चात होगा। माननीय सदस्य को इतनी जानकारी तो होनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि इनको इतना अनुभव नहीं है कि जब बजट स्वीकृति की बात आती है, तो बजट तब स्वीकृत होगा जब किसी भी प्रोजैक्ट की डी.पी.आर. बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद उसकी फाईनल सैंक्शन आएगी और उसके बाद पैसा आएगा। अभी जो पैसा उन्होंने स्वीकृत किया है, उसमें सिर्फ डी.पी.आर. की ऑऊटसोर्सिंग के लिए पैसा स्वीकृत किया है ताकि प्रदेश सरकार पर वह खर्च न पड़े। लेकिन केन्द्र सरकार ने इसके लिए भी कहा कि इसको भी हम ही वहन करेंगे, आप काम करें, आप बनाओ। उस दृष्टि से वह पैसा दिया गया है। न कि इस प्रकार से जो आप कह रहे हैं। तो डी.पी.आर. से पहले किसी भी स्कीम के तहत पैसा नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय सदस्य यह भी कह रहे हैं कि यह सब राजनीतिक दृष्टि से किया गया है। तो राजनीति का इससे दूर-दूर तक कोई लेना-देना

नहीं है। राजनीति तो तब हुई, जब ये सारे प्रोजैक्ट्स स्वीकृत होने के बावजूद इनको दफ़न कर दिया गया कि कहीं यदि हमने डी.पी.आर. का जिक्र कर दिया कि डी.पी.आर. का काम शुरू हो गया है, तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और चुनाव में हमारे लोग इसका जिक्र करेंगे। यह जिक्र ही न हो पाए इसलिए डी.पी.आर. बनाने का काम ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया और इस प्रोजैक्ट को बंद कर दिया। डेढ़ साल के कार्यकाल में मात्र आठ डी.पी.आर. बनाने की प्रक्रिया शुरू की और यहां आप तीन महीने में हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मैं यहां बताना चाहूंगा कि हमने तीन महीने के कार्यकाल में 43 डी.पी.आर्ज. की प्रक्रिया पूर्ण कर ली। इसलिए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि यदि राजनीति हुई है, तो उस तरफ (विपक्ष की इशारा करते हुए) से हुई है, इधर से नहीं हुई। हमारी मन्शा बहुत साफ है। हम विकास के मुद्दे पर कमिटिड हैं। केन्द्र सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है और उसमें हिमाचल प्रदेश प्राथमिकता पर है।

28/03/2018/1150/RG/DC/3

अब आने वाले समय में प्राथमिकता नंबर-1 पर हमारा प्रदेश आने वाला है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश से उनका बहुत नज़दीकी लगाव है, बहुत व्यक्तिगत लगाव है। वे एक-एक चीज को देखते हैं

28.03.2018/1155/जेके/डीसी/1

प्रश्न सं. 277---क्रमागत

मुख्य मंत्री महोदय.. जारी...

खासतौर से रोड़्ज़ के प्रोजैक्ट्स को खुद अपने स्तर पर मॉनिटर करने के लिए उन्होंने मैकेनिज्म डवैल्प किया है। उसमें वे चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो सड़कें स्वीकृत की हैं ये जल्दी से जल्दी बन करके तैयार हों। अध्यक्ष महोदय, हमारी भी इच्छा है कि ये सड़कें बन कर तैयार हों ताकि हमारे प्रदेश की कनैक्टिविटी बनें जिसको हम हमेशा महसूस करते हैं और हम रेलवे का इंतज़ार करते-करते थक गए है। रेलवे धीरे-धीरे

जिस गति से आ रही है अभी भी उसमें समय लगेगा। अब की बार उसमें थोड़ा पैसा स्वीकृत हुआ है । अभी हमारे पास बाई एअर कनैक्टिविटी नहीं है। नेशनल हाईवेज़ और फ़ोर लेन हमारे लिए ऐसा सपना है जिसको हिमाचल का हर आदमी साकार होता हुआ देखना चाहता है ताकि पर्यटक देश-दुनिया से हमारे हिमाचल प्रदेश में सुविधा के साथ आए, सुविधा के साथ जाए और पर्यटन इंडस्ट्री को हमारे यहां पर बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इसलिए मुकेश जी इसमें राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है और आप भी मत रखिए। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है।

श्री हर्ष वर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, this is an example of Election stunt. अच्छी बात है यदि आप इसमें काम करेंगे और पूर्ण होगा। आप जो यह कह रहे हैं कि 69 नेशनल हाई वेज़ के लिए 65 हजार करोड़ रूपया है और जो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट है उसका टोटल एक साल का बजट भी 65 हजार करोड़ रूपया नहीं होता है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को 65 हजार करोड़ रूपया नहीं मिलेगा। मेरा अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यह है कि 69 रोड़्ज़ कब बनेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। मगर ऐसा न हो कि विभाग इन सड़कों पर काम करना बन्द कर दें। इनकी जो मेंटिनैंस है उसको न बन्द कर दे। उदाहरण के तौर पर मेरा पांवटा-शिलाई-हाटकोटी नेशनल हाई वे जो बना उसमें पी0डब्ल्यू0डी0 ने मेंटिनैंस करना छोड़ दिया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। मैं, मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि ये जो 69 नेशनल हाई वे रोड़ज हैं, इनमें पी0डब्ल्यू0डी समय-समय पर मेंटिनैंस करता रहे। इसमें हो सकता है कि इन नेशनल हाई वेज़ की डी0पी0आर0 बनेगी, पैसा आएगा, टेंडर आएगा और दो-चार साल लगेंगे इसलिए इन रोड़ज़ की मेंटिनैंस समय-समय पर करते रहें। ऐसा न हो कि इन नेशनल हाईवेज़ के चक्कर में इन सड़कों की हालत खराब हो जाए। मैं, मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं।

28.03.2018/1155/जेके/डीसी/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ये गर्भ में छिपी बातें हैं। मैं कह रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और आपके देखते-देखते डिलिवरी हो जाएगी। जहां तक आपने बात कही कि जो अभी तक नेशनल हाई वेज की

इनप्रिंसिपल नोटिफिकेशन हुई है उन सड़कों के बारे में आप कह रहे हैं कि उसमें पी0डब्ल्यू0डी0 ने व प्रदेश सरकार ने सोचना ही छोड़ दिया है। वहां पर उनकी मेंटिनैंस का इशू है और उसके साथ-साथ दूसरी चीजों को भी ले करके बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं होने देंगे। जब तक काम शुरू नहीं हुआ, हमारी डी0पी0आर0 बन कर तैयार होगी, डी0पी0आर0 के बाद टेंडर होंगे और टेंडर के बाद जब तक काम शुरू नहीं हुआ तब तक के लिए वह सड़क चालू हालत में रहे। वह अच्छी कंडिशन में रहे। इस बात को हम अपनी सरकार की तरफ से और विभाग की ओर से सुनिश्चित करेंगे इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है।

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यम मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया और उसमें मैं कह सकता हूं कि इनके मूंह से पांच बार तो राजनीति ही राजनीति आई। माननीय सदस्य, विनोद जी आप चुप रहें, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ रहा हूं और आप बोल रहे हैं। मुझे बोलो तो मैं बैठ जाता हूं। अगर आपको तसल्ली नहीं होगी तो मैं क्या करूं और कैसे तसल्ली करूं। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं और आपने कहा कि पहले की सरकार ने केवल 8 केसों में डी0पी0आर0 बनाई। आपका नम्बर 51 तक पहूंच गया। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में जो पैसा डी0पी0आर0 बनाने के लिए दिया गया था, वह कितना पैसा दिया गया और कौन से महीने में दिया गया था? अब आप 51 का नम्बर बता रहे हैं।

28.03.2018/1200/SS-HK/1

प्रश्न संख्याः 277 क्रमागत

श्री राम लाल ठाकुर क्रमागतः इनमें क्या डी0पी0आर0 बन गई है? अभी जब प्रोसैस शुरू हुआ तो उसमें टाइम लगेगा। कितने केसिज़ ऐसे हैं जिनमें फॉरैस्ट कंजरवेशन ऐक्ट लागू होगा? कितने ऐसे नेशनल हाईवेज़ हैं जिनमें आपको प्राइवेट जमीन को अक्वायर करना पड़ेगा? अगर अक्वायर करेंगे तो पैसा आयेगा, इसकी एक्विजिशन प्रोसिडिंग्ज़ चलेंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि कितने केसिज़ हैं जो फॉरैस्ट कंजरवेशन ऐक्ट के अधीन आते हैं? कितने केसिज़ हैं जिनमें प्राइवेट लैंड परचेज़ होनी है। आप ये

दो-तीन चीज़ें क्लीयर कर दीजिए। राजनीति छोड़ दीजिए। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। --(व्यवधान)-- बात सुन लो। क्या डी0पी0आर0 ऐसे ही बन जायेगी? डी0पी0आर बनने का आधार क्या है? डी0पी0आर0 कैसे बनती है? जब तक फॉरैस्ट कंजरवेशन ऐक्ट में परमिशन नहीं मिलेगी तब तक सड़क क्लीयर नहीं होगी। जब तक आप लैंड अक्वायर नहीं करेंगे तब तक आप सड़क नहीं बना सकते। उसके लिए क्या प्रोसैस है, यह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाज़त से थोड़ी-सी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहता हूं। इन्होंने सारे मामले को बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि डी0पी0आर0 नहीं बनी। डी0पी0आर0 के लिए सिर्फ कंसल्टैंट एप्वाइंट किये। मैं आपको बताऊं कि केन्द्र सरकार ने कहा है कि उसमें बजट प्रोविजन 270 करोड़ रुपये का रखा है। डी0पी0आर0 तो उसके बाद बनेगी। अभी तो मैं कंसल्टैंट की बात कर रहा हूं। ये सारी जो बातें हो रही हैं --(व्यवधान)-- वही मैंने पहले भी बोला। आपने पूरी बात सुनी नहीं। आप पूरी बात सुनते नहीं है, यह समस्या है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है, जहां तक इन्होंने लैंड एक्विजिशन और एफ0सी0ए0 की बात कही है और अन्य फॉर्मैलिटीज़ की बात कही है, वह प्रोसैस उसके बाद का विषय है जब आपकी डी0पी0आर0 बन करके तैयार होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से उसमें कुछ भी नहीं है। आप पता नहीं इसमें क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। आज तक की आज़ादी के इतिहास में इतना पैसा एक साथ कभी नहीं आया। इतना बड़ा पैकेज हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं आया। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार और प्रधान मंत्री, श्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। --(व्यवधान)--

प्रश्न काल समाप्त

28.03.2018/1200/SS-HK/2

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित); और

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विधि अधिकारी, वर्ग-II(राजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-बी(3)-1/2016 दिनांक 01.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.12.2017 को प्रकाशित।

अध्यक्षः अब माननीय वन मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम के 43वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

28.03.2018/1200/SS-HK/3

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर भी रखती हूंः-

i. समिति के **269वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 91वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

ii. समिति के 71**वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 96वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

iii. समिति के **135वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 157वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है;

iv. समिति के **147वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 167वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है;

28.03.2018/1200/SS-HK/4

v. समिति के **154वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 170वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **तकनीकी शिक्षा विभाग**

से सम्बन्धित है;

vi. समिति के **152वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 196वां कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है; और

vii. समिति के **100वें मूल प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 269वां कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री नरेन्द्र बरागटाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा), जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही गतिविधियों पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं

28.03.2018/1200/SS-HK/5

<u>माननीय वन मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

अध्यक्षः अब माननीय वन मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

28.03.2018/1205/केएस/एचके/1

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन में यह वक्तव्य देना चाहता हूं कि पिछले कल ही श्री टहल सिंह, गांव भेडोंवाला, ग्राम पंचायत सेनवाला मुबारकपुर, विकासखण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर जो कि एक डोजर चालक के पद पर कार्यरत्त थे,आज प्रातःकाल ही उनका शव उनके घर के पीछे मिला है। ऐसा लगता है कि उसे जंगली जानवरों द्वारा बुरी तरह से काटा गया है और गर्दन से खून भी चूसा गया है। इसी के साथ इन्हीं दिनों एक और घटना घटित हुई है। एक अघोरी बाबा की कुटिया के पास नाहन में चीते ने हमला किया और उन्हें बूरी तरह से घायल किया है जो आज भी मैडिकल कॉलेज नाहन के अस्पताल में एडमिट है। श्री टहल सिंह जी की जो मृत्यु हुई है। वहां पर हमारे वन विभाग के डी.एफ.ओ., आर.ओ. मौके पर गए हैं और उनका पोस्टमॉर्टम हो गया है। उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है वह आ जाएगी। जो व्यक्ति नाहन मैडिकल कॉलेज में एडमिट है उनको भी विभाग द्वारा जो मदद दी जाती है, वह देंगें और साथ में वन विभाग के अधिकारियों को हमने सख्ती से दिशा-निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की कोई अन्य घटना न हो, उसको भी रोका जाए ।यह सभी के लिए हृदय विदारक है तो ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। लगता है कि चीते नरसंहार करने में लगे हैं। इसलिए इसको रोका जाना आवश्यक है। धन्यवाद

अध्यक्षः मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का यह मामला है जो कि मैंने इनके ध्यान में लाया था। यह ग्राम पंचायत सेनवाला, मुबारकपुर का मामला है।

28.03.2018/1205/केएस/एचके/2

. <u>वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान</u>

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। अब मैं मांग संख्याः 10-लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन को चर्चा एवं मतदान हेतु ले रहा हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः10- लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः मु0 33,08,06,03,000 रुपये व 12,16,28,02,000/-रुपये की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस पर सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री, अनिरुद्ध सिंह, आशा कुमारी, हर्षवर्धन चाहौन, जगत सिंह नेगी, राम लाल ठाकुर, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, नन्द लाल, डॉ0 धनीराम शांडिल, राकेश सिंघा, पवन कुमार काजल, लखविन्द्र सिंह राणा, विक्रमादित्य, आशीष बुटेल और श्री सतपाल सिंह रायजादा की ओर से आठ कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या मैं उन्हें इनकी ओर से प्रस्तुत हुआ समझूं?

माननीय सदस्यगणः अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत हुआ समझें।

28.03.2018/1205/केएस/एचके/3

अध्यक्षः कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ समझे गए जो इस प्रकार हैः

<u>मांग संख्याः 10 -लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन</u>

सदस्य का नाम	**कटौती प्रस्ताव**	**मांग संख्या**

<u>नीति का अननुमोदन</u> **10**

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन"
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए ।

1. **श्री मुकेश अग्निहोत्री,**
2. **श्री अनिरूद्ध सिंह,**
3. **श्रीमती आशा कुमारी,**
4. **श्री हर्षवर्धन चौहान,**
5. **श्री जगत सिंह नेगी,**
6. **श्री राम लाल ठाकुर,**
7. **श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु,**
8. **श्री नन्द लाल,**
9. **डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल,**
10. **श्री राकेश सिंघा,**
11. **श्री पवन कुमार काजल,**
12. **श्री लखविन्द्र सिंह राणा,**
13. **श्री विक्रमादित्य सिंह,**
14. **श्री आशीष बुटेल,**
15. **श्री सतपाल सिंह रायजादा ।**

28.03.2018/1205/केएस/एचके/4

1. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।

2. सरकार की मशीनरी तथा उपकरण क्रय एवं आबंटन की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की प्रत्येक पंचायत को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की विश्राम गृहों और परिधि गृहों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।
5. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण में कार्यरत्त मजदूरों की नीति का अननुमोदन ।

2. <u>सांकेतिक कटौती</u>

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

"लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन"

की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

<u>श्री हर्षवर्धन चौहानः</u>

1. मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप राष्ट्रीय उच्च मार्ग पावंटा-शिलाई-मिनस सड़क के कार्य में ठेकेदार द्वारा उचित सामग्री का उपयोग न कर पाने में सरकार की असफलता।
2. मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग मण्डल, शिलाई में नये जे0सी0बी0, टिप्पर, बुलडोज़र, ट्रक का प्रावधान न कर पाने में सरकार की असफलता।
3. मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप बी0 एण्ड आर0, मण्डल, शिलाई में सड़कों की मैटलिंग/टॉरिंग न कर पाने में सरकार की असफलता।

28.03.2018/1205/केएस/एचके/5

अध्यक्षः मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध है। इसमें सर्वप्रथम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, ठीक 12.00 बजे प्रश्नकाल की समाप्ति पर जो सवाल उठ रहा था, वही हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि लोक निर्माण विभाग की डिमांड है और नेशनल हाईवेज़ पर ही प्रश्न पर चर्चा चल रही थी, विभाग मुख्य मंत्री जी ने अपने पास रखा हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है।

28.3.2018/1210/av/yk/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री -------- जारी

और मुझे फिर से नेशनल हाई-वेज की बात करनी है। हमने जैसे कहा कि ये राजनैतिक हाई-वेज हैं जिनकी घोषणा एक पार्टी विशेष को सत्ता में लाने के नजरिए से की गई है। केंद्रीय मंत्री को हिमाचल बुलाकर उनसे यह अनाउंसमैंट करवाई गई और यह कहा गया कि इनके लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। यह अमूमन होता है कि कोई स्टेट हाई-वे है तो उसको नेशनल हाई-वे बनाने की बात आ जाती है जिसके लिए उसका वोल्यूम ऑफ ट्रैफिक देखा जाता है। इसके अतिरिक्त नेशनल हाई-वे के लिए 10-12 मापदण्ड हैं जिस कसौटी से उस सड़क को देखा जाता है। मगर राजनैतिक फायदा लेने के लिए इसमें गांव की सड़कें भी डलवा दी और माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। ये 4210 किलोमीटर, 65000 करोड़ रुपये का बन्दोबस्त तथा पौने पांच साल का समय; इन सारी चुनौतियों के बाद मुख्य मंत्री इन सड़कों को कैसे बनवायेंगे। यहां पर हमारे वरिष्ठ साथी राम लाल ठाकुर जी ने कहा कि लैण्ड एक्विजिशन होनी है और उसमें भी अब फैक्टर टू लगना है क्योंकि आपने इस बारे में वायदा किया हुआ है। आपने इस बारे में हर मन्च पर कहा कि हम किसान व गरीब को जमीन का ठीक रेट दिलवाएंगे। यहां से तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार धूमल जी बार-बार कहा करते थे कि जब भी लैण्ड ऐक्वायर होगी तो फैक्टर टू लगेगा। इन सड़कों को बनाने के लिए वोल्यूम ऑफ ट्रैफिक के अलावा फोरैस्ट कनज़र्वेशन ऐक्ट देखना पड़ेगा कि कितनी सड़कों पर लग रहा है। इसके अतिरिक्त लैण्ड एक्विजिशन पर कितना खर्च आयेगा; यह भी देखना पड़ेगा। मुख्य मंत्री जी ने अभी तक तो यह स्पष्ट कर दिया है कि मामला कनसल्टैंसी पर लटका हुआ है और उससे आगे नहीं बढ़ा है। इन्होंने कहा है कि कनसल्टैंसी का कार्य 31 मार्च तक पूरा करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह हो जायेगा क्योंकि अभी मंत्री जी कह रहे थे कि आफिसर

हमारी गति से भी तेज दौड़ेंगे। आप इस कनसल्टैंसी के लिए अपने आफिसरों को किस गति से दौड़ायेंगे क्योंकि अब 31 मार्च को केवल 2-3 दिन का समय बचा है। उसके बाद आप डी0पी0आर0 बनायेंगे और फिर टैंडर करेंगे। उसके पश्चात

28.3.2018/1210/av/yk/2

आप यह कहना शुरू कर देंगे कि टैंडर करना हमारा काम नहीं है यह तो दिल्ली से होने हैं। हम तो चाहेंगे जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि विभाग इसीलिए रखा है कि पांच साल के अंदर यह 4210 किलोमीटर सड़क की लैंथ बनेगी और 65000 करोड़ रुपये की राशि आयेगी। यहां पर जैसे हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि यह भी पता कर लेना कि केन्द्रीय मन्त्रालय का इतना बजट है या नहीं है। अभी मैं साउथ गया था और केंद्रीय मंत्री जी ने वहां पर भी इसी प्रकार से हजारों करोड़ रुपये की 40-50 सड़कें अनाउंस कर दी हैं। मंत्री जी ने पूरे हिन्दुस्तान में एक ही फार्मुला लगाया हुआ है कि जो नेशनल हाई-वे 25-50 साल में बनेंगे उनकी घोषणा कर दो। उनकी घोषणा करने या उनको नोटिफाई करने में क्या जाता है। यहां पर जैसे हमारे साथी सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने कहा कि इन नेशनल हाई-वेज की न तो नम्बरिंग हुई हैं और न ही इनका कोई नाम अंकित किया गया है।

28.03.2018/1215/TCV/YK-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री..... जारी

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी जवाब में कहा है कि अभी तक 3 नेशनल हाईवे बने हैं। अफसरशाही यह कहती है कि 4 स्टेट हाईवे ऐसे तैयार है, जो नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड के हैं। अगर आप उन 4 स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवा लो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि वे 4 स्टेट हाईवे उस स्टैंडर्ड के बने हुए हैं और आप उनको घोषित करवा सकते हैं। कल भी माननीय मंत्री जी ने 4200 और 3500 करोड़ रुपये जिक्र किया था। माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणायें करनी आसान होती है। लेकिन जब इनका जवाब

देने का समय आएगा, ज़रा इसका भी मूल्यांकन कर लेना क्योंकि आपको ही इस 65 हजार करोड़ रुपये का जवाब देना है। ये मसला अभी तक कंसल्टैंसी पर है और 270 करोड़ रुपये की कुल राशि का यहां पर उल्लेख किया गया है। क्योंकि लैंड एक्वाज़िशन करना एक बहुत बड़ा मसला है। आपने कई विधायकों को कहा कि कौन-कौन-सी सड़कें इन परियोजनाओं में डाली जा सकती है? उसने ऐसी सड़क बता दी, जो उसके गांव की सड़कें हैं। कई जगह तो गांव की सड़कें भी नहीं हैं। इस बात से अधिकारी भी परेशान है कि ये क्या किया गया है? जो सड़कें हमने कभी देखी ही नहीं ,जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, वे नेशनल हाईवे की सूचियों में डाल दी गईं। सड़कों के लिए कोई पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सही मायने में ये जुमला है। जोकि इस प्रदेश में बिना पैरामीटर्ज के घोषित कर दिया गया है और ये चुनावी सैंक्शन हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली की सरकार के 10 महीने रह गये हैं। मेरा आपसे यह आग्रह है कि अगर कुछ लाया जा सकता है, तो जा करके ले आओ। ये भी जुलाई-अगस्त तक ही मिलेगा। उसके बाद तो दिल्ली के ऑफिसर भी नहीं सुनेंगे। इसलिए अगर इन सड़कों के लिए कुछ ला सकते हो तो ले आओ। आपने राजनीतिक कारणों से और खासतौर पर सांसदों को रिलीफ़ देने के लिए ये चुनावी मैप बनाया था। क्योंकि सांसद सारी जगह जाकर कह रहे थे कि

28.03.2018/1215/TCV/YK-2

कोई सड़क तो नहीं डलवानी है। 65 हजार करोड़ रुपये की घोषणा हो चुकी है, अभी भी सांसद केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के पास जाकर फोटो खींचवा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक सड़क की और सैंक्शन आ गई है। ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है। ये तो कह रहे है कि आपने प्राइमरी हैल्थ सैंटर खोल दिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि ऐसी जगह प्राइमरी हैल्थ सैंटर खोल दिया जो कागज़ों में था ही न

28-03-2018/1220/NS/AG/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री -----जारी।

अध्यक्ष महोदय, गांव में जहां पर स्कूटर नहीं जा सकता है, वहां पर सरकार नेशनल हाईवे बनाने जा रही है। पता लग जायेगा। ---(व्यवधान)--- इस सूची में ऐसी-ऐसी सड़कें शामिल की गई हैं। ---(व्यवधान)--- ये कोरी घोषणायें हैं। अगर आप (सत्ता पक्ष) ज्यादा बोलेंगे तो हम आपको डेप्यूटेशन पर इस तरफ (विपक्ष) ले आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे का जो मसला है, इन सड़कों के बारे में बहुत मंथन करने की जरूरत है। दूसरा, ये सड़कें वर्ल्ड बैंक की हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, पी0डब्ल्यू0डी0 की डिमांड पर चर्चा हो रही है। यह may be done और to be done बाद में कर लेना। यह लगातार सारी सरकारों को खज्ज़ल करते हैं। आपकी डिमांड पर चर्चा हो रही है और पांच सालों तक may be done ही चलना है। ये सड़कें वर्ल्ड बैंक की हैं। ---(व्यवधान)--- आपका स्वागत है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने वर्ल्ड बैंक का पहला पैकेज़ लगभग 1350 करोड़ रुपये का बनवाया था। उसके बाद हमारी सरकार चली गई थी और उस पैसे को लगाने में इतना समय लगा। विशेष रूप से रोहडू-हाटकोटी सड़क पर कितना बवंडर मचा रहा, कई बार राजनीतिक कारण भी रहे और ये मामला कभी अदालतों में जा रहा था तथा कभी सरकार मोनीटर कर रही थी। दूसरा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक-II का है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने फिर से प्रोजेक्ट तैयार करवा दिया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसको समयबद्ध तरीके से इम्पलीमैंट करवायें ताकि समयबद्ध तरीके से इसकी सैंक्शन हो और ये पैसा आ जाये।

अध्यक्ष महोदय, इससे भी महत्वपूर्ण मसला टनल्ज़ का है। इस माननीय सदन में 7-8 टनल्ज़ बनाने की बातें लगातार होती रही हैं। इस बार बज़ट में सिर्फ एक टनल की बात की गई है। एक किलोमीटर की एक टनल बनाने के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि खर्च होती है। एक-एक टनल लगभग चार या पांच हजार करोड़ रुपये की राशि से बनती है। हमारे मंत्री जी यहां से चले गये हैं। ये भी एक टनल का शोर मचाते हैं कि पांच हजार करोड़ रुपये की सुरंग बंगाणा से हमीरपुर या जाहू को बनानी है। मैं

आपसे जानना चाहता हूं कि इन सुरगों को ले करके आपकी क्या नीति है? क्या आप इन सुरंगों को आगे परस्यू करेंगे? क्योंकि ये सुरंगें चार या पांच हजार करोड़ रुपये की हैं। पहले कहा जाता था कि इनको हम बी0ओ0टी0 पर बनवायेंगे। इसके लिए कोई नहीं

28-03-2018/1220/NS/AG/2

आया, पता नहीं इन्होंने कितनी बार टैंडर कर दिये होंगे? क्योंकि लोगों को पता है कि ये वायबल नहीं है। इस पर कितनी चर्चा होती रही है और क्या स्थिति थी? लेकिन इतना जरूर है कि विभाग के ही लोगों को मानना है कि टनल्ज़ बनाना संभव नहीं है और बी0ओ0टी0 पर कोई आने वाला नहीं है। इन्होंने यहां पर लगभग 600 करोड़ रुपये की एक सुरंग की बात की है और कहा है कि इसके लिए हम केंद्र सरकार से पैसा ले करके आयेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री महोदय को इस सुरंग को बनाने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये की राशि का आश्वासन केंद्र से मिला है? इन्होंने जलौड़ी दर्रे के नीचे सैंज-लूहरी-औट मार्ग पर एक सुरंग बनाने के लिए कहा है और इसकी लम्बाई लगभग 4.2 किलोमीटर रखी गई है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सड़कों की टारिंग के लिए इस बज़ट में बहुत कम पैसा रखा गया है। इन्होंने इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि रखी है जोकि कम है। सड़कों की हालत खराब है। मुझे मालूम है, माननीय मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि हम तो तीन महीने से आये हैं, सड़कों की हालत तो पहले से ही खराब है। यह आपका तकिया कलाम हो गया है और आपने फिक्स कर दिया है कि आपको ऐसा बोलना ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रदेश की सड़कों की स्थिति सुधरे और इसमें गुणात्मक परिवर्तन आये। आपने यहां पर ब्लैक स्पोट्स की बात भी की है। अगर ये ठीक हो पायें और दुर्घटनायें कम हों। इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। मुख्य मंत्री महोदय, निश्चित तौर पर हमें बतायें कि जो नेशनल हाइवेज़ हैं

28.03.2018/1225/RKS/AG-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री...जारी

उनके रख-रखाव या मरम्मत के लिए कितना पैसा प्रदेश के पास आया है? हमें यह

बताया गया कि इन सड़कों की मरम्मत के लिए कम पैसा आ रहा है। दूसरा, पीछे एक ही सड़क के लिए 250-300 करोड़ रुपये दे दिया गया, जोकि सारे प्रदेश में बंटना था। वह पैसा एक ही सड़क में चला गया। मेरे कहना यह है कि पूरे प्रदेश में बांट कर पैसा आए ताकि सड़कों की रख-रखाव ठीक तरीके से हो। इसके अलावा जो नाबार्ड के तहत सड़कें दी गई हैं, उनकी टाइम बाउंड डी.पी.आर्ज. बनाई जाए। यह बहुत जरूरी है कि टाइम बाउंड डी.पी.आर्ज. बनें। सत्तापक्ष वाले तो प्रैशर बनवाकर अपनी डी.पी.आर्ज. बनवा लेंगे। लेकिन मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप संबंधित विभाग के एस.सी., एक्सिअन को डायरैक्शन्ज दें, क्योंकि ऑपोजीशन के एम.एल.एज. भी इलैक्टिड एम.एल.एज. हैं और उनके पास भी विभाग के XENs जाएं ताकि उनकी सड़कों की डी.पी.आर्ज. भी टाइम बाउंड बन सके। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि डी.पी.आर्ज को आउटसोर्स किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो 90 करोड़ रुपये की सीलिंग्स है, यह इस विधान सभा के 5 वर्ष के लिए लगाई जाए। जो विधायक इस विधान सभा में इस वर्ष आए हैं, उनको 5 वर्ष में 90 करोड़ रुपये मिले। सत्तापक्ष के भी 23 विधायक नये आए हैं और आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। (...व्यवधान...) कोई निर्वाचन क्षेत्र 70 करोड़ रुपये पर खड़ा है, कोई 80 करोड़ रुपये पर खड़ा है। (...व्यवधान...) फिर नये विधायक को चुनकर आने का क्या फायदा है? अगर आपने इसे वर्ष 2011 से चलाना है तो उनके खाते में पहले ही 70 करोड़ रुपये पड़ा है। फिर उन विधायकों को क्या मिला? इन पांच साल में 90 करोड़ रुपये की सीलिंग लगाओ। कुछ नये बने हैं तो नई शुरूआत करो। यह हमारा आपसे आग्रह है।

28.03.2018/1225/RKS/AG-2

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सड़कों के लिए 4082 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की बात कही है। हम यही कहना चाहते हैं कि प्रदेश की सड़कें, पुल व

टनल ठीक से बनें परन्तु इनके लिए आपने बजट में कोई सही सोच रिफ्लैक्ट नहीं की है। आपने इसमें कोई दिशा-दशा रिफ्लैक्ट नहीं की है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः10- लोक निर्माण -सड़क, पुल एवं भवन, कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सड़कें न केवल टूरिज्म व इंडस्ट्रीज़ के लिए ही महत्वपूर्ण है बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर्ज के लिए भी यह एक अहम कड़ी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की भौगौलिक स्थिति या मौसम को देखें तो हमारे नॉर्म्स इतने तैयार नहीं है कि वे स्टैंड कर सके। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। एक तो यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि पेवर से ही मैटलिंग हो ताकि काम में गुणवत्ता आए। 1-1 किलोमीटर या डेढ़-डेढ़ किलोमीटर के टैंडर न हो। कलस्टर टैंडर लगाए जाएं। पेवर से ही मैटलिंग अनिवार्य की जाए ताकि प्लांट से ही मिक्सिंग हो और सही ढंग के तापमान में मटीरीअल तैयार हो ताकि सही तरीके से मैटलिंग हो सके। जो अभी AMP में थिकनैस फिक्स की गई है वह 22 MM की की गई है। दो साल पहले शिमला शहर की सड़कें काफी खराब थी।

28.03.2018/1230/बी0एस0/डी0सी0-1

श्री अनिरूद्ध सिंह.....जारी

मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी का इन्होंने जो तारकोल और बजरी पड़ती है उसकी थिकनेस बढ़ाई और आज आप देख रहें हैं कि जो PWD या जो हमारे शिमला नगर निगम की सड़के हैं उनमें दो साल से एक गड्ढा तक नहीं पड़ा है। उस समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मेरे कहने का मतलब है कि यह

एक मॉडल है, इसे पूरे प्रदेश में अपनाया जाना चाहए। क्लस्टर टैंडर लगाए जाएं और सब डीविजन के हिसाब से क्लस्टर टैंडर लगने चाहिए, जैसे शिमला नगर निगम में शुरू हुआ था। इससे गुणवत्ता काफी अच्छी हो गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने डीविजन न0-1 शिमला के लिए बोला था, कृपया उसे भी रीलीज करने की कृपा करें। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग को आधुनिक करने की जरूरत है । अभी पुरानी मशीनें है पुराने टिप्पर हैं, मशीनरी के ऊपर भी कृपया ध्यान रखें। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि रिज बजन के कारण किसी भी दिन गिर जाएगा, इसका वेट बढ़ रहा है, वेट इसलिए बढ़ रहा है कि डेढ़ से दो फुट तक कॉंकरीट, तारकोट के साथ रोड़ी उसमें बिछी हुई है। जब तक हम उसको उखाड़ेंगे ही नहीं तब तक वह वेट कम नहीं हो सकता। ऐसा ही हम दुकानों को अगर देखें तो वहां भी कॉंकरीट की थिकनेस बढ़ती जा रही है। दुकानों के शट्टर तक यह पहुंच गई है। मैं समझता हूं कि पूरे सर्कुलर रोड में और अन्य स्थानों में भी इसको निकाल कर इसे दोबारा से जो प्रोसेस है उसे शुरू करें। इस कार्य के लिए कोई-न-कोई कदम उठाए जाएं। लोक निर्माण विभाग को हाईड्रॉलिक रोड़ रोलर्स मुहैया करवाए जाएं। सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि हम किसी भी चुनाव क्षेत्र की बात करें तो लोक निर्माण विभाग के पास लेबर ही नहीं है। ठेकेदारों के ऊपर ही निर्भर हैं। अगर सरकार लेबर कान्ट्रैक्ट पर नहीं रख सकती है तो उसको आउट सोर्सिज के जरिए जैसा आई.पी.एच. विभाग में कार्य चलाने के लिए एक व्यक्ति को ठेका दिया हुआ है

28.03.2018/1230/बी0एस0/डी0सी0-2

25-26 आदमियों में लिए, इस तरह से कोई कदम उठाएं। यह मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कदम रहेगा। ठेकेदार के द्वारा लेबर हर सब डीविजन और डीविजन में रखी जाए ताकि सफाई की ठीक व्यवस्था भी हो सके। माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारे चुनाव क्षेत्रों में 25-50 किलोमीटर तक ऐसी सड़कें हैं जो लोक निर्माण विभाग के अंडर नहीं है। कोई

ऐसी पॉलिसी हम बनाएं जो गांव की सड़के ब्लॉक के द्वारा बनाई गई हैं उसके लिए आप चुनाव क्षेत्र वाईज बजट प्रदान करें और लोक निर्माण विभाग उस कार्य को करवाए। क्योंकि लोक निर्माण विभाग कहता है कि यह सड़क ही हमारे नाम नहीं है या इसके लिए बजट चाहिए तब हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि उन्हें बजट का प्रावधान करकें क्लस्टर टेंडर लगवाएं जाएं तो यह एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुलों की बात करना चाहूंगा, पुल हमारे क्षेत्रों को जोड़ने की अहम भूमिका निभाते हैं न केवल राज्यों को बल्कि हमारे जिलों को भी ये जोड़ते हैं । मैं राजा साहब को धन्यवाद करना चाहूंगा इन्होंने हमारा संतोख पंचायत में एक कौंती पुल था, उसे रिर्काड समय में मात्र डेढ़ साल में उसे बनाया गया। पहले वह सिंगल लेन था अब उसे डबल लेन कर दिया गया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में दो पुल हैं एक लखोटी पुल है जो ग्राम पंचायत बनोग में है जो सिरमौर को जोड़ता है और जुग्गर पुल जो कटियार और मंझार गांव को जोड़ता है । ये भी सिरमौर के साथ है केलव दो किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। ये दोनो ही विधायक प्राथमिकता में डालें हैं। एक का तो माननीय धूमल साहब ने काफी समय पहले शिलान्यास किया था। इन पुलों का जल्दी से जल्दी सर्वे करव कर इस कार्य को करने की कृपा करें। एक और पुल जो नार्बाड से पास हो चुका है, नोटी खड्ड के ऊपर ग्राम पंचायत गुम्मा में जाब्बल पुल के नाम से है। उसके टेंडर हैडक्वाटर से विभाग ने लगाने हैं। मैं चाहता हूं कि यह टेंडर भी जल्दी -से- जल्दी लगवाया जाए। अभी यहां पर एन.एच. की भी बात हुई। एन.एच. में बोलना चाहूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो 31 की लिस्ट है उसमें क्रम संख्या- 17 पर 23 पर और 30 पर कसुम्पट्टी चुनाव क्षेत्र से होकर एन.एच. जा रहे हैं। अगर यह बनने हैं अभी तो कागजों में ही है। मैं चाहूंगा कि इस पर जल्दी कार्य शुरू किया जाए।

28.3.2018/1235/DT/DC/1-

श्री अनिरूद्व सिंह द्वारा जारी

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूगा कि जब एन0एच0 अनाउन्स हुए थे उस समय भी अखबारो में यह बडा-बडा लिख कर आया था कि ये

सिरमौर से जुड रहा है और वाया लखोटी-बलोग-जनेडघाट-छलांडा और वहां से आगे मेहली आयेगा। मैं समझता हूं इसको लखोटी से जोड़ना चाहिए न कि छलांडा से ताकि ज़िला सिरमौर भी इससे जुड पाए। एन0 एच0 के सम्बन्ध में एक-दो बाते मै बोलना चाहूंगा। यह आच्छी बात है नैशनल प्रोजेक्ट आ रहे है और एन0एच0 रोड बन रहे है। एक बहुत गम्भीर समस्या जो हम लोगो को उत्पन हो रही है वह यह है कि एम0ओ0यू0 साईन होने के बाद जो लिंक रोड राज्य सरकार ने प्रोवाईड करवाने है और पी0एम0जी0एस0ई0 की रोडज़ उन्हें असेस करने के लिए दि गई है। जो ऑलरेडी मैटिलींग के टेण्डर लगे हैं उनका काम रूका दिया गया है जिस कारण लोग धूल खाने के लिए मजबूर हैं। वैसे एन0एच0 का काम चार साल में कंप्लीट होता हैं लेकिन अभी तो केवल पुल ही बन रहे है। जो वाकनाघाट से शिमला तक का हमारा एन0एच0 अनाउन्स हुआ है उसमें अभी पुलों का ही टेन्डर हुआ, रोड का टेन्डर नहीं हुआ है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, से यह भी अनुरोध है कि मैहली से गुसाण तक पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत जो ऑलरेडी टेन्डरड रोडज़ है और जिन रोडज़ का 90 प्रतिशत काम पूर्ण भी हो चुका है, केवल मटिलिग का कार्य ही शेष है, उस कार्य को तो कम से कम पूर्ण करवा दें ताकि लोगों को उस रास्तें में धूल न खानी पड़े। इसके साथ ही मैं नाबार्ड की कुछ स्कीमों के बारे मे भी बात करना चाहूंगा। यहां पर डी0पी0आएज़ की यह बात हुई। क्योकि डी0पी0आएज़ बनने में काफी समय लगता है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा ही समय है, इसलिए मैं समझता हूं कि हमें बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृप्या आप बैठिए। यह आप ही का समय और यह समय सत्ता पक्ष को नहीं दिया जा रहा। इस समय 18 अन्य माननीय सदस्यों को बोलना है अगर आप चाहें तो कल तक भी इसे चला सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। परन्तु आप की जो समिति है या फिर लीडर है उनसे चर्चा करने के बाद पांच मिनट का समय निर्धारित किया है। अगर आपको साढे सात मिनट बोलने के बाद भी यह लगता है कि मुझे और बोलना है तो आप डिसाईड करके मुझे बता दें।

28.3.2018/1235/DT/DC/2-

श्री अनिरूद्व सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से दो मिनट नाबार्ड के सम्बन्ध में और बोलना चाहूंगा। नाबार्ड में एक समस्या सभी को फेश करनी पड़ रही है और वह यह है कि हम लोग MLA प्रायोरटीज में अपनी स्कीम डालते हैं उसके बाद उसका सर्वे होता है फिर गिफट डीड होती है। प्रायोरटीज़ में डालने के बाद भी दो-दो तीन-तीन साल गिफट डीड नहीं होती। मेरा आपसे अनुरोध कि इसे मेन्डेटरी भी किया जाये कि पहले रोड के सम्बन्ध में विधायक साधारण पत्र लोक निर्माण विभाग को दे और लोक निर्माण विभाग उस पर सर्वे करेा जहां तक गिफट डीड की बात है यह विधायक या सम्बन्धित पंचायत का काम है। इसके बाद ही विधायक प्राथमिकता में इस स्कीम को डाला जाए क्योंकि गिफट डीड के बाद ही डी0पी0आरज़ या फारेस्ट केस बनने शुरू होते हैं। पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सर्वे समय में किया जाना चाहिए। मै अन्त में टन्नल के बारे बात करना चाहूंगा। मै समझता हूं की आज समय की अधिक किल्लत है। हम सड़कों के मोड़ों को घूम कर जो हम पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर का सफर तय करते है, अगर टन्नल बनेगी तो मै समझता हूं कि समय भी बचेगा और तेल भी बचेगा इसके साथ-साथ ट्रेफिक की समस्या भी हल होगी। शिमला शहर की दो प्रस्तावित टन्नलज़, एक टन्नल लक्कड़ बाज़ार से लिफट की और है और दूसरी स्नोडन से स्टोक पैलेस के पास बननी है। मेरे ख्याल से एक बार उसकी डी0पी0आर0 भी तैयार की गई थी। यहटन्नलज़ बी0ओ0टी0 मोड में बननी सम्भव नहीं है, मै समझता हूं कि अगर माननीय मुख्यमन्त्री महोदय और सरकार इसमें पहल करे और इन् टन्नलज़ को बनाने के लिए कदम उठाये तो यह शिमला शहर के लिए एक बहुत बड़ी शौगात होगी । अध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.3.2018/1235/DT/DC/3

अध्यक्षः अब माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 10, लोक निर्माण, सड़क पुल एवं भवन के कसौट प्रस्ताव में आपने बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद।

28.03.2018/1240/SLS-HK-1

श्रीमती आशा कुमारी....जारी

वैसे तो अध्यक्ष महोदय, आज का प्रश्न काल भी लोक निर्माण विभाग के लिए ही समर्पित रहा। जैसा मुकेश जी ने कहा, यह वह सड़कें हैं जो काल्पनिक, सपने में बनने वाली, जिनको सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिली है। सुबह से 4210 किलोमीटर लैंथ की नैशनल हाईवेज का ज़िक्र हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस बात को ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहती क्योंकि अग्निहोत्री जी और अन्य सदस्यों ने जो कहा वह सब सच्चाई है। यह भी सच्चाई है कि यह जो 4210 किलोमीटर की बात आप कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि 10 किलोमीटर सड़क बनाने में ही 5-5 साल लग जाते हैं। ...(व्यवधान)... लगते हैं क्योंकि पहले आप उसकी लैंड अक्वायर करते हैं, फिर आप उसका मुआवजा दोगे, फिर उसकी फोरैस्ट क्लीयरैंस लोगे, फिर कहीं जाकर, जैसे कि अनिरूद्ध जी ने कहा कि अगर किसी की लोकल लैंड हुई तो उसकी गिफ्ट डीड होगी। यह सब करते-करते, उस सड़क की मैटलिंग-टारिंग करते-करते 5 साल लग जाते हैं। यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।

जहां तक नैशनल हाईवेज का सवाल है, प्रदेश में जो नैशनल हाईवेज बन रहे हैं। आज से नहीं बल्कि वर्षों से बन रहे हैं। जैसे एक नैशनल हाईवे, जिसमें बिक्रम जी आप और मैं शायद रोज़ ही आते होंगे, वह कितने सालों से बन रहा है? बन रहा है, किसी ने उसका काम रोका नहीं मगर जो हालत उस नैशनल हाईवे की हमीरपुर, बिलासपुर से लेकर आगे तक है, वह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन सही है कि उसमें समय लगता है। यह नहीं कि उस पर काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है और बड़े ज़ोर-शोर से हो रहा है।

इसमें एक हमारे चम्बा में माननीय सदस्य जरयाल जी के इलाके से होते हुए चम्बा होते हुए, तीसा होते हुए किलाड़ जाने वाला बहुत महत्वकांक्षी नैशनल हाईवे है।

जब यह उस स्टैंडर्ड का नैशनल हाईवे बनेगा तो जो भी इसे बनाएगा, इसके लिए वह बधाई का पात्र होगा। मगर एक नैशनल हाईवे, जो कि पहले से ही स्वीकृति है, जो कि पठानकोट से बनीखेत होते हुए, चम्बा होते हुए भरमौर जा रहा है, जब

28.03.2018/1240/SLS-HK-2

माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो हमने इनसे निवेदन किया कि यह नैशनल हाईवे डिक्लेयर भी हो गया और डिविजन को हैंड ओवर भी हो गया है, इसलिए इसका रख-रखाव और काम कैसे किया जाएगा, क्योंकि नैशनल हाईवे के लिए जो नैशनल हाईवे स्टैंडड्र्ज हैं, उसके लिए तो अभी लैंड एक्युजीशन तक नहीं हुई है। मैं उस नैशनल हाईवे की बात कर रही हूं जो पहले से स्वीकृत है। यह काम इन पिछले 3 सालों में नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उसको स्वीकृत हुए 5 साल या 4 साल तो हो ही गए हैं, मगर अभी तक उसकी लैंड अक्वायर नहीं हुई है अक्सैप्ट कि जो उसकी एग्जिस्टिंग विडथ है, उसके ऊपर हमारी सरकार के वक्त, जो नैशनल हाईवे पूल होता है, उसमें से पैसा दिया गया और चम्बा तक के टैंडर लगे हुए हैं और काम भी लगा हुआ है। बनीखेत तक उसमें पूरा काम हो भी गया है। मगर जो नैशनल हाईवे विडथ है, उसकी तो आपने अभी तक एक्युजीशन भी शुरू नहीं की है। फिर ये सभी काल्पनिक, सैद्धांतिक न जाने सब क्या-क्या हैं? ...(व्यवधान)... ये तो सपनों के महल भी नहीं हैं। ये सपनों के महल को जाने वाले रास्ते हैं। ये कब बनेंगे, सही में बनेंगे भी या नहीं या वाक़ई जैसे मुकेश जी ने कहा, ये एक राजनीतिक स्टंट था। अगर आप पूरे भारत में पता करेंगे कि ऐसी कितनी सैद्धांतिक स्वीकृतियां मिली हैं तो 65000 करोड़ नहीं बल्कि हिंदुस्तान का अगले 10 साल का बजट भी उनको पूरा करने के लिए काफी नहीं होगा।

नेशनल हाईवेज की चर्चा बहुत हो गई है। इस पर ज्यादा बात करना, मुझे नहीं लगता कि और ज़रूरी है। मगर चुनाव क्षेत्र और जिले कि अगर हम बात करें तो अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा दिक्कत फोरैस्ट क्लीयरैंसिज की आ रही है। फोरैस्ट क्लीयरैंसिज हो भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही हैं। विभाग केसिज तैयार कर रहा है। मगर मैं एक पर्टिकुलर सड़क का आपसे ज़िक्र करना चाहती

हूं। जम्मु बाऊंडरी, जिसकी सुबह आप चर्चा कर रहे थे, जहां से बकरवाल चोरी करने के लिए आते हैं, उसी बाऊंडरी से भदरवाह की तरफ से एक सड़क आ रही है या उस ओर जा रही है लेकिन वह बहुत पुरानी सड़क है। उसको हम लंगेरा बाऊंडरी की सड़क बोलते हैं। कोटी-सुंडला-लंगेरा बाऊंडरी की यह रोड है। यह सैंट्रल रोड फंड से बन रही है।

28/03/2018/1245/RG/HK/1

श्रीमती आशा कुमारी-----जारी

मैं तत्कालीन केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री जी जो श्री गडकरी से पहले थे, उनकी धन्यवादी हूं कि उन्होंने उसकी स्वीकृति दी थी। उसका काम लगा हुआ है। मगर जो उसका शुरूआती एरिया है वह वाइल्ड लाईफ सैंक्चुरी के अन्तर्गत आता है और लैण्ड बहुत साल पहले, already it stands to transfer to PWD. इसमें मेरा, आपका या हममें से किसी का कोई योगदान नहीं है। वह बहुत पुरानी लोक निर्माण विभाग की ट्रांसफर्ड लैण्ड है। जहां भी वाइल्ड लाईफ सैंक्चुरी होती है अगर पेड़ों को काटने की स्वीकृति लेनी हो, तो वाइल्ड लाईफ बोर्ड में जाना पड़ता है। मैं उस समय के मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की धन्यवादी हूं कि इनके समय में लोक निर्माण ने अपना केस वाइल्ड लाईफ बोर्ड को भेजा। वहां से स्वीकृति हो गई और उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं, इन्यूमरेशन हो गई, जंगलात विभाग के सारा पत्राचार कर दिया गया, मगर वाइल्ड लाईफ डिवीजन, चंबा आगे उसके फेलिंग के ऑर्डर ही नहीं कर रहा है, तो सड़क कैसे बनेगी? करोड़ों रुपयों की धनराशि इस सड़क के लिए आई हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के मामले जहां इन्यूमरेशन हो गई है, जहां लोक निर्माण विभाग ने एन.पी.ए. का पैसा जमा कर दिया है या जहां औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं, ऐसी सड़कें जो वन विभाग के फेलिंग ऑर्डर न करने के कारण रुकी हुई हैं, आप इनको प्राथमिकता के तौर पर आदेश दें, because it is only a question of coordinating between the two departments. एक विभाग ने काम भी कर दिया और दूसरा विभाग फैलिंग के ऑर्डर नहीं कर रहा है। ---(घण्टी)----

अध्यक्ष महोदय, बाकी डिवीजन्ज का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन चंबा फॉरेस्ट सर्कल ने एक तिथि निर्धारित की हुई है कि उसी दिन फैलिंग के ऑर्डर्ज करते हैं। तो

ऐसा नहीं होना चाहिए। जब-जब लोक निर्माण विभाग के केस इन-ऑडर जाते हैं, पैसा जमा हो गया है, तो फैलिंग हो जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यहां मशीनरी की बात जरूर करना चाहूंगी। हमारा स्नो-बॉउन्ड एरिया है। कई बार मैं यहां इस बात की चर्चा कर चुकी हूं कि पुरानी मशीनरी को बदलने की जरूरत है। विशेषकर सलूणी मण्डल के लिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा, डलहौजी मण्डल के लिए तो मैं पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करती हूं कि वहां इन्होंने एक रोबो जो बर्फ हटाने के लिए काम आता है, वह दिया। क्योंकि स्नो कटर बहुत महंगा होता है और उसका रख-रखाव

28/03/2018/1245/RG/HK/2

भी बहुत महंगा होता है। लेकिन छोटा रोबो बर्फ हटाने के लिए बहुत प्रभावी होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सलूणी मण्डल के लिए आप एक छोटा रोबो उपलब्ध करवाएं। इसी प्रकार से जो वहां की पुरानी मशीनरी है, उसको बदलवाएं। पुरानी मशीनरी अपनी यूटीलिटी लाईफ को खत्म कर चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे प्रदेश में भवन हैं जिनका रख-रखाव लोक निर्माण विभाग करता है, वे चाहे किसी भी विभाग के भवन हों, उनका रख-रखाव लोक निर्माण विभाग ही करता है। उसके लिए आपको पर्याप्त धनराशि देनी चाहिए। क्योंकि सरकारी भवनों की दशा दुर्दशा में बदलती जा रही है। वे बने हुए भवन हैं और आपने उन पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए हुए हैं। लेकिन छोटा सा काम या उनकी मरम्मत न होने के कारण उन भवनों की हालत खराब हो जाती है। इसी तरह से विश्राम गृह या परिधि गृह हैं। इनके रख-रखाव के लिए पर्याप्त धन आप उपलब्ध करवाएं।

अध्यक्ष महोदय, एक 'मुख्य मंत्री सड़क योजना' है। वैसे तो बजट में आपने इसका जिक्र किया और इसमें 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं, लेकिन पिछले सालों से राजा वीरभद्र सिंह जी के समय से यह योजना चल रही है। इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि हर निर्वाचन क्षेत्र को जितना इसका शेयर बनता है, वह दें। क्योंकि यह छोटी सड़कें

बनाने के काम जरूर आएगा।

अध्यक्ष महोदय, , मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव है जो जनजातीय क्षेत्र में तो नहीं हैं क्योंकि जनजातीय क्षेत्र पांगी एवं भरमौर ही है, लेकिन वहां की 60% जनसंख्या ट्रायबल है। वहां के लिए सड़कें ट्रायबल सब प्लान से बनी हैं। अब इस बजट में यह क्लीयरिटी नहीं है कि जो टी.ए.एस.पी. के बजट से सड़कें बनी थीं उनकी फण्डिंग अब कौन करेगा?

28.03.2018/1250/जेके/वाईके/1

श्रीमती आशा कुमारीः------जारी--------

क्योंकि पहले वह ट्राइबल सब प्लान में अपीयर होती थी, अब वह पी0डब्ल्यू0डी0 में अपीयर हुई है तो उन सड़कों की फंडिंग कौन करेगा? क्योंकि वे ट्राइबल सब प्लान की थी, उसका कौन सा हैड होगा? अच्छी सड़कें गांव की हो, यह आपके जो तय मापदण्ड है उनको पूरा करती है। कुछ-कुछ गांव तो हमारे ऐसे हैं जिनमें 90 या 100 परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है। मेरे एरिया और भटियात में जरियाल जी के एरिया में ट्राइबल सब प्लान से हमारी सड़कें बनी हुई है ।उनका कोई न कोई आपको प्रावधान करना पड़ेगा ताकि हमारी ये जो सड़कें अब कम्पलिशन में हैं, उनकी कटिंग हो गई है, टारिंग होनी है इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यह जो ट्राइबल सब प्लान की नॉन ट्राइबल एरिया की सड़कें हैं, इनके लिए भी आप कोई फंड इयरमार्क करवाएं। मुझे उम्मीद है कि आपका सड़कों का कार्यक्रम, क्योंकि हमारे एरिया की सड़कें दूर-दराज़ की सड़कें हैं, बर्फ पड़ने से डैमेज होती हैं तो उनमें मेंटिनैंस का फंड आप बढ़ाएंगे। खास करके जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जैसे सलूणी, तीसा और मैला, ये चम्बा के हमारे इलाके हैं। ये बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं। यहां के लिए आप मेंटिनैंस का फंड बढ़ाएंगें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2018/1250/जेके/वाईके/2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री हर्ष वर्धन चौहान।

श्री हर्ष वर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः10- लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन पर मैं चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे कि कहते हैं सड़कें जीवन रेखाएं हैं और हिमाचल प्रदेश सड़कों के मामले में बहुत विकास भी हुआ है। आज सबसे बड़ी जरूरत सड़कों की इम्प्रूवमैंट की है, सुधार की है और quality of construction को इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। हम जब भी बॉर्डर एरिया से एन्टर करते हैं, उत्तराखंड है, हरियाणा है, चाहे पंजाब है, जब हम एन्टर करके अपने प्रदेश में आते हैं तो एकदम से हम सड़कों में चेंज देखते हैं कि दूसरे राज्यों की जो सड़कें हैं उनकी quality of construction बैटर है as compare to our quality of construction. मुख्य मंत्री जी, आप नौज़वान हैं और आपके जो सचिव, लोक निर्माण विभाग है, अनिल खाची जी वे भी ईमानदार हैं और कम्पिटैंट हैं। हम चाहेंगे कि इन सड़कों का जो हिमाचल में quality of construction है, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अभी मैं जब सुबह आया तो मैंने अमर उजाला में खबर देखी कि "सड़कों की घटिया मैटलिंग पर हाईकोर्ट ने अफसरों से मांगा शपथपत्र "। अब इसमें कसौली डिविज़न का जिक्र किया गया है। कोई कसौली डिविज़न में सड़क बनी होगी उसकी तीन या छः महीने में मैटलिंग/टारिंग उखड़ गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह काम जो सरकार का है, वह हाईकोर्ट कर रहा है। करना तो सरकार को चाहिए। मैं चाहूंगा कि ऐसी-ऐसी जो घटनाएं हैं, जो कसौली का जिक्र किया है, ऐसी-ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश से विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर आती रहती है। आज ठेकेदार जो अनियमितताएं बरतते हैं quality of construction जहां पर पूअर है, उन ठेकेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जो दूर-दराज़ के क्षेत्र है वहां पर ठेकेदार लॉबी हावी रहती है। चाहे कोई भी सरकार आए।

चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे भाजपा की सरकार आए। ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकदार लॉबी हावी रहती है। उन पर भी मुख्य मंत्री जी अंकुश लगाने की जरूरत है। आपका चुनाव क्षेत्र भी कठिन है, दिक्कत वाला है, जैसे हमारा शिमला,

28.03.2018/1250/जेके/वाईके/3

सोलन, सिरमौर और मण्डी का ट्राइबल एरिया है, वहां पर काम करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जितने भी प्रोजैक्ट आए, हमने देखा वे प्रोजैक्ट कभी भी समय पर कम्पलीट नहीं हुए। परवाणू-शिमला फोर लेनिंग है वह मेरे ख्याल डेढ़ साल it is delay by one and half year. सबसे बड़ी बात मुख्य मंत्री जी यह है कि आपको इस वक्त बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारा एक्विज़िशन बहुत पूअर होता है acquisition of land नहीं होती है। फोरैस्ट क्लीयरैंसिज जैसे कि मेरे से पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि सड़कों में पैसा आ गया लेकिन एफ0सी0ए0 नहीं होती है। एफ0सी0ए0 पी0डब्ल्यू0डी0 का विषय नहीं है लेकिन मुख्य मंत्री जी मैं कहना चाहूंगा कि वन विभाग को भी आप हिदायत दें कि फोरैस्ट क्लीयरैंसिज जो रोड़ज की है, वह प्राथमिकता के आधार पर रहे। हम देखते हैं कि वन विभाग की मानसिकता नाजायज़ ऑब्जैक्शन्ज़ लगाने की है। एफ0सी0ए0 क्लीयरैंसिज के लिए केसिज़ आते हैं तो वे नाजायज़ ऑब्जैक्शन्ज़ लगाते हैं। आज इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अभी जैसे जिक्र किया कि वर्ल्ड बैंक प्रोजैक्ट्स की रोड़ज आई, 1350 करोड़ रूपया आया, पांच-पांच साल सात-सात साल से सड़कें कम्पलीट नहीं हुई। Construction cost escalation हो गया।

28.03.2018/1255/SS-YK/1

श्री हर्षवर्धन चौहान क्रमागतः

अध्यक्ष महोदय, इसमें टाइम बाउंड करने की बहुत ज़रूरत है। कई ठेकेदार तीन, चार

या पांच-पांच काम ले लेते हैं उसमें भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। इसमें लिमिट फिक्स की जाए। दो या तीन काम से ज्यादा एक ठेकेदार को न मिलें। अगर वह काम को पूरा करने में डिले करता है तो उस पर पैनल्टी लगाने की ज़रूरत है। अभी जैसे नेशनल हाईवेज़ का ज़िक्र किया गया, नेशनल हाईवेज़ बनेंगे या नहीं बनेंगे यह तो समय बतायेगा। मगर नेशनल हाईवेज़ का रख-रखाव रखना बड़ा ज़रूरी है। 69 रोडस हैं। कहीं ऐसा न हो कि 69 रोडस को पी0डब्ल्यू0डी0 वाले कहें कि हमने डी0पी0आर0 बना कर भेजी है केन्द्र सरकार से पैसा आयेगा और कहीं ऐसा न हो कि पैसा न आए। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि उन रोडस का रख-रखाव बेहतर ढंग से करेंगे, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है।

पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा कोर नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें किस-किस गांव की कितनी आबादी है और कैसे-कैसे सड़कों से जोड़ा जाए, वह आपका कोर नेटवर्क भी पुराना हो चुका है। उसको भी अपडेट करने की ज़रूरत है। मेरे खुद अपने चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जोकि कोर नेटवर्क में नहीं जुड़े हैं। आज अगर हम पी0डब्ल्यू0डी0 को कहते हैं, बजट में रोड डालते हैं तो वे कहते हैं कि यह कोर नेटवर्क में नहीं है। कोर नेटवर्क में आप उसको डालेंगे तो प्रधान मंत्री सड़क योजना में उसकी फंडिंग हो जायेगी। आज बहुत सारे गांव ऐसे छूट गए हैं जो 250 से कम आबादी के हैं। कोई गांव 100, 150 या 200 की आबादी का है। उनको कोर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ करके आपको एक नई सड़कों की रूपरेखा बनाने की ज़रूरत है। जैसे अभी आशा कुमारी जी ने ज़िक्र किया कि चम्बा, सिरमौर और कई क्षेत्रों में जहां पर बैकवर्ड पंचायतें हैं, बहुत सारी सड़कों को बैकवर्ड एरिया सब-प्लान से पैसा मिलता है। हम पी0डब्ल्यू0डी0 को पैसा देकर रोड बना देते हैं मगर बाद में उसमें मैंटीनेंस का कोई प्रावधान नहीं है। पी0डब्ल्यू0डी0 रोड बना तो देगा, फिर कहता है कि हमारे बजट में एपीयर नहीं है, हमारे पास मैंटीनेंस के लिए पैसा नहीं है। हमारे जिला सिरमौर में बहुत सारी सड़कें बी0आर0जी0एफ0, बैकवर्ड एरिया सब प्लान, राष्ट्रीय श्रम विकास योजना जोकि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, उसमें बनाई गई हैं। मगर उनके रख-रखाव के लिए पैसे की आवश्यकता है।

28.03.2018/1255/SS-YK/2

कहते हैं कि पैसा नहीं है। मुख्य मंत्री जी उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसी सड़कें जोकि ब्लॉक से बनी हैं या किसी भी हैड से बनी हैं उनको भी पी0डब्ल्यू0डी0 में लेने की ज़रूरत है और उनको मैंटेन करने की बहुत आवश्यकता है।

मशीनरी पी0डब्ल्यू0डी0 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बरसातों में सड़कें बंद हो जाती हैं। ऐसे तो हमारे पूर्व मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह के समय में बहुत सारी मशीनरी आई है। मगर मेरे अपने शिलाई डिवीजन में आज से 10-12 साल पहले की दो जे0सी0बी0 मशीनें हैं। वे काम नहीं करती हैं। एक डोजर बहुत पुराना है। वहां पर टिप्पर नहीं हैं। मैं चाहूंगा, जैसे मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में भी दिया है कि जब भी आपकी नई मशीनरी आए तब कम-से-कम आप जो हार्ड एरियाज़, दूर-दराज के क्षेत्र हैं वहां पर प्राथमिकता के आधार पर नई मशीनरी को भेजा जाए। आज ड्राईवर नहीं हैं। आपकी जे0सी0बी0 मशीन आ गईं, आपके डोजर आ गए हैं मगर आपके पास उनको चलाने के लिए ड्राईवर उपलब्ध नहीं हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जे0सी0बी0 के ड्राईवर/ऑपरेटर की नियुक्ति की जाए। पूर्व सरकार ने उसकी शुरूआत तो की थी मगर बहुत कम नियुक्त हुए थे। मेरे एक नेशनल हाईवे में कोई एक करोड़ रुपये की बहुत बड़ी मशीन आई हुई है मगर उसका ड्राईवर ही नहीं है। एक-डेढ़ साल से वह मशीन खड़ी हुई है। मुख्य मंत्री जी हम चाहेंगे कि इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पांवटा-शिलाई- हाटकोटी नेशनल हाईवे जोकि मेरे चुनाव क्षेत्र की लाइफ लाइन है उसमें टारिंग हो रही है। दो बार टैंडर हुए, मगर अभी भी जो काम किया जा रहा है उसका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत पूअर है। अभी छः महीने पहले ठेकेदार ने काम किया, उसमें गड्ढे पड़ गए हैं। मैं विभाग से चाहूंगा --(व्यवधान)-- मैं इस सदन से बाहर था। ऐसा है, मुख्य मंत्री जी, ये कुछ बातें ऐसी हैं जोकि राजनीतिक नहीं हैं। मैं खुद भी राजनीतिक बातें कम करता हूं। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। आपसे उम्मीद करते हैं कि इसे इम्प्रूव करो। बेहतर करो। अमूमन क्या होता है कि पी0डब्ल्यू0डी0 मुख्य मंत्री के पास होता है और मुख्य मंत्री के पास अपने विभाग को देखने के लिए समय नहीं होता। आप इसमें समय दें। We will be grateful यदि आप इसको समय देंगे। इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठेकेदारों के ऊपर सख्ती करने की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ वर्क

इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्या होता है कि बारिश हो रही है फिर भी ठेकेदार टारिंग कर रहा है।

28.03.2018/1255/SS-YK/3

सड़कों में आज सोलिंग करेंगे और दो साल बाद टारिंग करेंगे। जब टारिंग करने की बारी आती है तो सोलिंग उखड़ जाती है। पी0डब्ल्यू0डी0 का जो वर्क कल्चर है उसको बदलने की ज़रूरत है। उसको ठीक करने की ज़रूरत है। --(घंटी)--सर, मैं वाइंड अप कर रहा हूं।

28.03.2018/1300/केएस/एजी/1

श्री हर्षवर्धन चौहान जारी---

हम देखते हैं कि मैटलिंग की जाती है। पी.डब्ल्यू.डी. का टारगेट होता है कि एक किलोमीटर, पांच किलोमीटर या 10 किलोमीटर रोड़ की टारिंग करनी है। एक-एक किलोमीटर का एक-एक रोड़ पकड़ लेंगें फिर ठेकेदार को ठेका दे देंगें। मशीनरी उसके पास नहीं है। एक किलोमीटर के लिए वह मशीनरी नहीं लाता और मैनुअली उसको करता है और क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत घटिया होती है। मुख्य मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस भी रोड़ की मैटलिंग करनी है, कम से कम तीन या पांच किलोमीटर रोड़ मैटल किया जाए ताकि ठेकेदार मशीनरी भी लाए और उसका जो ठेका है, उसको इकनॉमिकली वाइबल भी हो।

अध्यक्ष महोदय, फंड्ज़ के बारे में जिक्र किया गया । पी.डब्ल्यू.डी. का जो स्टेट हैड है, उसमें पैसे का प्रावधान किया जाए । आज पी.डब्ल्यू.डी. विभाग, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड या अन्य प्रोजैक्ट्स पर निर्भर है। स्टेट हैड का पैसा पी.डब्ल्यू.डी. का कम हो रहा है। इस वजह से जो हमारे इंटिरियर के रोड़्ज़ हैं, उनकी मेंटिनैंस कम हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि हमारे

दूर-दराज के क्षेत्रों के रोड़ज़ की मेंटिनैंस के लिए लोक निर्माण विभाग के पास पैसा हो।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सारे बिन्दुओं पर चर्चा की है। मैं उम्मीद करुंगा कि मुख्य मंत्री जी और लोक निर्माण विभाग उस ओर ध्यान देगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोवकाश के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक स्थगित की जाती है।

28.3.2018/1410/av/dc/1

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को आज एक कार्यक्रम के लिए निमन्त्रण पत्र प्राप्त हुआ है जिसको केवल रिमाइंड करने के लिए मैं सूचित कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग ने आज जलवायु परिवर्तन के बारे में एक कार्यशाला रखी है और इसमें काफी अच्छी संख्या में डिगनिटरीस आ रहे हैं जिसमें डा0 हर्ष कुमार भानवाला, अध्यक्ष (नाबार्ड) विशेष रूप से आ रहे हैं। इनके अलावा डा0 अनिल कुलकर्णी (भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरु), प्रो0 ए0के0गोसाईं (भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली), डा0 आशीष चतुर्वेदी, निदेशक (जी0आई0जैड0 इंडिया, दिल्ली) और डा0 अजय कुमार माथुर, मुख्य निदेशक (द एनर्जी एण्ड रिसोर्सिस इनस्टिच्यूट, नई दिल्ली) से आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्विटजरलैंड से अम्बेसेडर, डा0 एन्ड्रेयास बोम भी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इसलिए आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यथासम्भव प्रयास करें। यह कार्यशाला 6.30 बजे (अपराह्न) पीटरहाफ में आयोजित होगी और उसके बाद डिनर का आयोजन भी है।

अब माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी चर्चा में भाग लेंगे।

28.03.2018/1415/TCV/DC-1

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या:10 पर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हूं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिनके पास लोक निर्माण विभाग भी है, वे अभी मौजूद नहीं है। फिर भी मैं अपनी बात रखता हूं। अभी मुझसे पूर्व व़क्ताओं ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा जुमला है, उसकी यहां पर चर्चा हुई। वे एक ही बार में 70 से ज्यादा नेशनल हाईवेज़ खोलने की बात कह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि इन 70 नेशनल हाईवेज़ को बनाने के लिए नॉर्मज़ रखे गये हैं। इसके लिए 10 पैरामीटर्ज़ हैं और इन पैरामीटर्ज़ में जब तक ये फिट नहीं होंगे, आप राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस के समय में हमने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के समय में दिल्ली में श्री नरेद्र मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने इन नेशनल हाईवेज़ के लिए एक पैसा नहीं दिया। केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने भी एक पैसा नहीं दिया। फिर कहां से इनकी डी0पी0आर बननी थी? क्योंकि इन नेशनल हाईवेज की डी0पी0आर0 और कंसल्टेंसी के लिए सारा पैसा केन्द्र से आना था। केन्द्र से पैसा तब आया जब हमारी सरकार बदल गई और वह भी मामूली सा पैसा दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो 273 करोड़ रुपया आया है, उससे आप कितने कंसल्टैंट्स अप्वाईंट करेंगे? कितनी डी0पी0आर्ज़ तैयार होंगी? केन्द्र के बजट में 65 हजार करोड़ रुपया रखा गया है, उसमें एक पैसा भी हिमाचल प्रदेश के खाते में नहीं रखा गया है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा जुमला है और जुमले की सबसे बड़ी फैक्टरी भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप कहते हैं- मैक-इन-इंडिया, वह तो होगा नहीं। लेकिन मेक-इन-जुमला में आप नम्बर वन पर है। ये तो मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं, पता नहीं कब पूरे होंगे। हिमाचल प्रदेश में सड़कों के लिए डॉ0 परमार से लेकर राजा वीरभद्र सिंह तक, बीच में आपकी भी सरकारें/मुख्य मंत्री रहे, सभी ने प्रयास किये हैं। इसलिए आज हम पहाड़ी राज्यों में सड़क के मामले में बहुत आगे हैं। आज इनमें इम्प्रूवमैंट करने की जरूरत है। इसके लिए पहले बजट के हिसाब से नार्मज़ छोटे रखे गये थे, अब इसको इम्प्रूव करके चौड़ा करने की जरूरत है।

28-03-2018/1420/NS/HK/1

श्री जगत सिंह नेगी -----जारी।

आज की डेट में क्रैश बैरियर का ज़माना आ गया है। आप देखेंगे जो पैरापिट लगे हैं, वे मिट्टी के ढांचे खड़े किये हुये हैं और अगर आप इनको लात मारेंगे तो नीचे गिर जायेंगे। आज क्रैश बैरियर का ज़माना आ गया है। आज आपको हर सड़क को इम्प्रूव करके इसकी क्वालिटी को सुधारने की जरूरत है और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी चिन्तित हैं कि टारिंग ठीक होनी चाहिए। लोक निर्माण विभाग में आज की तारीख में टारिंग सबसे बड़ी गड़बड़ी का काम हो रहा है। इसमें ठेकेदार खूब पैसे कमा रहा है। इसमें बिच्चूमन, वज़री और रोड़ी भी ठीक नहीं लगती है। इससे हमारा सारा पैसा वेस्ट हो रहा है। हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय उच्च मार्गों में सी0सी0 लाइनिंग शुरू की गई है। आप हिमाचल प्रदेश की कुछ सड़कों में टारिंग के वजाए सी0सी0 लाइनिंग शुरू करेंगे तो हमारी सड़कें अत्याधिक बेहतर हो सकती हैं। मैं नहीं कहता कि लोक निर्माण विभाग में सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं। हमारे लोक निर्माण विभाग में बहुत अच्छे, कुशल और ईमानदार अधिकारी भी हैं। परन्तु इसमें ज्यादातर भ्रष्टाचार है। हम आज भ्रष्टाचार से किसी भी विभाग में छूटे नहीं हैं, चाहे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, वन या राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग है। हम भ्रष्टाचार से कहीं नहीं छूटे हैं। भ्रष्टाचार सब जगहों पर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने राम राज्य बनाने की बात की है। क्या आपके राम राज में कमीश्न सिस्टम खत्म हो जायेगा? जिसको सभ्य लोग कमीश्न कहते हैं, हम इसको रिश्वतखोरी कहते हैं। क्या ये रिश्वतखोरी खत्म हो जायेगी? लोक निर्माण विभाग में ऐस्टिमेट रिश्वत से शुरू किया जाता है। ऐस्टिमेट के बाद जब टैंडर लगता है, तब भी रिश्वत देनी पड़ती है। टैंडर के बाद अवार्ड या नेगोशिएशन होना है, तब भी रिश्वत देनी पड़ती है। कामु शुरू करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है और बिल निकालने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। यह भ्रष्टाचार सभी विभागों में हैं। लेकिन आज यहां पर लोक निर्माण विभाग की बात हो रही है तो मैं इसे लोक निर्माण विभाग तक ही सीमित रखता हूं। यह भ्रष्टाचार किस तरीके से राम राज में खत्म होगा? इसके लिए बहुत चिन्तन करने की आवश्यकता है। जब तक लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार जे0ई0 से ले करके चीफ इंजीनियर या ई0एन0सी0

तक जाता है, इसको नहीं रोक पायेंगे तो हम क्वालिटी की बात नहीं कर सकते हैं। हम टारगेट को कम्पलीट नहीं कर

28-03-2018/1420/NS/HK/2

सकते हैं। इसके बारे में हमें चिन्तन करने की सख्त जरूरत है। अभी हमारे नेशनल हाइवे की फोर लेनिंग का काम चला हुआ है। हमने सारा काम National Highway Authority of India को छोड़ रखा है। आप परवाणू से सोलन के बीच में ही निम्न स्तर का काम देखेंगे, शुरू में इसमें 25-25 क्रेट लगा करके ऊंचे-ऊंचे डंगे लग रहे थे, हमने इसका विरोध किया तब जा करके इसको छोड़ा गया। लेकिन आजकल फिर नया सिस्टम शुरू किया गया है कि मिट्टी की दीवारें बननी शुरू हो गई हैं। इसमें इतना समय बर्वाद किया गया है कि हमें नहीं लगता है कि हम दस घंटें में भी शिमला पहुंच पायेंगे। हमें NHAI के ऊपर सुपरविज़न करने की जरूरत है। अरबों रुपये इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं और टारगेट पर काम नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके पास आजकल हैलीकॉप्टर है। मुझे याद है, जब नया-नया हैलीकॉप्टर सरकार ने ट्राइबल सब-प्लान से जनजातीय इलाकों की सुविधा के लिए लिया था तो आपकी पार्टी बड़ा शोर करती थी कि यहां पर हैलीकॉप्टर लिया गया है। आजकल आप भी इस हैलीकॉप्टर का बड़ा आनन्द ले रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी का भी रोड से जाना कम है, ये भी ऊपर-ऊपर से जाते हैं, सड़कों की दुर्दशा तो ऐसी ही रहेगी। मुझे ज्यादा चिन्ता इस बात की है कि सड़कों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री महोदय हैलीकॉप्टर से जायेंगे और आयेंगे तो सड़क को कौन देखेगा? इसके लिए भी हमें चिन्ता करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे में फोर लेनिंग का काम हो रहा है। इसमें भी पैरापिट लगाने शुरू कर दिये हैं। इन पैरापिट की ऊंचाई इतनी कम है कि गाड़ियां ज्यादा-से-ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। जबकि आज के जमाने में क्रैश बैरियर लग रहे हैं तो परवाणू-शिमला हाइवे में क्यों नहीं लग रहे हैं? जबकि मिट्टी और पत्थर वहीं पर है और ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए इस बात को नज़रअन्दाज किया जा रहा है। ये पैरापिट बहुत कम हाईट के लग रहे हैं, इस पर चिन्तन करने की जरूरत है।

28.03.2018/1425/RKS/YK-1

श्री जगत सिंह नेगी...जारी

अभी यहां पर सड़कों की डी.पी.आर्ज.की बात चली। जब हमारी सरकार थी तब भी डी.पी.आर्ज. बनाने में समय बर्बाद हुआ। जबकि केन्द्र सरकार ने स्टेट फोरैस्ट डिपार्टमैंट को एफ.आर.ए. के तहत 5 हैक्टेयर तक सड़क बनाने की पॉवर डी.एफ.ओज. को दी है। पांच हैक्टेयर तक सड़क बनाने में आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने लैवल पर कर सकते हैं। परन्तु फोरैस्ट डिपार्टमैंट यह करने के लिए राज़ी नहीं है। हमने जिला किन्नौर में 120 से ज्यादा सड़कों को एफ.आर.ए. के तहत बनाया है। इसके लिए हमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ा और न ही हमें शिमला आना पड़ा। जो वहां पर डी.एफ.ओ. हैं उन्होंने इस बात को अच्छी तरह समझा और कानून के तहत अमलीज़ामा पहनाया। एफ.सी.ए. में भी 5 हैक्टेयर तक का प्रावधान है। आप 5 हैक्टेयर में छोटी-छोटी सड़के बनाइए। फस्ट-फेस, सैकिंड और थर्ड फेस में सड़कें बनाइए और आपकी सारी डी.पी.आर्ज. यहीं पर तैयार हो जाएगी। डी.पी.आर्ज. का यह रोना खत्म हो जाएगा। इसके लिए पैसा भी नहीं लगेगा और समय भी बचेगा। इस कार्य को जल्द-से-जल्द करने की आवश्यकता है।

मेरे चुनाव क्षेत्र में अभी बहुत सारी सड़कें बनी हैं। सड़क के क्षेत्र में किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बनने जा रहा है। हमने इसके लिए एक टारगेट रखा था कि वर्ष 2018 के अंत तक सारा जिला सम्पर्क सड़कों से जुड़ जाएगा। उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं और हम टारगेट के नज़दीक भी हैं। जो टारगेट हमने सैट किए हुए हैं, चाहे वे चाइना बोर्डर तक सड़क पहुंचाने की बात हो या दूर-दराज़ के 15-20 इलाकों को जो सड़क जा रही है, उनके ऊपर जब से आपकी सरकार बनी है, ये सारे काम बंद हो गए हैं। क्योंकि वहां पर जो आपके छुटभैया नेता हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो टैंडर हैं, जिन कार्यों के लिए भारी-भरकम बजट आया

है, उन सभी कामों को बंद करा दिया है। उन कामों को तेजी से करने की जरूरत है अन्यथा यह सारे-का-सारा काम रुक जाएगा।

28.03.2018/1425/RKS/YK-2

किन्नौर में जो हमारी सम्पर्क सड़क तरांडा है, उसमें हमने पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से एक टनल बनाने का काम शुरू किया है। जोकि 250 किलोमीटर की टनल बननी है। लेकिन काफी लम्बा अरसा हो गया उस टनल का काम बंद हो गया है। उसमें बजट का प्रावधान भी किया है परन्तु चीफ इंजीनियर के लैवल पर या पता नहीं किस लैवल पर फाइलें इधर-उधर पटकाकर जो चला हुआ काम है, उसको बंद कर दिया गया । पी.डब्ल्यू.डी. ने हिमाचल में ऐसी कोई टनल नहीं बनाई है। यह पहली टनल है जिसकी शरूआत जनजातीय इलाके से हुई है। इसमें भी इन्होंने अड़ंगा डाल दिया। पी.डब्ल्यू.डी. में 250 मीटर की यह पहली टनल बनेगी। इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। केवल लाल फीताशाही के कारण हमारा सारा काम रुका हुआ है। मैं पी.डब्ल्यू.डी. के बिल्डिंग्स वर्क्स की बात करना चाहता हूं। हम एक बिल्डिंग का काम जिस बजट के साथ शुरू करते हैं उसका कार्य 10 साल में भी कम्पलीट नहीं होता है। किन्नौर में एकलव्य स्कूल है। माननीय मोदी जी ने दिल्ली में बड़ी चर्चा की कि हम जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य स्कूल खोलेंगे। इसकी शुरूआत माननीय मोदी जी ने नहीं की बल्कि इस एकलव्य स्कूल की शुरूआत यू.पी.ए. गवर्नमैंट ने की थी। वर्ष 2006 में हमने सबसे पहला एकलव्य स्कूल हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला किन्नौर में शुरू किया। आज इस स्कूल में 250 से भी ज्यादा लड़के-लड़कियां इग्लिंश मीडियम में पढ़ रहे हैं। उसका 21 करोड़ रुपये का बजट होने के बावजूद भी पी.डब्ल्यू.डी. इस स्कूल की केवल एक ही बिल्डिंग बना पाया है। वह भी हॉस्टल की बिल्डिंग है और बाकी बिल्डिंग्स का काम बंद पड़ा हुआ है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जिन स्कीमों में बजट का प्रावधान हुआ है, उनके ऊपर तेजी से काम किया जाए। धन्यवाद।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। यहां पर एक मंत्री जी बैठे हैं और बाकी सारी सरकार गायब है। ये लोग इस प्रदेश में क्या स्थिति पैदा करना चाहते हैं? इस असैम्बली की अपनी एक गरीमा है। अध्यक्ष महोदय, आपको

इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को लिखित रूप में भेजना चाहिए कि वे सदन के दौरान यहां पर बैठें।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री राम लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

28.03.2018/1430/बी0एस0/वाई0के0-1

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या- 10 जो लोक निर्माण विभाग के ऊपर है, उस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर हमारी बात को अपने कमरे में सुन रहे होंगे तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हमारे साथी बैठें है, वे कृपया हमारी बात को पल्यूट करके वहां न पहुंचाए केवल मात्र अधिकारियों पर छोड़ दें कि कौन सा सदस्य क्या बोल रहा है। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि फिजूल में बीच में टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने विचार रख रहा हूं, आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं फिर भी आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो वक्ता कह रहा है वह अपनी समझ से कह रहा है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अभी तो कोई बोल ही नहीं रहा है आप पहले से ही तैयारी कर रहें है।

श्री राम लाल ठाकुरः नहीं, मुझे मालूम है ये करते रहते हैं। इसलिए मैं इनको तैयार कर रहा हूं। कृपया ऐसा मत करो। अध्यक्ष महोदय, सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं । हिमाचल प्रदेश के बनने के बाद और प्रजातंत्र में जब से हमने कदम रखा और पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के माध्यम से जब हिमाचल प्रदेश ने बाकी राज्य के साथ आगे बढ़ना शुरू किया तो उस समय हिमाचल प्रदेश की दयनीय स्थिति होती थी। हमारा कोई अगर कर्मचारी अप्पर शिमला में बदली होता था तो उसकी मां घर में रोना शुरू कर देती थी। क्योंकि 40-40, 50-50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। आज वह परिस्थिति नहीं है। हमने बड़ा लम्बा सफर तय किया है और डॉ0 यशवंत सिंह परमार जी जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री हुए, हिमाचल प्रदेश के निर्माता थे, उनके आशीर्वाद से हमने इस रफ्तार से चलना शुरू किया कि आज हिमाचल प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में और खासकर जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें हिमाचल प्रदेश को सम्मान जनक

स्थिति में ला करके हमारी सरकारों ने खड़ा किया है। मैं इसका श्रेय केवल कांग्रेस को ही नहीं देना चाहता हूं। माननीय शांता कुमार जी मुख्य मंत्री बने उन्होंने भी अपनी सामर्थय के मुताबिक काम किया। माननीय धूमल साहब दो बार मुख्य मंत्री रहे उन्होंने भी अपने सामर्थय के मुताबिक सड़कों के विस्तार के लिए कार्य किया। बड़े अरसे तक माननीय वीरभद्र सिंह जी छः बार

28.03.2018/1430/बी0एस0/एच0के0-2

मुख्य मंत्री रहे, इन्होंने भी बड़ी शक्ति से सड़को के निर्माण के लिए अपना योग दान दिया और आज आप और हम यहां खड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी जो नेशनल आईवेज की बात है उनके बारे में पहले भी चर्चा हुई और अब भी मैं कहूंगा कि कटौती प्रस्ताव के माध्यम से हमें बोलने का मौका मिला है। सैद्धांतिक जो स्वीकृतियां हैं वह तो होगी ही, मैं उसके लिए यह नहीं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यह स्कोर चुनावों के लिए किया या कांग्रेस पार्टी ने किया, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जितने भी नेशन हाईवेज केन्द्र सरकार के मंत्री जी ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किए उनमें अभी समय लगेगा। धर्मशाला से स्टेटमैंट आई, फिर रिवाईज स्टेटमैंट आई फिर कॉरीजंडम इशू हुआ, होते-होते यह नम्बर 70 तक चला गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कितने वर्षो में पूरा होगा। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि डी.पी.आर. बनाना कोई आसान बात नहीं है आपको पैसा मिला, माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी उनको भी पैसा मिला, उन्होंने 8 डी.पी.आर. बनाने के लिए कमद उठाए, आपका नम्बर आप कहते हैं 51 तक पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय, कहने और करने में फर्क होता है, अगर मैंने कोई स्टेटमैंट दे दी तो क्या डी.पी.आर. तैयार हो गई। मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी कंस्लटेंट अप्वांइट होगा, उसे भी पैसा केन्द्र सरकार देगी। उसके बाद फिर डी.पी.आर. जो बनेगी उसके बाद सारी औपचारिकताएं बाकी होगीं। जो कंस्लटेंसी का कार्य है यहां ज्यादा समय लेगा। अगर हम यह कहेंगे कि हमने अप्रैल महीना दे दिया, अप्रैल महीने में यह खत्म हो जाएगा यह सम्भव नहीं है। बड़ा कठिन कार्य यह भी है कि फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में इसकी कलियरेंस नहीं आ जाती तब तक यह कार्य कैसे होगा।

28.3.2018/1435/DT/YK/1-

श्री राम लाल ठाकुर...द्वारा जारी

मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या अप्रैल महीने में आपके कंसलटैंट इस काम को पूरा कर पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, जब तक फोरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत इसकी क्लीयरैंस नहीं होती, जब तक प्राइवेट लैंड की एक्विजिशन नहीं हो जाती तब तक इन सड़कों का निर्माण करना बहुत कठिन है। हम तो यहां पर माथापची कर रहे हैं लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके हाथ में भी कुछ है? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार इन नैशनल हाईवे को नहीं बनाएगी। ये सड़कें नैशनल हाईवे अथॉरटी ऑफ इंडिया के अंडर बनेगी। इसमें भले ही इंजीनियर्ज हिमाचल प्रदेश के हों। लेकिन हम दोनों तरफ से अड़े हुए हैं। हम कुछ कह रहे हैं और सतापक्ष के लोग कुछ कह रहे हैं। हर विषय की व्यावहारिकता को जानते हुए हम लोगों को इसमें आगे बढ़ना होगा। Let's think for the best. अभी जो कदम उठ रहे हैं, इसका कितने सालों में परिणाम आएगा, फसल कब पकेगी और कब लोगों को इसका फायदा होगा। यह भविष्य के गर्भ में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर जो हमारी सड़कें बन रही हैं, अभी अखबारों में भी आया है कि जो कांगड़ा का एरिया है उसमें ज्वाला जी तक अप्रैल महीने में टेंडर हो जाएगा। जो फोरलेन शिमला के लिए बनेगी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। वैसे ही कीर्तपुर- मण्डी-कुल्लू फोर लेन का काम भी शुरू हुआ है। अध्यक्ष जी, यह काम सैंटर गवर्नमैंट के हैं। लेकिन 3 साल हो गए गेरामोड़ा से लेकर बिलासपुर तक की सड़क का काम खड़ा है। क्यों खड़ा है? ठेकेदार काम कर गए,सब-कॉन्ट्रैक्टर भी आ गए, पैसा किसी को नहीं मिला। कंपनियां भाग कर चली गई। आज एक ऐसी परिस्थिति है जो छोटे-छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका यह पैसा मार कर बैठे हैं। तीन साल हो गए मेरा प्रदेश सरकार से निवेदन है क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कृपया इन

सड़कों का काम चरणबद्ध तरीके से और समयावधि में किया जाए। नेशलन हाईवे नालागढ-स्वारघाट का काम कब से शुरू हुआ? मुझे भी इस काम को 8-10 साल देखते

28.3.2018/1435/DT/YK/-2

हुए हो गए। कोई भी ठेकेदार सड़क को पक्का करने का काम करेगा तो उसका मिक्सिंग प्लांट within 30 k.m. from the work होना चाहिए। यहां पर यह हो रहा है कि 70 किलोमीटर से रोड़ी मिक्स होकर ,बिचुमन मिलाकर आ रही है। जब तक यह मौके पर पहुंचती है तो वह ठंडी हो जाती है। यही कारण है कि सड़क बनती बाद में है और उखड़ना पहले शुरू हो जाती है। क्या जो सड़कों में काम चला हुआ है उस काम की गुणवत्ता सही है? आज नई टैक्नॉलाजी है। आज जो प्लेन एरिया है उनकी भांति पहाड़ी प्रदेशों में भी काम हो रहा है। पहले हम सड़कों में गटका डालते थे लेकिन अब पूरे हिन्दुस्तान की तरह हिमाचल प्रदेश में भी 30 एम.एम. की रोड़ी पड़ेगी और वह रोड़ी क्रशर की होगी। वह खड्डों की रोड़ी नहीं होगी। उसके बाद उसमें 10 प्रतिशत लॉकल मिट्टी मिक्स होगी। तब उसको मिला कर, मिक्स करके, पानी डाल के

28.03.2018/1440/SLS-AG-1

श्री राम लाल ठाकुर ...जारी

तब उसकी पहली सतह बनेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इस औपचारिकता को पूरा नहीं किया जा रहा है। कहीं पर भी मिक्सर और वाईब्रेटिंग मशीनें नहीं लगी हैं। होना यह चाहिए कि जब रोड़ी बिछाई जाए तो बाईब्रेटर ऑन होना चाहिए। लेकिन वहां पर बाईब्रेटर को बंद रखा जाता है। मशीन चली है और बाईब्रेट न होने के कारण मैटिरियल में गड़बड़ हो रही है। मेरा निवेदन है कि यह जो छोटी-छोटी बातें हैं, जो कल को उठेंगी, उनके ऊपर हम लोगों को आज ही ध्यान देना चाहिए।

मेरा मुख्य मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि लोक निर्माण विभाग में पुरानी

मशीनरी है। जो डोज़र और जे.सी.बीज. हैं या जितनी भी मशीनरी वहां काम कर रही है, वह सारी मशीनरी पुरानी हो गई है। कहीं मशीनरी के ऊपर ड्राईवर नहीं है तो कहीं लेबर का आदमी ही उस पर काम कर रहा है। फिर जो मशीनरी है, उसकी बुक वैल्यु से ज्यादा पैसा साल भर में उसकी रिपेयर पर ख़र्च हो रहा है। मेरा निवेदन है कि अगर रिपेयर का पैसा ज्यादा लगना है, बुक वैल्यु मशीनरी की कम है, तो इन पुरानी मशीनों को रिप्लेस करना ज़रूरी है। यह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग में जो गाड़ियां हैं, वह ऐसी हैं कि मान लो किसी एस.डी.ओ., एक्स.ई.एन. की गाड़ी है; एस.ई. को तो शायद ठीक गाड़ी मिल भी जाती है पर नीचे के अधिकारियों की गाड़ियों की बुक वैल्यु भी ख़त्म है। उन पर जितने पैसे का तेल लग रहा है, जितनी उनकी रिपेयर हो रही है उतनी वह गाड़ी चल नहीं रही है। मेरा निवेदन है कि नई मशीनरी खरीद कर सब-डिविजन वाईज दी जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2 जे.सी.बीज. हैं। एक नैणादेवी में है एक सब-डिविजन नम्होल में है। नैणादेवी में 2 सब-डिविजन हैं जो एक नैणादेवी और दूसरा स्वारघाट है।

28.03.2018/1440/SLS-AG-2

वहां ज़मीन पथरीली है और कटाव ज्यादा होता है। इसलिए बरसात में नुकसान होने पर अगर जे.सी.बी. नैणा देवी में चली गई तो स्वारघाट का एरिया बंद रहेगा क्योंकि वहां पर मशीनरी नहीं है। इसलिए व्यवहारिक रूप से मशीनरी का बंटवारा होना चाहिए। इसलिए मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि मेरे कुछ क्षेत्र दूसरे डिविजन्ज के अंदर हैं। बिलासपुर में घुमारवीं का डिविजन अलग है लेकिन डिविजन नंबर-1 और डिविजन नंबर-2 बिलासपुर शहर के अंदर हैं। डिविजन नंबर-2 नैणा देवी निर्वाचन क्षेत्र के सारे एरिया के लिए है लेकिन वहां पर कुछ गांव ऐसे हैं जहां सड़क नहीं बन पा रही है। इसलिए नहीं बन पा रही हैं क्योंकि वह डिविजन

नंबर-I के अधीन है। ब्रह्मपुखर के पास विनायकघाट नाम से जगह है जहां से बंदला के लिए सड़क जाती है। वहां से नीचे जितने भी गांव हैं, उनमें एक जिनणु गांव हैं जहां के लिए सड़क ब्रह्मपुखर के पास से नीचे उस गांव के लिए जानी है जो कि अंतिम गांव है। ऐसे ही बंदला सड़क से भी एक लिंक रोड संगलेड़ी गांव के लिए जाना है जो हरिजनों का है। लेकिन क्योंकि वह डिविजन नंबर-1 में हैं, इसलिए उनकी कोई देखरेख नहीं हो रही है। 10-15 सालों से सड़क में पैसा आ रहा है लेकिन पैसा लग नहीं रहा है क्योंकि यह जो डिविजन नंबर-1 है, उसमें यह एरिया है। यह बड़ा एरिया नहीं है। इसके लिए पंचायतों के प्रस्ताव आए हैं। यह जो 2 प्रस्तावित सड़कें हैं, कृपा करके इनको डिविजन नंबर-2 में बदल दिया जाए ताकि डिविजन नंबर-2 में पूरे निर्वाचन क्षेत्र का काम सही ढंग से हो पाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा ज़रूरी काम और है। हम कह तो रहे हैं लेकिन आज हमारे पास ट्रेंड मैन पॉवर नहीं है, ड्राईवर्ज़ नहीं हैं। इसलिए जब डोज़र या जे.सी.बी चलाने की बात आती है, तो उसमें नुकसान यह हो रहा है कि उनको चलाने वाले नहीं मिल पा रहे हैं। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा, हमारे एक साथी ने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से लेबर रखी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार आई.पी.एच., बिजली बोर्ड या दूसरे विभागों में क्या कर रहे हैं?

28/03/2018/1445/RG/AG/1
श्री राम लाल ठाकुर--------जारी

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग तथा बिजली बोर्ड में ठेकेदार क्या कर रहे हैं या दूसरी जगहों पर ठेकेदार क्या कर रहे है? मेरा निवेदन यह है कि लोक निर्माण विभाग अपने श्रमिक डेली वेज़ पर रखें ताकि सब-डिवीजन में उनको एस.डी.ओ. और जे.ई. पूछ सकें। इसलिए आज मैन पॉवर को बढ़ाने की जरूरत है, कहीं ऐसा न हो मैन पॉवर के कारण काम खराब हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आए हैं। हमारे विधायक महोदय विधायक प्राथमिकता में अपनी एक

सड़क देते हैं, लेकिन उसके बाद वह फॉरेस्ट कंजरवेशन ऐक्ट के अन्तर्गत फॉरेस्ट क्लीयरेंस में फंस जाती है और उसमें स्वीकृति नहीं मिल पाती। विधायक यह कहते रहते हैं कि हमने विधायक प्राथमिकता में यह सड़क दी थी, लेकिन अभी तक यह नहीं बनी। मेरे चुनाव क्षेत्र में चंगर एरिये में एक धलेत-जडौरी सड़क है। मैं जब वन मंत्री था, तो इसकी स्वीकृति मिली थी और नाबार्ड में इसका पैसा मिला था। सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके बाद इस सड़क का काम तुरन्त शुरू कर दिया गया। उसके ऊपर 72,00,000/- रुपये खर्च हो गया। 72,00,000/-रुपये ठेकेदार को देने के बाद पता चला कि इस पर अभी भारत सरकार से फॉरेस्ट क्लीयरैंस नहीं है। इन पांच सालों में हमने कई चक्कर लगाए और अब जाकर उसको शो करना पड़ा कि यह पुरानी सड़क का फेस-॥ है। अब फेस-॥ तब बनाया क्योंकि इसको क्लीयर करवाना था। इसलिए ऐसी गल्तियां नहीं होनी चाहिए कि सड़क का पैसा आ गया, लेकिन औपचारिकताएं पूरी नहीं हैं। ---(घण्टी)---फॉरेस्ट कंजरवेशन ऐक्ट में औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। ये सब चीजें हमें पहले देखनी चाहिए। इसी प्रकार से मेरे चुनाव क्षेत्र में एक स्वहण-कटिरड़ - पंगवाणा सड़क है। इसका हाल भी यही है। इसलिए यह रुकी हुई है क्योंकि उसके लिए भी 80,00,000/-रुपये खर्च कर दिया, लेकिन फॉरेस्ट क्लीयरेंस उसकी नहीं आई है। इसलिए इन छोटी-छोटी चीजों पर हम ध्यान दें। इसके अतिरिक्त जो नैनादेवी और कोटधार के बीच में बबखाल पुल है क्योंकि अब इस पुल की क्लीयरेंस हो गई है और अब वह बनना शुरू हुआ है। इस बारे में कुछ लोग कोर्ट में भी गए और कोर्ट से भी इस बारे में आदेश हुए। अब कोर्ट ने कहा कि इसको एक साल में बना दो। क्या कोर्ट के पास ऐसी कोई टैक्नॉलॉजी है कि गोविन्दसागर के ऊपर एक साल में कोई पुल बन सकता है? व्यवहारिकता से बात नहीं हुई। आज उसका काम चला हुआ है।

28/03/2018/1445/RG/AG/2

हमीरपुर, ऊना एवं कांगड़ा जिले को जाने वाले लोगों के लिए इसका बहुत फायदा होगा। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि कम्पनी को कहकर प्राथमिकता के आधार पर इसका काम पूरा किया जाए।इसके अतिरिक्त बिलासपुर में गोविन्दसागर के ऊपर वैरी दरोला पुल है जिसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी

मिल गई है और माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसका फाउन्डेशन स्टोन भी रखा था। फिर सत्ता परिवर्तन के बाद वहां कुछ लोग ऐसे थे, कुछ पत्रकार थे जिन्होंने कहा कि यह यहां नहीं बनना चाहिए। उसके लिए 32 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई थी, उसका काम भी शुरू हो गया था, लेकिन फिर उसका काम बंद कर दिया गया। फिर कहा गया कि यह खैरियां से बनना चाहिए। इंजीनियर्ज कह रहे हैं कि खैरियां से बनाने में इस पर 350 करोड़ रुपये खर्च होगा। हम 32 करोड़ रुपये का पुल बना नहीं सकते, फोर लेन दूसरी साइड में चली गई। मेरा निवेदन है कि तुरन्त इस पुल का निर्माण किया जाए ताकि हमारे साथ के क्षेत्र बिलासपुर तक बढ़ने का मौका मिलेगा। अब तो 32 करोड़ रुपये से बढ़कर इस पुल की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये तक चली जाएगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करिए। आपको बीस मिनट हो गए हैं।

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहता हुआ पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये नेशनल हाइवेज़ बनें और न हमारे लोग और न ही उस तरफ बैठे हुए लोग इसको राजनीतिक दृष्टि से देखें। नेशनल हाइवेज़ बनें, ऐसा न हो---(घण्टी)----कि आप ऐसे ही बयान दे दें कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ तो केन्द्र सरकार ने करना है, उन्होंने ही पैसा देना है। इसमें आप भी कुछ नहीं करेंगे, यह सारा तो नेशनल हाइवे अथौरिटी ऑफ इण्डिया करेगी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है

28.03.2018/1450/जेके/वाईके/1

श्री राम लाल ठाकुरः------जारी-------

इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपा करके हम सदन में वह कहें, हम सरकार की तरफ से वह कहें जो हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में है ही नहीं, आप दिल्ली की सरकार से कहो कि ये काम जल्दी से पूरे होने चाहिए क्योंकि इनकी घोषणा हुई है। और क्योंकि सैद्धांतिक स्वीकृतियां इसका नाम दिया गया है तो सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इन

सड़कों को पूरा करना अति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2018/1450/जेके/वाईके/2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी।

सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर कटौती प्रस्ताव आया है, मैं उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट भाषण के समय भी मैंने कहा था कि जो 69 नेशनल हाइवेज़ की आप बात कर रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका ज़वाब दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो 69 नेशनल हाइवे डिक्लेयर हो चुके हैं, उनकी कन्सलटैंसी को हमने डी0पी0आर0 बनाने के लिए एक महीने का समय दिया है। बहुत अच्छी बात है, आपका प्रयास है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस मंच के माध्यम से आश्वासन दें विधान सभा के पटल पर कि जब इनकी डी0पी0आर0 बन जाएगी तो आप इनको नेशनल हाइवे डिक्लेयर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? इनप्रिंसिपल है, कितनी वायबिलिटी होगी, ट्रैफिक का वॉल्यूम क्या होगा, उस आधार पर नेशनल हाइवे डिक्लेयर होते हैं? अगर माननीय मुख्य मंत्री जी यह आश्वासन दे देते हैं तो हमें कोई ऑब्जैक्शन नहीं है। अगर डी0पी0आर0 बनने के बाद डिक्लेयर हो जाएंगे। ..(व्यवधान).. हम इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से ज़वाब चाह रहे हैं ।आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप रिप्लाई में कह देंगे कि जैसे ही डी0पी0आर0 बनेंगी डी0पी0आर0 बनने के बाद जितने भी नेशनल हाइवे नितिन गडकरी जी ने और जय राम जी ने बोले हैं, उनको नेशनल हाइवे इनप्रिंसिपल की जगह नेशनल हाइवे डिक्लेयर कर दिया जाएगा? ऐसा न हो कि जैसे एक नारा है कि "जय राम जी के बोल और जुमलों के ढोल" यह कहीं जुमला न बन जाए। आपने प्रयास किया है। हम आपके सार्थक प्रयास की सराहना करेंगे। आप इसको डिक्लेयर करवाएंगे तो भी अच्छी बात है। हिमाचल की सड़कें यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देख कर हमारी जीवन रेखाएं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात हो, ग्रामीण सड़क योजना की बात हो, एम0डी0आर0 की बात हो और चाहे नाबार्ड के

तहत जो सड़कें बनती हैं, उनकी बात हो। जब इन सड़कों की डी0पी0आर0 बनती है तो डी0पी0आर0 का जो टैक्निकल विंग है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, वह डी0पी0आर0 बनाते समय यह नहीं देखता,

(माननीय सभापति, श्री नरेन्द्र बरागटा पदासीन हुए)

28.03.2018/1450/जेके/वाईके/3

अभी हम जब दाड़लाघाट से बिलासपुर की ओर जाते हैं तो 12 टायर के ट्रक उस सड़क पर चलते हैं। क्या उस सड़क की लोड बियरिंग केपेसिटी 12 या 10 टन से ज्यादा सामान ढोने की है? इन चीजों का ध्यान सड़क बनाते हुए रखना चाहिए कि जहां हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं और खास करके सीमेंट इंडस्ट्रीज आती हैं तो वहां लोड बीयरिंग केपेसिटी के हिसाब से कैसी सड़क बनाई जाए? कंकरीट वाली सड़क बनाई जाए और कई जगह तो पानी वाला इलाका होता है जहां तारकोल बिछा दी जाती है और 6 महीने तारकोल बिछाने के बाद गड्ढे बन जाते हैं। दूसरा जब आप टेंडर प्रोसैस करते हैं, टेंडर प्रोसैस का बड़ा लैंथी प्रोसैस है। आप टेंडर एडवर्टिज़मैंट करते हैं, वह आपके पब्लिकेशन डिपार्टमैंट में जाएगा। डिपार्टमैंट वहां एक महीने तक भेजेगा और एक महीने के बाद पब्लिकेशन होगी। जब उसकी पब्लिकेशन होती है तो उसमें लिख दिया जाता है कि 21 दिन के भीतर आप टेंडर भरो। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा जब वे 21 दिन के अन्दर टेंडर भरते हैं फिर उसके टेंडर अप्रूवल के लिए एक महीना लगता है। फिर टैक्निकल सेंक्शन के लिए एक और महीना लगता है। जो हमारा काम करने का समय है वह बहुत कम है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि रूल्ज़ में कुछ परिवर्तन करके 21 दिन की जगह जो टेंडर डालने की प्रक्रिया है उसको 10 दिन में कर दिया जाए, क्योंकि ऑन लाइन है। ऑन लाइन में आप कोई भी टेंडर भर लें। 10 दिन के अन्दर यदि आप करोगे।....व्यवधान.... मुख्य मंत्री जी यदि आप इस मामले में करोगे तो हम सब लोग हाउस में आपके समर्थन में खड़ेंगे। आप रूल्ज़ में यह प्रोविज़न करें, मेरा यह मानना है।

28.03.2018/1455/SS-DC/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु क्रमागतः

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि अगर यह टैंडर प्रोसैस हमारा कम समय के लिए हो जाए, 21 दिन की जगह 10 दिन के लिए हो जाए, टेक्निकल सैंक्शन 10 दिन में हो जाए और अवार्ड भी 10 दिन के अंदर हो जाए तो हमें काम करने का समय ज्यादा मिल जायेगा। फिर एक टैंडर आ जाता है, अब किसी ठेकेदार की किसी अन्य ठेकेदार से नहीं बनती है, वह बोलता है कि एक या दो टैंडर हैं वह उसकी कम्पलेंट कर देता है। अगर कहीं एक टैंडर आता है और किसी क्वालिटी कंट्रैक्टर का टैंडर आता है तो उसको अधिकार देना पड़ेगा कि कौन-सा कंसर्नड ऑफिसर एक टैंडर को एप्रूव कर सकता है। फिर दोबारा से प्रोसैस स्टार्ट हो जाता है कि एक सिंगल टैंडर कैंसल किया जाए और छः महीने उसको और लग जाते हैं। इस प्रकार सड़क की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत बढ़ जाती है। 6 या 8 महीने बाद वह दोबारा टैंडर लगता है। अगर दो बार एक टैंडर आ गया तो एक साल उसमें व्यतीत हो जाता है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जहां आप अच्छी सोच के साथ सरलीकरण करेंगे कांग्रेस पार्टी आपको पूरा सहयोग करेगी।

सभापति महोदय, हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हमें टनलिंग की ओर जाना चाहिए। कहां मक डिस्पोजल होगा, कहां टनल बनेगी, इसके लिए अलग से विंग की स्थापना करने की ज़रूरत है। ब्रिटिशर्ज़ आए, उनके पास कोई इतनी ज्यादा टैक्नोलॉजी नहीं थी मगर कालका से लेकर शिमला तक उन्होंने 103 टनल्ज़ बनाईं। उस समय कहां मक डिस्पोजल होगा और किस प्रकार से उन्होंने टनल बनाई, इस दिशा में लोक निर्माण विभाग को एक विंग स्थापित करने की ज़रूरत है। पहाड़ हैं, अगर टनलिंग से डिस्टैंस कम होता है तो उसे बनाया जाना चाहिए। अगर कोई टनल एक किलोमीटर की बनती है और उससे 10 किलोमीटर डिस्टैंस शॉर्ट होता है तो उस 10 किलोमीटर को बनाने में और उसे मैंटेन करने में टनल से ज्यादा खर्चा आयेगा। टनल पर हमारा खर्च कम आयेगा। टाइम भी कम लगेगा। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि आप टनलिंग के लिए स्पैशलाइजड विंग बनाईये ताकि आने वाले समय में यह सर्वे किया जा सके कि किस क्षेत्र में हम कहां-कहां टनल बना सकते हैं। कहीं मिड हिमालय है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, कहीं बिग हिमालय है, शिमला

28.03.2018/1455/SS-DC/2

डिस्ट्रिक्ट हो गया, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहां पर बहुत अधिक टनलिंग की सम्भावनाएं हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी जिस तरह से नेशनल हाईवेज़ की डी0पी0आर0 के लिए कह रहे हैं कि 31 मार्च तक डी0पी0आर0 बनायेंगे, कंसल्टैंट एप्वाइंट करेंगे उसी तरह से अगर टनलिंग का एक विंग बनाकर एक साल के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश का सर्वे किया जायेगा तो मेरा यह मानना है कि 15-20 टनलिंग के लिए पैसा आयेगा। आपके दिल्ली में बहुत अच्छे संबंध हैं अगर आप 15-20 टनल के लिए पैसा ले आयेंगे उससे हिमाचल के लोगों के आने-जाने का डिस्टैंस कम होगा।

माननीय सभापति महोदय, अंत मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ज़रा भेदभाव की दृष्टि से कार्य न किया जाए। जो चुने हुए विधायक होते हैं उनकी बात का भी सम्मान किया जाए। यह ठीक है कि आपका जो सिराज क्षेत्र है वहां सड़कों की थोड़ी ज्यादा ज़रूरत है। देखा यह गया है कि जो भी मुख्य मंत्री महोदय बनते हैं उनके क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन विपक्ष के सदस्यों का भी थोड़ा ख्याल किया जाए। मुख्य मंत्री पथ योजना आपने स्टार्ट की है उसमें 50 करोड़ रुपया है। एलोकेशन ऑफ फंडस हो जाए कि 80 लाख या एक करोड़ नदौन को मिलेगा, इतना बिलासपुर को मिलेगा या किसी और क्षेत्र को मिलेगा तो उचित रहेगा।

नाबार्ड के तहत आप 90 करोड़ की योजनाएं लाए हैं। नाबार्ड की कौन-सी ऐसी योजना है जोकि विधायक प्राथमिकता में होती है। उसमें सैंक्शन ही नहीं मिलती। यह देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष का एम0एल0ए0 है तो उसकी सैंक्शन को थोड़ा डिले किया जाए। अब नये युवा मुख्य मंत्री बने हैं उम्मीद है कि एक समान विकास का नारा लेकर आगे बढ़ेंगे और हमारे इस तरफ बैठे विधायकों का भी ख्याल रखेंगे। सरलीकरण में हम आपके साथ हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2018/1455/SS-DC/3

सभापतिः सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, धन्यवाद। अब माननीय सदस्य, श्री नन्द लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नन्द लालः सभापति महोदय, मांग संख्याः 10 - लोक निर्माण - सड़क, पुल एवं भवन पर जो कटौती प्रस्ताव आए हैं, मैं उस चर्चा में अपने आपको शामिल करता हूं।

सभापति महोदय, ट्रांसपोर्ट जो मोड है, हमारी सड़कें जीवन रेखाएं हैं।

28.03.2018/1500/केएस/एचके/1

श्री नन्द लाल जारी----

रेलवेज़, वाटर वेज़, एअर वेज़ की हमारे यहां पर सुविधा नहीं है। सड़क पर ही सारा दारोमदार है और सड़क बनाने के लिए मैं समझता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग आज काफी ऊपर की श्रेणी में है। जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रिब्यूशन है। जैसे ठाकुर राम लाल जी ने ज़िक्र किया, डॉ0 वाई.एस. परमार जी से लेकर माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी तक और अब वर्तमान में ठाकुर जय राम जी के, सड़कों को बनाने में, इस प्रदेश को आगे पहुंचाने में, कनैक्टिविटी जोड़ने में सभी के प्रयास रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमको यह भी देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? अगर आप रोड़ज़ का पूरा हुलिया देखेंगें, जितने काम 2017-18 के वित्तीय वर्ष में हुए हैं, हम तो धन्यवाद करना चाहेंगें पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का। मैं आपको डाटा पढ़कर सुनाता हूं। सड़क का जहां तक सवाल है, 2017-18 के लिए जो टारगेट फिक्स किया था, वह मैं आपको एक-एक कर बताना चाहता हूं। मोटरेबल रोड़ का 2017-18 का 380 किलोमीटर का टारगेट था जबकि अचीव किया गया 471 किलोमीटर that to till December 2016-2017. इसी तरह से क्रॉस ड्रेनेज़ बननी थी, इसके लिए 520 किलोमीटर का टारगेट था, 701 किलोमीटर

दिसम्बर, 2017 में पूरा हो गया। मैटलिंग और टारिंग का 500 किलोमीटर का टारगेट था दिसम्बर, 2017 तक 1246 किलोमीटर टारगेट अचीव किया गया । बृजिज़ 30 बनने थे और सरकार ने 64 दिसम्बर तक कम्पलीट किए। विलेज कनैक्टिविटी में भी बहुत योगदान रहा। तो हम यह कहना चाहेंगें कि हमको इस डवैल्पमैंट में जो रोल जिसने किया हो, जैसे किया हो, उसका आदर करना चाहिए।

सभापति महोदय, इस तरह की सोच के साथ अभी बजट पेश किया गया और बजट भाषण में डैरोगेटरी लैंग्वेज़ का इस्तेमाल किया सरकार के लोगों ने। बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिससे मन दुखी हो जाता है। आज नेशनल हाइवेज़ का हिमाचल में एक बड़ा चैलेंज है जिस बारे में सुबह से चर्चा हो रही है। सिंपल सी बात है it is just an Election stunt. सत्ता पक्ष की तरफ से लोग कह रहे थे कि इलैक्शन स्टंट मत कहिए। इलैक्शन स्टंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी भी 69 National Highway in one go

28.03.2018/1500/केएस/एचके/2

to be sanctioned to a particular State, वह भी सिर्फ इलैक्शन के दौरान और साऊथ में भी कहीं इस तरह से हुआ है। वह खाली इलैक्शन स्टंट है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसमें जो डी.पी.आर. की बात कर रहे हैं, इस तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं और आज तो इन्होंने एक बहुत बड़ी कमिटमैंट कर दी he want to show us a sea change in four years. I don't know what is going to happen? हम पूरी तरह से केन्द्र सरकार पर निर्भर है। अब बताइए 65 हजार करोड़ रुपये का जो ये हिसाब-किताब ले कर वहां जा रहे हैं, जैसे किसी और सदस्य ने भी कहा है कि वहां से जून-जुलाई तक ले लो जो भी मिलता है। Rs. 65,000 crores is a huge amount, जितना भी अमाउंट सड़कों के लिए मिलता है, वह ले लिया जाए ।उसके बाद वहां से भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कर्नल इन्द्र सिंह जी, मैं यह कह रहा हूं कि जो भी

करना है It has to be done before June-July this year . उसके बाद वहां भी दिक्कत आ जाएगी। अच्छी बात है। आपको नेशनल हाइवेज़ बनाने हैं इनको आप आगे बढ़ा रहे हैं यह अच्छी बात है। आज एक चीज़ ओर देखने में आ रही है कि हमारी जो चालू सड़कें हैं, उनमें कुछ जगह पर उस तरफ की पार्टी के लोगों का हस्तक्षेप है और उनके काम बन्द किए जा रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जो चलते हुए काम हैं, उनको एक्सपीडाइट किया जाए उसमें कोई राजनीति की बात न हो।

28.3.2018/1505/av/hk/1

श्री नन्द लाल जारी

मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र, रामपुर में सड़कों का बहुत काम चला हुआ है जिसमें टारिंग/मैटलिंग और रोड कनस्ट्रक्शन इत्यादि कार्य शामिल हैं। वहां कई जगह इंटरफेयरैंस की वजह से काम में बाधा आ रही है। सरकार इस ओर ध्यान दें ताकि हमारे काम न रुक पायें। रामपुर में एक बाई पास की बात हुई, वहां पर बजीर बावड़ी से लेकर नया बस स्टैंड के आगे एक पुल बनना था। उस पुल के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थी। हमने उसका स्टेटस जानने के लिए एक सवाल भी किया था जिसके जवाब में यह लिखा गया कि फंड उपलब्ध नहीं है।। think Department is not aware. The decision taken was that एस0जे0वी0एन0एल0 ने इसके लिए फंड प्रोवाइड करने है। इसमें डी0पी0आर0 इत्यादि सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर दी थी। उनसे इसको टेकअप किया जाए ताकि उस पुल का निर्माण हो जाए। रामपुर के अंदर वर्तमान में बहुत ज्यादा कन्जैशन है और यह एक छोटा सा शहर है। वहां नोगली से लेकर खनेरी तक पूरी सड़क जाम होने की कगार पर है इसलिए मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि उस पुल का जल्दी-से-जल्दी निर्माण किया जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काशापाट रोड के बारे में मुझे लगता है कि कोई भी विधान सभा का सत्र या प्लानिंग की

मीटिंग ऐसी नहीं गई होगी जिसमें इस सड़क का जिक्र न हुआ हो। पिछले 4-5 सालों में उसमें रॉक को काटकर बहुत ज्यादा काम हुआ है लेकिन अब उसको अचानक बंद कर दिया गया है। हमने जब यहां पर सवाल लगाया तो आजकल उसका काम फिर से शुरू कर दिया है। उसमें केवल सौ मीटर का पैच है और यह काफी हार्ड रॉक है। उसके आगे को भी सड़क बनी हुई है। इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इस सौ मीटर के पैच को जल्दी तैयार करवाया जाए क्योंकि आज भी वहां लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहां जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है इसलिए मेरा लोक निर्माण विभाग से आग्रह रहेगा कि कम-से-कम वहां पर पैदल चलने का रास्ता बना दिया जाए। वहां रॉक को काटकर कुछ स्टैप्स बनाये जाएं क्योंकि वहां से लोग पैदल चलते हैं। पन्द्रह-बीश, नंती-टिक्कर, फांचा के आगे उसमें पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़क है जिस पर

28.3.2018/1505/av/hk/2

वर्तमान में कोई काम नहीं हो रहा है, इस कार्य को भी ऐक्सपिडाइट किया जाए। ज्वाल्डा-दनेव्ठी, चैब्डी सड़क ननखड़ी में पड़ती हैं। इस सड़क पर कुछ काम करने के बाद इसको छोड़ दिया है। चिलाडी से दरशाल-बठेड़ा, बतूना for clearances everything has been done. लेकिन इसके लिए जो भी औपचारिकताएं बची हैं उनको सरकार पूरा करे। इस सड़क के बनने से हमें रामपुर जाने के लिए लगभग 10 किलो मीटर का फर्क पड़ेगा। यहां पर तकरीबन सभी माननीय सदस्यों ने मशीनरी और एक्विपमैंट की बात की है और यह सही बात है। वहां पर बुल्डोजर मिले हैं तो वह सड़क पर खड़े हैं। हमारे काशापाट रोड के लिए पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने आर0ओ0सी0 मशीन पहुंचाई थी लेकिन उसके पुर्जे टूटने के कारण अब वह खड़ी पड़ी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर डिविजन के अंदर नई मशीनें प्रोवाइड की जाए ताकि मशीनों की कमी की वजह से कोई काम न रुके। यहां पर जैसे माननीय सदस्य राम लाल ठाकुर जी ने कहा कि हमारे यहां तकरीबन सभी बेलदार रिटायर हो गये हैं। हमारा इसके लिए आग्रह रहेगा कि वे लोग ऐनरोल किए जाएं ताकि वहां पर जो

डिविजन की पर्टिकुलर सेक्शन है वह जिन्दा रहे और उसमें कुछ ऐक्टिविटीज चलती रहें। इसके अतिरिक्त, मैं यह कहना चाहता हूं कि एम0एल0ए0 की नाबार्ड की जो किटी होती है जिसमें आई0पी0एच0 और पी0डब्ल्यू0डी0 की स्कीम्ज जाती हैं वह 80 करोड़ रुपये की किटी लगभग सभी विधायकों की ऐग्जोस्ट हो चुकी है। इस बजट में उसके लिए 10 करोड़ रुपये की ऐडिशन की गई है जो कि अब 90 करोड़ रुपये हो गई है। अब जैसे हम लोग लगभग 80 करोड़ रुपये तक पहुंच चुके हैं तो आने वाले समय में क्या are we left with Rs. 10 crores only? मेरी जानकारी के अनुसार यह किटी वर्ष 2022 तक है अतः माननीय मुख्य मंत्री इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें ताकि हमारी स्कीम नाबार्ड में जाएं और उसका काम पूरा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2018/1510/TCV/YK-1

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिलः माननीय सभापति महोदय, मैं माग संख्याः10 'सड़क, पुल एवं भवन' कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये विषय जनहित से जुड़ा हुआ है और इस माननीय सदन में इस पर चर्चा चल रही है। सभी माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। इस क्षेत्र में, खासकर हमारी इस देवभूमि में, हिमाचल निर्माण डॉ0 वाई0एस0 परमार के शब्दों में मुझे याद है, वे कहा करते थे कि सड़कें हमारी जीवन रेखा है। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी भी कहते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कैसे इतनी सड़कें बन जाएगी। परन्तु आज ये सड़कें बनी है। इसमें सभी माननीय सदस्यों और लोगों का योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि कुछेक चीजें ऐसी होती है, जिन पर सबको एक मत होना चाहिए और सड़क एक ऐसा विषय है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में ज्यादा कहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सोलन और कण्डाघाट में 2 ब्लॉक हैं। इन दोनों ही ब्लॉकों में सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा हैं। इनमें अभी तक अच्छे काम हुए हैं। परन्तु कुछेक ऐसे काम है

जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक 3 बैडिड कम्युनिटी हैल्थ सैंटर, सायरी है, जो 5 करोड़ 75 लाख रुपये से बन रहा है। इसका कार्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। परन्तु पिछले दिनों से इसके कार्य में कुछ ढ़ील आई है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाये। क्योंकि इस कम्युनिटी हैल्थ सैंटर का पूरा होना बहुत अनिवार्य है। वहीं पर एक पी0डब्ल्यू0डी0 रेस्ट हाउस भी है जो एक करोड़ 10 लाख से बन रहा है। इसका निर्माण कार्य भी चला हुआ है but flow of fund is very weak. उनको कुछेक धनराशि गई है, लेकिन इसके लिए और ज्यादा धनराशि की जरूरत है। यदि उन्हें एक करोड़ 10 लाख रुपये में से 10-10 लाख रुपये देते रहे तो उनका काम धीरे-धीरे चलेगा। इसलिए आने वाले वित्तीय वर्ष में उन्हें एकमुश्त् धनराशि दे दी जानी चाहिए। इसी प्रकार एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग कण्डाघाट में है और चम्बाघाट में सर्कट हॉउस का निर्माण कार्य चला हुआ है। ये विषय मैंने पहले भी माननीय मुख्य मंत्री जी से उठाया था कि ये जनहित से जुड़ी हुई

28.03.2018/1510/TCV/HK-2

चीजें हैं। इन पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए that the hospital building is needed for the welfare of the people. अगर वहां का (सोलन) प्रैशर कम करना है तो कंडाघाट की बिल्डिंग बनना आवश्यक है और यह जितनी जल्दी बनेगी, उससे रिजनल हॉस्पिटल सोलन का प्रैशर कम होगा। इसी तरह से नौणी की तरफ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, अगर वह जल्दी होंगे, तो उससे भी सोलन के हॉस्पिटल पर प्रैशर कम होगा। मेरा सर्कट हाउस के पीछे भी यही आश्य है, वहां पर आने वाले गैस्ट्स या पदाधिकारियों/नेताओं को ठहरना पड़ता है, इसलिए हमें वहां पर सर्कट हाउस बनाना पड़ा। शिमला में भी सर्कट हाउस इसी आश्य से बन रहा है। जिसमें लगभग 105 कमरे

बनेंगे। हमें इन पर इसलिए ज्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि ये जनहित और हमारी आगे की एक्टिविटी से संबंधित है। एक आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शारड़ा घाट में है।

28-03-2018/1515/NS/YK/1

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल -----जारी।

हमारी आयुर्वेदिक पद्धति बहुत लोकप्रिय है। इसलिये हमें इसमें कभी भी ढील नहीं करनी चाहिए और the file is with the Director Ayurveda and may kindly be cleared soon. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कुछेक छोटी-छोटी चीजें हैं जैसे इन्डोर स्टेडियम आदि, इनके लिए कुछ धनराशि जानी है। I think 10 lakh or something is lying there and when I see Para-16 of the Budget book इसमें बड़ी अच्छी तरह से कहा गया है कि execution of public work in time is of paramount importance यह बहुत अच्छा पग दिया गया है लेकिन इसे फॉलो करना जरूरी है। मैं कुछ फोर लेनिंग पर प्वाईंट देना चाहूंगा , फोर लेनिंग की जितनी भी मीटिंग्ज़ हुई हैं, उनमें से आधा दर्ज़न मैंने स्वयं अटैंड की हैं with Army Authorities, with the Station Commandant , with Regiment Commandant that is 9 Dogra Regiment in Solan. फोर लेनिंग के तकरीबन सारे मुद्दे तय कर दिये गये हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि कुछेक चीजें रह गई हैं जैसे सर्विस लेन्ज़। हमारे कृषक और बागवान किस प्रकार से अपनी जगह को जा सकें, घासनीयों को जा सकें और स्टूडैंट्स वहां से कैसे स्कूल और कालेजों के लिए निकलें? इस तरह की कुछ बातें या ईश्यूज़ रही हैं, जो अभी भी unresolved हैं। They must be attended. एक इसी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जब फोर लेनिंग पूरी हो जायेगी तो हमारे लोगों के लिए जो यहां पर विस्तार होगा, उनके लिए छोटी-छोटी ओद्यौगिक इकाईयां कैसे समअप होंगी? इनका भी अभी से ध्यान रखा जाये तो ये समस्यायें बाद में नहीं आयेंगी क्योंकि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है वह safety of the road पहाड़ों में जब हम रात को जाते हैं तो मान लो कि हम त्यूणी से जुब्बल-कोटखाई की तरफ आ रहे हैं, मैंने देखा कि रात को suddenly you feel there is a gorge and you can fall क्योंकि इसके साथ हमारी सुरक्षा दीवार और गार्ड

भी नहीं है। मेरा मानना है कि मेरा पहला सुझाव यह होगा कि हम रोड की सेफ्टी की तरफ ध्यान दें। यही चीज़ मैं समझता हूं कि जब फोर लेनिंग होती है और उसमें से जो सब-वेज़ निकलते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाये। गांव की रोडज़ बहुत अच्छी बनी हैं, कच्ची हैं लेकिन मैंटेनैंस को कोई फंड नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें रोड मैंटेनैंस की तरफ कुछ फंड जरूर देना चाहिए। हम क्यों न अपने अच्छे ट्रेंड लेबरर्ज रखें। हमारे माननीय ठाकुर राम लाल जी और माननीय नन्द लाल जी ने भी यह बात कही है कि कुछेक लोग जो ईमानदार होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। हमारे

28-03-2018/1515/NS/YK/2

पुराने जो लेबरर्ज़ हैं, वे अच्छे हैं। हम इनको मोटीवेट करके गांव के जो लोग काम करना चाहते हैं तो हम उनको ट्रेंड करें और एक reservoir of manpower बनायें तो मेरा मानना है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए and it should be put on Superintendent Engineer (SE) or Engineer-In-Chief, or even a independent wing can be made to see that how we are executing that work, कुछ-न-कुछ तो इसके ऊपर अंकुश होना चाहिए। अदवाईज़ क्या होता है कि हम वहां पर छोड़ देते हैं कि एस0ई0 देख लेंगे और उसके बाद एक्स0ई0एन0 देख लेंगे। There should be some independent body to observe and oversee their functioning and work. मैं यह भी कहूंगा कि वे अच्छा काम करते हैं। वे चाहे हमारे ठेकेदार हों या पदाधिकारी हों, उनको सम्मानित भी करना चाहिए ताकि अच्छा काम हो। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछेक चीजें सोलन ब्लॉक की बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक कोठीदयोरा स्कूल है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इसका काम काफी स्लो हो रहा है। मैंने इसके लिए 3.47 करोड़ रुपये की राशि स्वयं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री था, तब दिये थे। इसका फंड बिल्कुल ठीक गया है, परन्तु काम बहुत स्लो हो रहा है। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र का एक कोटकडोर स्कूल है, उस पर भी काम बहुत स्लो हुआ है। शामती बायपास लगभग 25 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, पैसे पूरे दिये जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, ये अभी लगभग एक या दो छोटे-छोटे ईश्यूज़ हैं लेकिन

28.03.2018/1520/RKS/AG-1

डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल... जारी

अगर यह बाईपास ज्वाइन हो जाता है तो हमारे सोलन के ऊपर पार्किंग या ट्रांसपोर्टेशन्ज का जितना भी प्रैशर है, वह काफी हद तक ठीक हो जाएगा। एक श्रीमान् जी हैं जिनका थोड़ा-सा लैंड इस बाईपास में आया था परन्तु उसे भी ठीक कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि उन्हें भी हम स्वयं जाकर पूछ लेंगे। जितने जल्दी इस इश्यू को हल कर दिया जाए उतने ही जल्दी हमारा शामती बाईपास थ्रू हो जाएगा। इसके साथ एक जाबली घाटी-नदीमू रोड है और काकड़ा-चपला-बढानाघाट- हरिपुर-भलयाणा रोड है। इसे भी आप पूरा कर देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी काफी समस्या हल हो जाएगी। वैसे तो रोड्स की संख्या बहुत ज्यादा है। परन्तु जो मैंने स्वयं देखा है, शिमला-कुनिहार-रामशहर-नालागढ़ रोड की बुरी हालत है। इस रोड को रिटारिंग करना होगा। Should there be any emergency on this sector? It is also a defence road. फाइनली मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे श्रम से हमेशा निर्माण की सुगन्ध आती है। ये जो हम सड़कों पर श्रम कर रहे हैं, इन लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जाए। इन्हें मोटिवेट किया जाए, इन्हें सम्मानित किया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारी सड़कों का कार्य अच्छा होगा। अंत में, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जरूर कहना चाहूंगा कि हमें हमारे गांव की सड़कों में भी पूरा ध्यान देना चाहिए। रोड मैंटिनैंस के लिए कुछ-न-कुछ फंड अवश्य लागू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2018/1520/RKS/AG-2

सभापतिः अब माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघाः सभापति महोदय, मैं मांग संख्याः10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं

भवन पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसान की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे सड़कों का नेटवर्क, उसका रख-रखाव और उसकी क्वालिटी क्या होगी? जितना नेटवर्क वाइडस्प्रेड होगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था उतनी ही आगे जाएगी। यह सच्चाई है कि जो हमारे राज्य सरकार की तिजोरी है, उसमें ज्यादा धन नहीं बचा है। इसलिए बहुत आशा भी नहीं की जा सकती है कि आने वाले समय में सड़कों का जाल या सड़कों का निर्माण हो। यह हकीकत है। जो हमारा तुजुर्बा है, अगर किसी सड़क का निर्माण समय पर हुआ हो तो वह, वे सड़क है जो पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत बन रही है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जो इसमें बाधाएं हैं उन बाधाओं को हटाने का काम करना चाहिए। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी के माननीय मोदी जी से अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए इनसे हम यह उम्मीद करते हैं कि जो भी बाधाएं होगी उनको ये जल्द-से-जल्द दूर करें ताकि हिमाचल प्रदेश का विकास हो सके। पहली बाधा कोर नेटवर्क की है जो पी.एम.जी.एस.वाई. ने निर्धारित किया है। यह वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर है। यह नेटवर्क आउटडेटिड हो गया है। अगर कुछ नया करना है तो इस कोर नेटवर्क को तब्दील कर नया नेटवर्क तैयार किया जाए जोकि हिमाचल प्रदेश की जनता और इस प्रदेश को मदद दे सकता है। मैं यह समझता हूं यह पहला बैरियर है। दूसरा, बैरियर इंडियन फॉरैस्ट एक्ट-1927 का है। जिसके तहत सन् 1952 में यह तय हुआ कि गैर- दरख्तान भूमि भी फोरैस्ट भूमि होगी।

28.03.2018/1525/बी0एस0/ए0जी0-1

श्री राकेश सिंघा .....जारी

यह दूसरी बड़ी बाधा है । जब तक हम इस बाधा को नहीं हटाएंगे तब तक यह बाधा हमारे कार्यों को नहीं होने देगी। इस बाधा का कोई हल नहीं हो सकता। इसी में 1952 का गैर दरख्तान भूमि जो हमने वन में तबदील की यह 1980 में भी शामिल की गई, जो

Forest Conservation act है, हालांकि सरकार की 1952 की नोटिफिकेशन है, परंतु Forest Conservation act में शामिल हो गई, इसलिए यह बाधा बनी है और इसको दूर करने का काम भी हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी कर सकते । आप देखेंगे कि 1927 का फोरेस्ट एक्ट आउटडेटिड है यह उस समय के बनाया गया था। जो नया फोरेस्ट एक्ट प्रपोजल भारत सरकार कर रही है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जा रही है अब तो यह अनुमति दे रही है कि अब जगंलों में बड़े-बड़े कॉरपरेट घरानों को भी काम करने की अनुमति दे रही है। तो इसलिए जो सड़कों के लिए हिमाचल प्रदेश में जो जंगल बाधा बन गया है इसको हटाने का काम करने की आज की तारीख में जरूरत है। क्योंकि इससे हिमाचल की जनता और हिमाचल प्रदेश की सड़कें बहुत बड़ा शिकार बन गई हैं। दूसरी बात मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो खसतौर पर जिस चुनाव क्षेत्र से चुनकर आया हूं, बहुत सी सड़कें जन सहयोग के तहत बनी हैं जिसको मुख्यतः 30/70 कहा जाता है। इसमें लोगों का पैसा लगा है। लेकिन इन सड़कों का आज कोई भी ऑनर नहीं है और मैं समझता हूं कि इन सड़कों को भी वन टाइम का इग्जेम्शन मिलना चाहिए। जैसे कुछ सड़कों की इग्जेम्शन माननीय हाईकोर्ट ने दी कि जहां पर वाईलेशन हो गई थी, तो इन्हें भी वन टाइम इग्जेम्शन मिलनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर सोच-विचार कर सकते हैं और यह संभव है और माननीय कोर्ट से भी आग्रह किया जा सकता है, जिससे की ये सड़कें लोक निर्माण विभाग के अधीन आ सके क्योंकि इन सड़कों पर न एल.पी.जी. की गाड़ी जा सकती है,

28.03.2018/1525/बी0एस0/ए0जी0-2

न एंबुलैंस जा सकती है और दुभाग्यपूर्ण कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें बीमा कवर भी नहीं मिलता है। इसलिए इन सड़को का माई-बाप तय करना होगा कि इसका माई-बाप कौन बने। कुछ हमारी और भी लावारिश सड़कें हैं जिसका ओनर्शिप आज किसी के पास नहीं है। यह जो पुरानी हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क है, यह बहुत से गांव को फीड करती है लेकिन इसका रख-रखाव आज कोई नहीं कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूं

लोक निर्माण विभाग को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। दूसरी किस्म की ऐसी सड़के हैं जो हमारे फोरेस्ट रोड के नाम से मानी जाती है, कहलाई जाती है जो जंगलों के अंदर है। अंग्रेजों के टाइम में इसमें डाकबंग्लों हुआ करते थे । इन सड़कों को भी लोक निर्माण विभाग को अपने अधीन लेना चाहिए। जिससे की इनका रख-रखवा हो सके और लोगों को भी इससे ममद मिल सकती है।

एक बात से मैं सहम हूं जो यहां पर माननीय नेगी जी ने उठाई। सड़कों के किनारे जो पैराफिट लगाए जाते हैं उनका आज क्या मतलब है? ये जो पैराफिट लगाए जाते हैं मैं समझता हूं कहीं न कही ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए यह कार्य किया जाता है। वह किसी भी तरह से न रोड़ का इंडिकेशन दे सकता है न किसी भी हालत में दुर्घटना के समय मदद दे सकता है, इसलिए यह बंद हो जाने चाहिए। इसलिए नीति बन जानी चाहिए, आज की तारीख में क्रॉस बेरियर ही होना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सी सड़कों में अभी भी आप पैरफिट लगा रहे हैं और अगली साल उसे तोड़कर वहां क्रॉस बेरियर लगा रहे हैं। मैं समझता हूं जनता के पैसा का दुरूपयोग है। इस पर मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का यह विभाग है और ये इस पर अवश्य रोक लगाएंगे।

28.03.2018/1530/डी0टी0/ऐ0जी0-1

श्री राकेश सिंघा .....जारी

दूसरा एरिया जहां करप्शन चलती है, नेगी जी की बात से मैं सहमत हूं कि बर्फ को साफ करने का एरिया है। यह रिकार्ड कहीं नहीं होता है। जिस ठेकेदार को फेवर करना है उसे कार्य दे दिया जाता है। जहां बर्फ पड़ी भी नहीं है वहां पर कलियरेंस के लिए लगा दिया जाता है। यह आपको चैक करना है और मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, मैं नहीं कह सकता। इस साल तो बर्फ कम पड़ी है लेकिन पिछला अगर आप रिकार्ड उठाएंगे तो इस तरह का कार्य पाएंगे जिसमें बर्फ साफ करने के नाम पर ऐसा कार्य होता है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कल भी यह चर्चा हुई थी, मैं समझता हूं कल की चर्चा से जो एक्सपर्ट आए थे, पानी के कनजर्वेशन के लिए डा0

राजेन्द्र सिंह जी, मैं समझता हूं कहीं न कहीं बरसात का पानी है या जब भी बारिश होती है वह सड़कों पर बहुत बहता है और सरकार ने ड्रेनेज का सही कदम उठाया है, लेकिन कलवट के एंड पर अगर वहां पर हम टैंक सिस्टम कर सकते हैं तो वह पानी हम खेती कि लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी अगर लोक निर्माण विभाग अगर जिम्मेवारी ले तो अच्छा रहेगा। अखिर बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ठेकेदार काम इतनी धीमी गति से करते हैं। यह क्रिमिनल ऑफेंस है। इनके खिलाफ कोई कानून होना चाहिए क्योंकि जो कार्य छः महीने में होना है उसे करने में 6 साल लगा देते हैं। उसका कॉस्ट बढ़ जाता है पब्लिक मनी का कोई कोस्टेटिव नहीं बनना चाहता है। इसलिए ऐसे- ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो मजदूर उस पर कार्य कर रहे हैं सुप्रिम कोर्ट के कुछ आदेश आए हैं उसके बारे में भी आपको सोचना है कि किस तरीके से उनका जो पेंशन के बारे में प्रश्न है उसका किस तरीके से समाधान निकालते हैं। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

28.03.2018/1530/डी0टी0/ऐ0जी0-2

सभापतिः अब मैं आग्रह करने जा रहा हूं माननीय सदस्य पवन कुमार काजल जी से।

श्री पवन काजल : सभापति महोदय, मांग संख्या -10 पुल, सड़क एवं भवन के कटौती प्रस्ताव पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मेरे से पूर्व वक्ता सिंघा जी ने जो बात कही कि जो हमारे प्रदेश में पी.एम.जी.एस.वाई. की जो सड़के बनी वह प्रदेश के दूसरे कार्यो की तुलना में बहुत बढ़िया बनी है। सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये जो पी.एम.जी.एस.वाई. सड़के बनती हैं, इसके लिए जो सीमेंट हो या स्टील हो ठेकेदार अपना लगाता है। मेरा सुझाव रहेगा कि जो हमारे लोक निर्माण विभाग के स्टोर हैं सीमेंट हम देते हैं लेकिन मेरा यहां यह सुझाव है कि जब

लोक निर्माण विभाग जक नए टैंडर करेंगे तो सीमेंट भी क्या ठेकेदार अपना लगाएगा? ऐसा कोई प्रावधान सरकार करेंगी? आप चोरी की बात कर रहे हैं चोर तो हम खुद बना रहे हैं । एक तरफ से हम पी.एम.जी.एस.वाई. में एलो कर रहे हैं कि सीमेंट ठेकेदार अपना लगाएगा, दूसरी तरफ जो ठेकेदार हैं जो स्टेट हाईवे का टैंडर लेगा या बिल्डिंग का कार्य लेगा, उसमें सिमेंट बचाएगा और दूसरे स्थान पर पी.एम.जी.एस.वाई.के कार्यों पर लगाएगा। हमें इसमें मंथन करने की जरूरत है। सीमेंट की बोरी का रंग हरा होता है या उसमें सीमेंट का रंग ही अलग कर दो तब इसमें चोरी रूक सकती है। सच्चाई मैं बोल रहा हूं। होता क्या है कि लोक निर्माण विभाग में जब सीमेंट जाता है, कई बार तो आता ही नहीं है, कई बार जब अनलोडिंग करते हैं उसके लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है फिर दोबारा जब सीमेंट जाता है उसके लिए पैसा दे रहे हैं। सभपति महोदय, आने वाले समय में सोचना पड़ेगा कि जितने भी टैंडर हो चाहे स्टील हो, पहले जमाना था कि जिस भी दुकानदार से आप सीमेंट का बिल लेना चाहो दे देता था ।

28.03.2018/1535/SLS-HK-1

श्री पवन कुमार काजल ...जारी

अब यह मेरी समझ से बाहर है कि आप ठेकेदार को सीमेंट भी अलौ करें।

दूसरे अगर किसी भी कंट्रैक्टर को आपने टैंडर देना है, चाहे वह बिल्डिंग का है या सड़क का है, वह जस्टिफिकेशन के हिसाब से दें। वही सही टैंडर होता है। लेकिन जब उसमें नैगोशियेशन करते हैं कि यह टैंडर केवल इतने रुपये का ही हो, उससे ज्यादा न हो, तो उस नैगोशियेशन से हम बड़े खुश होते हैं कि हमने पैसा कम करा लिया। लेकिन अगर हम ठेकेदार को जस्टिफिकेशन के हिसाब से रेट देंगे तो वह अच्छा काम करेगा। होता क्या है? जैसे एक भवन का काम है। मान लो, हम 5.00 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनाते हैं और मान लो कि उसमें कंक्रीट वर्क भी ठीक होता है, स्टील भी ठीक लगती है, लेकिन ठेकेदार क्या करता है कि जब आप नैगोशियेशन करते हैं तो उसमें जो थोड़ा-सा पैसा कम किया होता है उसको एडजस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि लोक निर्माण

विभाग अच्छा काम नहीं करता है, विभाग बढ़िया काम करता है। इस प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की चाहे सड़कें हों या पुल हों या भवन हों, उनसे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो हम 5.00 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बना देते हैं, उसमें होता क्या है कि जो कंट्रैक्टर है उसके लिए जब बाथरूम बनाने की बात आती है और वह उसमें जब पाईप्स की डिनिट (DNIT) बनाता है, उसमें गड़बड़ होती है। इसलिए डिनिट (DNIT) में हम पहले ही कंडिशन लगाएं। विभाग उसमें पाईप जो लेता था वह तो जी.आई. पाईप होती थी। अब तो हमने कटक पाईप शुरू की है। वह बड़ा अच्छा सुझाव है। लेकिन जो हम जी.आई. की पाईप लेते थे उसमें 'ए' क्लास की वार्निंग लिखी जानी चाहिए। जैसे कि पीले पटे वाली पाईप हल्की होती है, नीले पटे वाली उससे हल्की होती है, इसलिए क्यों न हम रैड पाईप लगाएं। जब हम टैंडर में मैंशन करेंगे तभी वह लगेगी।

दूसरी बात है कि एक बाथरूम में लगाने के लिए एक यूनियन 20 रुपये में आता है या एलबो 20 रुपये में आता है जबकि बढ़िया किसम का 50 रुपये में आता है। मान लो, एक बाथरूम के लिए 4 एलबो और 4 यूनियन लगते हैं। कंट्रैक्ट में होता क्या है? कंट्रैक्टर अपने 400 रुपये बचाने के पीछे पूरी बिल्डिंग का बेड़ा गर्क कर देता है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में आप कहीं भी चले जाओ, शानदार बिल्डिंगें बनी हैं। लेकिन बाथरूम की लीकेज की वजह से सारे काम का सत्यानाश हो जाता है।

28.03.2018/1535/SLS-HK-2

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि हम पहले डिनिट (DNIT) में मैंशन करें कि अगर हमने रविन्द्रा की पाईप लगानी है तो उसमें रविन्द्रा का ही यूनियन हो और उसी का एलबो हो। ऐसा न होने के कारण आप देखते होंगे कि प्रदेश में जितनी भी बिल्डिंग्ज बनी हैं वह हमें 10 सालों के बाद रिपेयर करनी पड़ती हैं क्योंकि उनका बाथरूम खराब हो जाता है। बाथरूम में टाईल अच्छी लगी है, प्लस्तर अच्छा हुआ है लेकिन जो यूनियन लगा है या जो एलबो लगा है, उसमें जो 5-10 रुपये की बचत के लिए नैगोशियेशन की गई, उसकी वजह से भवन का सत्यानाश हो जाता है।

दूसरी बात स्टील की है। हम स्टील का ऑर्डर देते हैं और स्टील स्टोर में आता

है। जब यह ऑर्डर पर आता है तो के.जी. के हिसाब से आता है, क्विंटल के हिसाब से आता है लेकिन जब स्टोर से जाता है तो नपाई के हिसाब से जाता है। कट्रैक्टर की सोच यह होती है कि ऑर्डर पर आया है, पूरा होगा या नहीं होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें भी देखने की बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जब हम सरलीकरण की बात कर रहे हैं तो जो स्टील और सीमेंट हैं, उसको भी अलौ कर दिया जाए और उसी हिसाब से टैंडरिंग की जाए। इसी तरह मैं बिचुमन और टारिंग की बात करना चाहूंगा। हम टारिंग करते हैं यह बात ठीक है। सभापति महोदय, इस बार टारिंग का सबके लिए 25-25, 28-28 किलोमीटर के टारगेट थे और अच्छी टारिंग हो गई। पर जब हम टारिंग करेंगे, तो टारिंग उस जगह में क्यों हो जहां पर पानी गिरता हो। क्यों हम वहां पर कंक्रीट नहीं कर सकते? हम देखते हैं कि अभी 3 महीने हुए और टारिंग उखड़ गई। जब टारिंग करेंगे और वहां अगर पानी आएगा तो टारिंग तो उखड़ेगी ही।

मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि गर्म मौसम में, जैसे कि अप्रैल और मई में जितनी टारिंग होगी वह मेरे हिसाब से उखड़ेगी नहीं। कई जगह डिविजनों में ऐसा होता है कि जब टारिंग सीजन होता है तो टैंडर नहीं होते और जब टैंडर होते हैं तो टारिंग सीजन चला जाता है। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े। मैं एक और छोटी-सी बात कहना चाहूंगा कि जैसे हम टारिंग करते हैं और कहीं किलोमीटर के बीच में कोई गड्ढा पड़ जाता है, अगर गड्ढा पड़ गया तो आजकल हमारे विभाग के पास उस पैचवर्क के लिए अपनी लेबर ही नहीं है। उस एक गड्ढे के लिए पैचवर्क का टैंडर लगाना पड़ता है।

28/03/2018/1540/RG/HK/1

श्री पवन कुमार काजल--------जारी

अगर तीन खड्डे हैं तो उसके लिए टैण्डर लगाना पड़ता है। इसलिए आपके विभाग के पास काम करने वाले हों, आपके पास अपनी लेबर हो। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आजकल झाड़ियां काटने के लिए टैण्डर लग रहे हैं। अगर हमारा कर्मचारी होगा, तो झाड़ियां काटने का 2,000/-रुपये लगेगा, लेकिन टैण्डर आपको लाख रुपये का लगाना पड़ेगा। तो इस सारे विषय पर हमें मन्थन करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, अब मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में बोलना चाहूंगा। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से योजना की बैठक में भी बात की थी और यह बहुत हैरानी की भी बात है कि जब मैं वर्ष 2012 में नया-नया विधायक बना था, तो कांगड़ा से स्कॉट को जोड़ने वाला पुल था और वह दो विधान सभा चुनाव क्षेत्रों को जोड़ने वाला पुल है जो कांगड़ा और नगरोटा को जोड़ता है। वहां पांच करोड़ का पुल बनकर तैयार हुए सात सात हो गए हैं। मैंने 12 बार उस पुल के बारे में इस सदन में प्रश्न किया। मुझे उसका एक ही उत्तर मिला कि 'रेलवे विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के तदोपरान्त कार्य आरम्भ होगा।' तो 12 बार मैंने प्रश्न किया और 12 बार आपने यही उत्तर दे दिया। वहां कौन जाएगा? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जाएंगे या विधायक जाएंगे?----(घण्टी)----मैं कहना चाहूंगा कि वह पुल बनकर तैयार है, वहां आर.ओ.बी. बनना है। ठीक है कि रेलवे विभाग से जल्दी अनुमति नहीं मिलती, लेकिन सात साल पहले की बात है और मैंने 12 बार इस प्रश्न को यहां उठाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से इस पर संरक्षण चाहता हूं कि इस बारे में आप कृपया सोचें।

सभापति महोदय, मैंने योजना की बैठक में कहा था कि सलोल स्कूल का भवन पिछले पांच वर्षों से बन रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बिना अनुभव के ही कोई ठेकेदार काम ले लेता है। बड़ी मुश्किल से वहां बिल्डिंग तैयार हो गई। एक विधायक होने के नाते मैंने विभाग को भी कहा और कोई पचास फोन भी किए कि इसको जल्दी करो। यदि इस ठेकेदार से काम नहीं होता, तो इसको रिसींड करो। फिर इसको रिसींड कर दिया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि काम को रिसींड करके दूसरी बार इसका टैण्डर उसके बेटे को दे दिया। हम क्या करें? हम आपके आगे नहीं चल सकते। इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हम वहां चले गए और एक बार आप उस तरफ चले गए और एक-दूसरे को हम गालियां

28/03/2018/1540/RG/HK/2

देते रहे। ---(घण्टी)----हमें इस सदन की गरिमा को बनाना पड़ेगा। हमें अपनी इस असोसियेशन को मजबूत करना पड़ेगा। अगर जनता हमसे जवाबदेही चाहती है, तो यहां जो ब्यूरोक्रेट्स या अन्य अधिकारी हैं, उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करुंगा। श्री राकेश सिंघा जी ने यहां एक बहुत अच्छी बात कही कि पैरापिट के स्थान पर आजकल जो यह क्रश बैरियर लगे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। अभी कहीं-कहीं पैरापिट्स की लग रहे हैं। उनको हटाकर वहां क्रश बैरियर्ज लगाए जाएं। एक और बात है कहते हैं कि भ्रष्टाचार की बू आती है, कहते हैं कि चोरी-चकारी होती है। यह डी.एन.आई.टी. है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले की सरकार ने प्रयास नहीं किए। इससे पहले की सरकार ने भी प्रयास किए। तो यह डी.एन.आई.टी. प्रथा बंद होनी चाहिए। अब छोटे-से-छोटे काम की भी ऑन लाईन टैण्डरिंग हो रही है। ठीक है कि इमरजेंसी वर्क के लिए कोई 50,000/-रुपये की डी.एन.आई.टी. तो बन जाती है। लेकिन होता क्या है कि आजकल ठेकेदार बहुत चतुर हैं। यदि आप एक डी.एन.आई.टी. किसी को देंगे, तो वह अपनी घरवाली की रजिस्ट्रेशन कराएगा और अपने भाई का रजिस्ट्रेशन कराएगा। मेरे चुनाव क्षेत्र कांगड़ा में एक कन्क्रीट की सड़क बनी है, 6,00,000/-रुपये में उसकी 13 डी.एन.आई.टी. बनी हैं। यदि आप उस सड़क पर जाएंगे, तो वह सारी फट गई है। जब छः लाख रुपये से वह कन्क्रीट रोड बन रहा है और तीन महीने के बाद वह खराब हो जाए। ---(व्यवधान)---
-यह बात नहीं है कि हमारी सरकार ने बनाया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह आपकी या हमारी सरकार में बना। जब तक आप एक-दूसरे की टांग खीचते रहेंगे, तो आगे-आगे देखो, होता है क्या? मैं एक बात कहूं कि आप चिन्तन करिए, काम करिए और दूसरी रही राजनीति की बात, तो

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

28.03.2018/1545/जेके/एचके/1

श्री पवन कुमार काजलः------जारी-----

जब बन्दा वोट डालने जाता है तो सुबह सोच के जाता है उससे पहले नहीं सोचता है। आप ऐसा न सोचो ।जो आप अच्छा काम करेंगे ....व्यवधान...

अध्यक्षः प्लीज आपस में बात मत करें।

श्री पवन कुमार काजलः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी, ये जो एक-दो बातें मैंने आपसे रखी है और यहां पर जो माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने कहा कि जो ये टेंडर प्रक्रिया हम करते हैं 22 दिन की होती है उसे क्यों न 10 दिन करें। ऑन लाइन कर देते हैं। अब पूरे प्रदेश में ऑन लाइन सिस्टम हो गया। नैट पर आ गया और सब जगह आ गया। चाहे एक टेंडर पड़े या तीन टेंडर पड़े उसमें क्या लेना-देना है क्योंकि ऑन लाइन है। जब ऑन लाइन टेंडर पड़ता है तो उसको अवार्ड करो। फिर अवार्ड करने के बाद यदि यह कहें की एक टेंडर पड़ा है कि हम दूसरी बार इसको करेंगे, कौन करेंगे और फिर तीसरी बार करेंगे....व्यवधान....

अध्यक्षः माननीय सदस्य प्लीज वाइंड अप करें।

श्री पवन कुमार काजलः अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न बोलता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे आपने 13 मिनट ही दिए परन्तु कोई बात नहीं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, पांच मिनट की जगह आपको 13 मिनट दिए।

श्री पवन कुमार काजलः अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। जय हिन्द।

अध्यक्षः मेरा सभी माननीय सदस्यों से एक आग्रह है कि हमारे पास बोलने वालों की संख्या छः है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका उत्तर भी देना है। जिस प्रकार की परिपाटी है उसके अनुसार 5 बजे से ऊपर आज की बैठक नहीं जा सकती है। मेरा आग्रह है कि छः लोग पांच-पांच मिनट में अपनी बात कहें ताकि मुख्य मंत्री महोदय कम से कम 40 मिनट में अपनी बात कह सकें और आप लोगों का उत्तर दे सकें। नहीं तो अंत में कुछ लोग रह जाएंगे। अब माननीय सदस्य, श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी।

28.03.2018/1545/जेके/एचके/2

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः10- लोक निर्माण सड़कें, पुल एवं भवन। इसमें कटौती प्रस्ताव के ऊपर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा

हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम सड़कों की बात करें तो स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सड़कें हमारे भविष्य की रेखाएं हैं। आज अगर हम हिमाचल प्रदेश में सड़कों की बात करते हैं तो जगह-जगह से सड़कें टूटी हुई हैं। उनका मुरम्मत का काम होना चाहिए। पैच वर्क तेज़ी से होना चाहिए क्योंकि जून के महीने में बरसात शुरू हो जाएगी। अगर यह काम हम अभी से नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारी सड़कों की स्थिति है वह बरसात में और भी ज्यादा खराब हो सकती है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मेरे नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनके ऊपर पैच वर्क भी होना है और मुरम्मत का भी काफी काम होना है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र नालागढ़-मितियाँ-कवारन-नण्ड-स्वारघाट रोड़, दूसरी नालागढ़-रामशहर-डोली-साई चढ़ोग रोड़, तीसरी नालागढ़ से रोपड़ रोड़, चौथी नालागढ़-रतवाड़ी-गुज़रहट्टी रोड़, पांचवीं सोबन माजरा-बरूणा-बघेरी रोड़, छठी सोबन माजरा- भरतगढ़ रोड़, सातवीं नालागढ़-बारियाँ -अलयोण रोड़ और आठवीं मस्तानपुरा-खिलियां - कोटला रोड़ की बात करना चाहता हूं। बहुत लम्बे समय से ये सड़कें पक्की हुई हैं। लेकिन पक्की होने के बाद कभी भी इनके ऊपर पैच वर्क नहीं हुआ। मैं, मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इन सड़कों की ओर ध्यान दे कर इनका मुरम्मत का काम जल्दी से करवाया जाए। सरकार की मशीनरी की बात यदि हम करें तो हमारे नालागढ़ डिविज़न में दो सब डिविज़न पड़ते हैं। दो जे0सी0बी0 और दो बुलडोजर्ज़ वहां पर हैं लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब है। हर रोज़ कोई न कोई बुलडोज़र और जे0सी0बी0 खराब रहती है। हमारा जो डिविज़न है तीन चुनाव क्षेत्र को डील करता है। दून है, अर्की है और हमारा नालागढ़ है लेकिन सरकार की तरफ से दो जे0सी0बी0, दो बुलडोजर्ज़ बहुत कम है। यह पुरानी मशीनरी है और इनकी जगह नई मशीनरी होनी चाहिए।

28.03.2018/1550/SS-YK/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा क्रमागतः

इतने बड़े डिवीजन में तीन-तीन जे0सी0बी0 और तीन-तीन बुलडोजर की आवश्यकता है। सरकार कहती है कि प्रत्येक पंचायत को सड़क के साथ जोड़ने का हम प्रयास करेंगे

परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी हिमाचल प्रदेश में बहुत-सी पंचायतें ऐसी हैं और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जोकि अभी भी सड़कों के साथ जुड़ी हुई नहीं हैं। कुछ सड़कें पंचायतें ने अपने लेवल पर बनाई हैं लेकिन जब बरसात आती है तो वे सड़कें बंद हो जाती हैं। लोगों को टमाटर व सब्जी लाने में बड़ी दिक्कत होती है। पंचायतों के पास अपना कोई बजट नहीं होता। लेकिन मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि इन सड़कों को पी0डब्ल्यू0डी0 के अधीन किया जाए ताकि बरसात के दिनों में हमारे किसानों को अपनी सब्जी व फसल सही ठिकाने पर पहुंचाने में कोई बाधा न आए।

सरकार ने यहां पर विश्राम व परिधि गृहों की बात की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नालागढ़ में जो पी0डब्ल्यू0डी0 का रैस्ट हाउस है उसमें बहुत कम कमरे हैं। ज्यूडिशरी के सैशन जज, एडिशनल सैशन जज के वहां टूअर होते रहते हैं लेकिन अगर वहां पर कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति ठहरना चाहे तो उनको कमरे नहीं मिलते हैं। उस विश्राम गृह को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। इसी प्रकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कुंडलू पंचायत पड़ती है वहां पर पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम 32 बीघा जमीन है अगर वहां पर विश्राम गृह बनाया जाए तो बेहतर होगा क्योंकि नालागढ़-स्वारघाट-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली का वह रोड है तो मुझे लगता है कि उसका लाभ सब लोग उठा सकते हैं।

इसी तरह अगर हम पुलों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में महादेव नदी के ऊपर नेशनल हाईवे पर एक पुल है। इसी तरह जोगो-बगलैहड़ गांव के पास कालाकुंड नदी के ऊपर पुल है उसकी स्थिति बड़ी खराब है। स्थिति खराब होने का कारण यह है कि वहां पर खनन काफी हुआ। वहां पुल के पैर खिसक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उसके लिए अलग बजट दिया जाए ताकि वह पुल इस बरसात को निकाल सके। अन्यथा लोगों के आने-जाने के लिए यह जो मेन रोड नालागढ़-स्वारघाट-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली का है इसमें बाधित होना पड़ेगा।

28.03.2018/1550/SS-YK/2

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैं पी0डब्ल्यू0डी0 डिवीजन नालागढ़ की बात करना चाहता हूं। यहां पर बहुत से सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि डिवीजनों में काफी गड़बड़ियां हैं। हमारे वहां पर मैंने पीछे देखा है कि 400 स्लिप्स के टैंडर किये गए, रिटेनिंग वॉल के टैंडर किये गए। 400 स्लिप्स का मतलब है कि एक स्लिप के लिए 50 हजार रुपया जे0सी0बी0 से उठाने का काम लेकिन हकीकत में वहां पर काम हुआ नहीं है। करोड़ों रुपये का चूना सरकार को लग रहा है। इसको चैक किया जाना चाहिए। रिटेनिंग वॉल जहां लगनी चाहिए वह वहां पर लग नहीं रही है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो कुछ पुल बनने हैं उनकी बात यहां पर रखना चाहता हूं। ग्राम पंचायत बरूणा में कोटला फलाही नदी पर पुल का निर्माण होना है। ग्राम पंचायत रेडू में कल्याणपुर नदी पर पुल का निर्माण, ग्राम पंचायत दभोटा में ग्राम बोदला से दभोटा नदी पर रतयोड़ गांव के लिए पुल का निर्माण और ग्राम पंचायत सैनीमाजरा से सिरसा नदी पर पुल का निर्माण होना बाकी है। मुख्य मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत गांववासियों को शीघ्र सड़क के साथ जोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह बजट बहुत कम है क्योंकि हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा है। इस बजट को बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज़ वाइंड अप करें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः इसी तरह 2018-19 में पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के लिए 4082 करोड़ के बजट का प्रावधान यहां पर रखा गया है। यह जो 4082 करोड़ रुपया है मुझे नहीं लगता कि यह पूरे प्रदेश के लिए काफी होगा, इस बजट को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह से मैं अपने एक नेशनल हाईवे की बात करूंगा। हमारे राम लाल ठाकुर जी ने भी इसकी बात कही। 21A - नालागढ़ से स्वारघाट का रोड, बहुत लम्बे समय से इसका काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। मैं सरकार से यहां पर आग्रह करना चाहता हूं कि इस काम को स्पीड अप किया जाए ताकि यह रोड लोगों को जल्दी समर्पित हो सके।

28.03.2018/1555/केएस/वाईके/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा जारी---

इसी तरह हिमाचल रोड़ इम्प्रूवमैंट स्कीम के तहत 2018-19 के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः अध्यक्ष जी, हर चुनाव क्षेत्र की अगर हम सड़कें देखें तो उनकी इम्प्रूवमैंट के लिए यह बजट काफी नहीं है, इसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। विधायक प्राथमिकता में जो हमने सड़कें डाली हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इन पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि सभी विधायकों ने विधायक प्राथमिकता में सड़कें डाली हैं । अक्सर ऐसा होता है कि पांच साल बीत जाते हैं और उनकी डी.पी.आर. नहीं बनती, उनका काम शुरू नहीं हो सकता और बाद में सभी विधायकगणों को पछताना पड़ता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज़। फिर मुझे अन्तिम दो-तीन लोगों के नाम काटने पड़ेंगें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, इसी तरह नालागढ़ में एक झूला पुल था कंगरवाल के लिए और उसकी रिपेयर के लिए दो लाख रु0 आए थे लेकिन विभाग ने उसके ऊपर 15 हजार रुपये खर्च किए, उसमें डेंटिंग-पेंटिंग, रंग वगैरह किया और उसका काम बन्द कर दिया। जब वहां के एक लोकल आदमी ने आर.टी.आई. लगाई तो उसके बाद वहां पर काम किया गया।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब मैं अगले सदस्य को कॉल करुंगा।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, बस अब मैं समाप्त कर रहा हूं। इस ढंग से चैक करने की आवश्यकता है ताकि लोक निर्माण विभाग का पैसा वेस्ट न हो। इन्हीं

शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

28.03.2018/1555/केएस/वाईके/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी।

श्री विक्रमादित्य सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे मांग संख्याः10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल तथा भवन पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पर जो अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट पेश किया, इस विभाग के अंतर्गत जो कार्य प्रदेश के अंदर चला है, उसके बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा हमारे विपक्ष के नेता तथा बाकी माननीय सदस्यों ने यहां पर की। वैसे तो खुशी की बात है, इसका हम स्वागत भी करते हैं कि नये 69 हाइवेज़ हिमाचल प्रदेश को मिले हैं मगर जैसा यहां पर कहा गया कि यह तो समय ही बताएगा कि बात कहने में और उसके इम्पलिमैंट होने में कितना समय लगता है। कहा गया कि 65 हजार करोड़ रु0 का बजट प्रावधान उसके लिए करवाया गया है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो पीछे विधान सभा के चुनाव थे, उनमें लोगों को आकर्षित करने के लिए यह कार्य किया गया था मगर क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केन्द्र में भी बी.जे.पी. की सरकार है तो हमारा तो सरकार से यही निवेदन रहेगा कि इसके लिए पैसे का प्रावधान करवाया जाए और तीन नेशनल हाइवेज़ हमारे विधान सभा क्षेत्र से हो कर भी गुज़रते हैं। एक सलापड़ से सैंज वाया सुन्नी है, इससे करीब चार-पांच जो हमारे इलाके हैं, रामपुर, आनी, किन्नौर, कुमारसैन और सुन्दरनगर इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। वैसे ही एक सुन्नी से लूहरी है और करीब 50 किलोमीटर का सफ़र इस सड़क के माध्यम से करवाया जाता है, इसका कार्य बहुत लम्बे समय से लम्बित है, इसको भी प्राथमिकता से करवाया जाए क्योंकि जब भी मौसम खराब होता है या जब भी बर्फ का सीज़न रहता है तो सारा ट्रैफिक जो हमारा रामपुर या किन्नौर जाना है वह वाया लूहरी हो कर ही जाता है। तो इस चीज़ को प्राथमिकता पर देखा जाए, यह मेरा निवेदन रहेगा। इसके साथ ही शिमला-ढली-तत्तापानी-रोहांडा और सुन्दरनगर की भी प्रपोज़ल है। डी.पी.आर. बननी है। कब बनेगी यह तो समय ही बताएगा मगर इसको भी

प्राथमिकता पर देखा जाए, यह मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत पुरानी सड़क है, देवीधार-घैणी-पाहल-नयासैल-दभोग-धारकुफर, यह नाबार्ड में वर्ष 2012-13 से लम्बित है

28.3.2018/1600/av/ag/1

श्री विक्रमादित्य सिंह जारी

because of non-forest clearance, वैसे तो बजट में इस बात को भी रखा गया है। मैं बजट बुक में पढ़ रहा था जिसमें मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जितने भी एफ0आर0ए0 या एफ0सी0ए0 के केसिज हैं उनको हम ऐक्सपिडाइट करने के लिए प्रयास करेंगे। मगर इसको आगे किस तरह से लेकर जाना है that needs to be seen. अभी यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं बैठे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गिफ्ट डीड्स की दिक्कत केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जिनके लिए बजटरी प्रोविजन के साथ-साथ सरकार / ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है मगर because of non-acceptance of gift deed की वजह से वे काम पूरे नहीं हो पाते हैं। मैं इसमें आपको बढ़ैहरी-शिल्ली सड़क का उदाहरण देना चाहता हूं। यह सड़क चार किलोमीटर तक पूरी हो चुकी है मगर उसमें आगे 1.5 किलोमीटर शिल्ली-रैहल सड़क बननी है जो पिछले तीन सालों से केवल एक व्यक्ति की वजह से पैंडिंग पड़ी है। अभी यहां पर एक माननीय सदस्य बात कर रहे थे कि सड़क बनाने के लिए एम0एल0ए0 और ऐडमिनिस्ट्रेशन के कोलैक्टिव ऐफर्ट्स होने चाहिए। उसमें वहां की स्थानीय जनता का भी सहयोग होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसमें स्थानीय लोगों को राइट्स दिए गए हैं मगर इसके लिए एक पोलिसी बनाने की आवश्यकता है। कई बार बहुत कम गिफ्ट डीड्स की वजह से विकास के कार्यों में बाधा आ रही है और उस चीज को देखने की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां पर सोलिंग

हो चुकी है मगर समय पर टारिंग न होने की वजह से वे सड़कें उखड़ने लग गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जमोग-जूनी, चैवड़ी लिंक रोड, बैंश-पिपलीधार, घनाहट्टी-पड़ैच इत्यादि सारी सड़कों पर सोलिंग हो चुकी है। मगर समय रहते विभाग द्वारा इस पर टारिंग नहीं की गई जिसकी वजह से इसके ऊपर फिर से सोलिंग का खर्चा करना पड़ेगा। मैं एक और बात इस मान्य सदन व सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। पीछे चुनाव के दौरान बहुत से वायदे किए गए हैं और निश्चित तौर पर चुनाव के

28.3.2018/1600/av/ag/2

दौरान कई छोटे-बड़े वायदे किए जाते हैं। हम भी लोगों की बीच में गये और लोगों से काफी ज्यादा वायदे किए। मैंने नई सड़कों को नाबार्ड के माध्यम से डालने या एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में डालने के बारे में पता किया। मगर जब मुझे प्लानिंग की मीटिंग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा जब यह पता चला कि यह सारा पैसा तो पिछले विधायक के समय से केरी फारवर्ड हो रहा है। इसमें अगर कहीं पैसा बचा होता है तो नये विधायक के आने पर उसमें प्राथमिकता दी जाती है। हमारा जब नया वित्त वर्ष शुरू होता है तो नये विधायक को उसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नई सड़कें जिसको विधायक आगे ले जाना चाहता है उसको भी प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए। यहां पर इस बजट में फोर लेनिंग की बात भी की गई है। वर्तमान में कालका-शिमला, कीर्तपुर-मनाली और शिमला-मटौर के लिए आने वाले समय में शुरुआत होगी। इसके लिए मेरा सुझाव रहेगा मगर उसको लागू करना या न करना सरकार की मर्जी है। हम प्रदेश में टूरिज्म की बात करते हैं कि हमें व्यवसाय बढ़ाना है और इसको बहुत ज्यादा सीनिक बनाना है। यहां पर जब भी कोई टूरिस्ट आता है तो यहां पर हो रहे फोर लेनिंग के कार्य को देखता है। वह शिमला से कांगड़ा या मनाली जा रहा है तो दोनों साइड पर बड़े-बड़े स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जिनकी वजह से इस प्रदेश की सीनिक ब्यूटी को देखने से वह कहीं-न-कहीं वंचित रह जाता है।

28.03.2018/1605/TCV/AG-1

श्री विक्रमादित्य सिंह... जारी

इसकी फोरलेनिंग अभी शुरू होनी है, इसका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि at least as a pilot project जो हमारी वैली व्यू है, वहां पर कंस्ट्रक्शन बैन की जाये। इसमें 10 या 15 किलोमीटर के बाद हब्ज़ बनाये जा सकते हैं, जहां पर टॉयलेट्स, होटल या मोटल का प्रावधान किया जा सकता है। ताकि जगह-जगह पर जो स्ट्रेक्चर बनाये जा रहे हैं, खासकर जहां सीनिक व्यू है, वहां पर इनको न रखा जाये।

ब्लैक स्पॉट्स की बात भी बजट में की गई है और इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं अभी हाल ही में एक दुर्घटना मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में हुई है जिसमें 4 लोंगों की मौत हो गई है। इसलिए निश्चित तौर पर क्रैश बैरियर को प्राथमिकता पर लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए मु0 50 करोड़ रुपये का बज़टरी प्रोविज़न करवाया गया है। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा कम है। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत-से ऐसे मोड़ हैं, जहां पर दुर्घटनायें होती है। उनको आईडैंटिफाई करवा करके, वहां पर क्रैश बैरियर लगवाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सड़कें और है, एक चैली-ब्यूंट-कडैची है, जो 60 करोड़ रुपये की नाबार्ड के माध्यम से बननी है। दूसरी सड़क का मैंने आप क्वैचन भी लगाया था लेकिन वह डिस्कशन के लिए नहीं आया। इस सड़क की मांग उस समय से चली आ रही है, जब स्वर्गीय खाची साहब और श्रीमती विद्या स्टोक्स जी इस क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे। ये बहुत ही पुरानी सड़क है। दूसरी सड़क धरोगड़ा-नागजुब्बड़-दिलोघाटी है जो ठियोग विधान सभा क्षेत्र में जाकर मिलती है। इसमें कांग्रेस सरकार के समय में स्टेट फंड से पैसा दिलवाया गया था। But because of non-availability of NABARD funds अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ये

एक महत्वपूर्ण सड़क है, आने वाले समय में प्राथमिकता पर इसका कार्य हो, ये मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

28.03.2018/1605/TCV/AG-2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह रायजादा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सतपाल सिंह रायजादाः अनुपस्थित

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर मांग संख्याः 10 रखी गई है- लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन , मैं भी उस पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस विषय पर काफी चर्चा कर ली है। फिर भी मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। जहां तक 69 नेशनल हाईवेज़ की बात आई है। इस पर भी काफी डिटेल में चर्चा हो चुकी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा और वह ठेकेदारों से संबंधित है। जो ठेकेदार हैं, वे अपनी पिछले कामों को पूरा न करके आगे-से-आगे काम लेते रहते हैं। जबकि उनके पिछले काम अधूरे ही होते हैं। इस पर भी चैक होना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि जिनके पास 2 या 3 काम पैंडिंग पड़े हो, उनको अगला काम नहीं देना चाहिए। इससे कई जगह काफी नुकसान हो रहा है। कई जगह इन कामों की सबलैटिंग भी हो रही है। इस कारण से भी काम नहीं हो रहे हैं, चाहे वह सड़कों की बात हो या बिल्डिंग की बात हो। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर सख्ती होनी चाहिए। मैं पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं। ठियोग-खड्डा पत्थर-हाटकोटी -रोहडू रोड़ काम पहले चाइनिज कंपनी के पास था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल उस समय मुख्य मंत्री थे। उस दौरान किसी कारणवश इसका काम बन्द पड़ा रहा । अढ़ाई-

तीन साल तक काम बन्द पड़ा रहा। जब 2012 में हमारी सरकार बनी और राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री बने। इनके प्रयासों से उसका काम शुरू हुआ।

28-03-2018/1610/NS/DC/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा -----जारी।

आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसका काम काफी हद तक हो चुका है। इसमें काफी इम्प्रूवमैंट है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि निहारी में थोड़ा काम बचा है। वहां पर लगभग 3 या 4 किलोमीटर कटिंग रही है। मैं खुद भी इसी रास्ते से आता जाता रहता हूं। वहां पर आजकल कटिंग का काम बंद पड़ा हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें स्पीड-अप किया जाये। इस रोड में अभी और काम होना बाकी है। क्योंकि मैंने इसके लिए विधान सभा में प्रश्न लगाया था और माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से जवाब आया है कि हम इसका 90 प्रतिशत काम कर चुके हैं। यह बात ठीक है। इसमें काफी काम हो चुका है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि आपने आते ही इसके लिए पैसा सैंक्शन किया है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इसमें अभी कलवट बचे हैं, डंगे लगने हैं और पुल का भी काफी काम बचा हुआ है। इसको जल्दी-से-जल्दी करवाया जाये। इस रोड से केवल रोहड़ू वासियों को ही फायदा नहीं हो रहा है बल्कि जुब्बल-कोटखाई वालों को भी फायदा होगा। इसके अलावा हमारे जो दूसरे आल्ट्रनेटिव रोड रोहड़ू के लिए हैं, इसमें हमारा नारकंडा-टिक्कर रोहड़ू रोड है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से आग्रह रहेगा कि इस रोड में वाइडनिंग, टारिंग और मैटलिंग की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारा दूसरा रोड नारकंडा से खदराला-सुंगरी हो करके जाता है, इसमें भी बहुत मरम्मत की आवश्यकता है। अभी जब हमारे चुनाव हुए थे, मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में बात लाई थी कि मेरे क्षेत्र में एक सेयो दोगरी रोड है। यह रोड डोडरा क्वार में सेयो से दोगरी तक बनना है। इसमें उत्तराखंड की लैंड भी आती है। इसके लिए हमें उत्तराखंड की सरकार से नेगोशिएशन करना पड़ेगा। चुनाव के दौरान उत्तराखंड के मुख्य मंत्री डोडरा क्वार आये थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस रोड को बनाया जाएगा। मैं समझता हूं, अगर यह रोड बन जाये तो यह अच्छी बात है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि

हमारा डोडरा क्वार का क्षेत्र जो छः महीने के लिए कट रहता है, इस रोड के बनने से जुड़ जाएगा। इसके अलावा गुसांगो-जिसकुन जाखड़ रोड है, इसका काम भी काफी अर्से से बंद पड़ा है। इसके कारण चाहे जो भी रहे हों, चाहे ठेकेदार या विभाग की वजह से रहे हों , इसके लिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इसका काम जल्दी-से-जल्दी करवाने के विभाग को आदेश दिये जायें।

28-03-2018/1610/NS/DC/2

माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी 3-4 मार्च को रोहड़ू के दौरे पर गये थे। मैं इसके लिए इनका स्वागत करता हूं। क्योंकि यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में आये थे। इन्होंने समाला रोड का उद्घाटन किया है। यह बहुत अच्छी बात है। यह रोड लगभग 8 या 9 किलोमीटर है। लेकिन आपने इसका सिर्फ तीन या साढ़े तीन किलोमीटर ही उद्घाटन किया है। आप इसको पूरा कर दें। क्योंकि आपके पास अभी पांच साल का समय है। (घंटी) इस रोड का सभी को फायदा होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी रोड हैं, किसी की टारिंग होनी है, किसी की मैटलिंग होनी है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इनका मैक्सिमम काम करवाया जाये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि डीलिमिटेशन के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार पंचायतें जुब्बल-कोटखाई से आई हैं- बराल, शील, कटला और करछाली। पहले इन चारों पंचायतों का डिवीज़न जुब्बल में था। लेकिन पिछले पांच सालों में इनके लिए बहुत खींचातानी रही है, ये कभी रोहड़ू में और कभी जुब्बल में । लेकिन अब ये पंचायतें रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में आ गई हैं।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी ने आप सबकी बात का रिप्लाई देना है। आप कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः इनका काम नहीं हो पाया है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इस बार लोक निर्माण विभाग इन चारों पंचायतों में विशेष ध्यान दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28-03-2018/1610/NS/DC/3

अध्यक्षः अब माननीय राजेन्द्र राणा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणाः अध्यक्ष महोदय, "मांग संख्याः10- लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन" जो कटौती प्रस्ताव है, उस पर चर्चा करने के लिए शामिल हुआ हूं। मेरे से पूर्व सभी माननीय सदस्यों ने 69 नेशनल हाईवेज़ पर काफी चर्चा की है। पर कन्फयूज़न यह है कि 69 नेशनल हाइवेज़ पर चुनावों से पहले बार-बार घोषण हुई और धन्यवाद प्रस्ताव भी हुए हैं। यह भी चर्चा हुई है कि लगभग 65,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश को मिली है। अब हम लोग ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी बात है, हिमाचल प्रदेश को 65,000 करोड़ रुपये की राशि मिल रही है लेकिन डी0पी0आर0 तैयार नहीं हुई और

28.03.2018/1615/RKS/DC-1

श्री राजेन्द्र राणा... जारी

65 हजार करोड़ रुपये का आकलन कैसे हुआ यह हमारी समझ से बाहर है। कहते हैं-

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो कतरा एक खुन न निकला॥

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप तो पुराने शायर हैं परन्तु आपने इस शेर को पढ़ के क्यों बोला?

श्री राजेन्द्र राणाः सर, इसलिए कि कहीं गलती न हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में आने वाले 5 वर्षों में यह काम पूरा होगा। मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा क्योंकि आपने मुझे 5 मिनट बोलने का समय दिया है। जब विधान सभा चुनाव हुआ और नतीजे आए तो मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, सुजानपुर में कई काम बंद करवा दिए गए। आज

मेरा विधान सभा प्रश्न लगा था और उसका उत्तर भी आया है। बहुत सारे टेंडर थे, बहुत-सारी सड़कें थीं, जिनके टैंडर रद्द कर दिए गए। जब मैंने इसके बारे में विभाग से बात की तो विभाग का यह कहना था कि इसमें राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा था। राजनीतिक दबाव तो हम समझ सकते हैं लेकिन जो पैसा पिछली सरकार ने स्वीकृत किया है, टैंडर हो चुके थे, कई काम शुरू हो चुके थे, वे काम बंद कर दिए गए। मुझे लगता है कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि विभाग के सभी अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। सुजानपुर में माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से एक टाउन हॉल स्वीकृत हुआ। उसके लिए 75 लाख रुपये की पहली किस्त भी जारी की गई। इतने महीने हो गए और विभाग यह कह रहा है कि अभी ड्राइंग्स बन रही है, आर्किटैक्चर इसकी तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है कि विभाग को इस कार्य को तेजी से करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उसकी ड्राइंग्स तैयार करने में ही

28.03.2018/1615/RKS/DC-2

2 वर्ष या 5 वर्ष लग जाए। इस कार्य को जल्द-से-जल्द शुरू किया जाए। इसके अलावा नाबार्ड के अंतर्गत जो सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ है उसमें Bhatra-Thalkrakhoia Road लगभग पूर्ण हो गई है। इस सड़क में एक पुल का निर्माण होना बाकी है। इसका शिलान्यास हो गया है। इसके लिए पैसा भी जारी हो गया है। अब जल्दी-से-जल्दी टेंडर करवाकर इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। इसी तरह बनाल-चम्याणा सड़क पर भी एक पुल का निर्माण होना है। उसके लिए भी पैसा स्वीकृत है। इसका शिलान्यास हो गया है और पी.डब्ल्यू. डी. को पैसा भी दे दिया गया है। एक ब्लॉक वैटरनरी हॉस्पिटल का निर्माण होना है, उसका काम भी जल्दी शुरू किया जाए। सुजानपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में मैडिकल और पैरा-मैडिकल स्टाफ के लिए रेजिडैंशियल एकोमोडेशन का निर्माण होना है, उसके लिए भी पैसा स्वीकृत हो गया है और इसका काम भी जल्द शुरू किया जाए। क्षेत्रीय अस्पताल के लिए अतिरिक्त भवन बनना है उसका भी सरकार जल्दी-से-जल्दी काम शुरू करे। हमारे माननीय सदस्यों

की तरफ से एक सुझाव आया है कि जो रोड डिपोजिट में बनते हैं, जब बाद में वे टूट जाते हैं तो उनके रख-रखाव के लिए सरकार बजट का प्रावधान करे। हर चुनाव क्षेत्र के लिए जो ऐसी सड़कें बनी हैं उनके रख-रखाव/ मरम्मत के लिए कुछ बजट का इंतजाम किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, सुजानपुर, विधान सभा चुनाव क्षेत्र जो कि धर्मपुर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ जुड़ता है। वहां पर दोनों तरफ से सड़कें मिल गई हैं। वहां पर कुजां द बल्ह एक स्थान है जहां पर एक पुल का निर्माण होना है ताकि दोनों चुनाव क्षेत्र आपस में जुड़ जाएं। मैं चाहूंगा कि इस पुल के निर्माण के लिए भी सरकार पैसे का इंतजाम करे। विधान सभा चुनाव के बाद एक सड़क निर्माण का कार्य रोक दिया था। वहां पर मशीनरी भी पहुंच गई थी और 10 दिन तक वह मशीनरी वहां रही। जब मैंने पूछा कि इस सड़क का काम क्यों नहीं हो रहा है तो विभाग का कहना यह था कि इसमें राजनीतिक दबाव ज्यादा था। जब मैंने ठेकेदार से पता किया तो उसने भी यह कहा कि मुझे विभाग ने कहा कि मशीनरी वापिस ले जाओ। लोगों ने वहां पर एजिटेशन करने की बात कही थी। परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इनके हस्तक्षेप से कल वहां मशीनरी आ गई है। मुझे लगता है कि अब वहां काम शुरू हो जाएगा।

28.03.2018/1620/बी0एस0/एच0के0-1

श्री राजेन्द्र राणा.....जारी

मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सड़कों का निर्माण और बढ़िया ढंग से होगा। क्योंकि किसी प्रदेश की तरक्की और विकास इस बात से आंका जाता है कि वहां की सड़कें कैसी हैं, क्योंकि प्रदेश में बाहर से भी लोग आते हैं और देखते हैं कि सड़कों का रख-रखाव और सड़कों का निर्माण किस तरीके से हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जो 69 राज मार्गों की बात की गई है, जल्दी से जल्दी ये राज मार्ग बने और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। धन्यवाद।

28.03.2018/1620/बी0एस0/एच0के0-2

अध्यक्षः माननीय श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी, कृपया पांच मिटन में अपनी बात रखें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष एक बहुत ही अहम बात रखना चाहता हूं, ये जो सड़क, पुल एवं भवनों को ले करके चर्चा चल रही है उसमें कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी ने भी हाल ही में कनेक्टिविटी की बात कई जगह कही है। हिमाचल प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में अगर आगे ले जाना है, अगर हिमाचल प्रदेश को पर्यटन प्रदेश बनाना है तो हमें कनेक्टिविटी पर जोर देना पड़ेगा। सरकार के पास बहुत काबिल टीम है, आरदणीय खाची साहब हैं बड़े अनुभवि हैं और अन्य भी अधिकारी हैं। मैं किर्तपुर से नेरचौक तक के फोरलेन की बात करना चाहूंगा। जो किर्तपुर से नेरचौक तक फोर लेन बन रहा है उसमें वही मोड़ वही लूप, यह नहीं देखा गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान की कितनी दूरी कम हुई। यह हमारे लोक निर्माण विभाग का कार्य नहीं था। लेकिन आगे एन.एच. पर ऐसा कार्य न हो, मैं अनुरोध करूंगा कि सीधे सेटेलाइट पिक्चर पर जाइए और वहां पर जो हमारे हाईवेज बनने हैं कम से कम एक शहर से दूसरे शहर की दूरी कम हो, यह तो तय होना चाहिए। आज हम क्या देख रहे हैं कि वही मोड़ हैं, उन्हीं को चौड़ा किया जा रहा है और उसमें मेरा एक अनुरोध रहेगा कि कृपया हमारे यहां पर ऐसा है कि एक राईट बैंक है और एक लेफ्ट बैंक है। जैसा हमारे कुल्लू के क्षेत्र में है। अगर आपको मणिकरण की तरफ कोई रोड़ बनाना है तो आप देखेंगे कि वहां पर लैफ्ट बैंक पर रोड़ है। अभी राईट बैंक पर पूरे के पूरे वहां लिंक रोड़ हैं, ब्रिज डालकर आपने गांव तक जोड़ दिया है। यदि आपका कोई भी नया रोड़ प्रपोज होता है तो इसी प्रकार की प्रपोज़ल बननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, न जाने क्यों हिमाचल प्रदेश में अभी टनल को लेकर बहुत बड़ा काम माना जाता है। मेरे गांव में लोगों ने चार-चार किलोमीटर की दो बाई स्वा दो डाए की टनल खुद हाईड्रो प्रोजैक्ट में बनाई हैं, वह ज्यादा कठिन होती है। जो बड़े डाए की

28.03.2018/1620/बी0एस0/एच0के0-3

टनल होती है वह आसान होती है। बड़े डाए में वेंटिलेशन भी बढ़िया मिलता है। छोटे डाए की टनल में भी एक तरफ से लोग अंदर गए है और वे गांव के लोग हैं। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है जिन-जिन स्थानों में ये हाईड्रो प्रोजेक्टस बने हैं हमारे लोगों ने उसमें कार्य किया है और इस कार्य में माहिर बन करके निकले हैं। आप अगर किसी बड़ी टनल को तैयार करने का ठेका देंगे तो वहां पर आपको बिहार और उड़िसा के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, वहां हमारी अपने ही लोग इस कार्यो को कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से जो बदलाव हुआ है इन बातों को भी हमें अपने रिर्काड में ले लेना चाहिए।

आज नेशनल हाईवे के लिए डी.पी.आर.की बात हो रही है, मेरा सुझाव है कि कम से कम आप टनल और फ्लाईओवर पर जरूर ध्यान दें। क्योंकि जिस प्रकार से फोर लेन का कार्य हो रहा है जैसे ही आप सड़क हैंडओवर करते हैं जब तक ये तैयार नहीं होती तब तक उन्होंने पूरे के पूरे हमारे पहाड़ खोद दिए हैं। कृपया आप टनल के बाद फ्लाईओवर पर जाइए। आज आप कालका से शिमला तक की सड़क को देखिए कहीं भी किलोमीटर कम होने की बात नहीं हो रही है।

28.03.2018/1625/डी०टी०/एचके/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर द्वारा जारी----

उसी ग्रेड में उसी मोड़ पर उन्हीं चीज़ों को फ़ोलो किया गया है । जबकि बीच-बीच में

सीधे फ्लाय ओवर डालकर ऑलरेडी जो रोड़ हैं उन्हें सर्विस रोड़ रखा जाता और ये दूरी कम की जाती । मैं चाहता हूं कि इन बातों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, मैं जानता हूं कि यह खुद बड़े आरकिटेक्ट है। जो बढ़िया भवन हम जगह-जगह देखते हैं इनके नक्शे ये खुद देखते थे और यह चाहते थे कि जो हमारा पहाड़ का आरकिटक्चर है वो हमारे भवनों में **झ**लकना चाहिए। हमारी रूफिंग कैसी हो, हमारी इमारतें कैसी बनें यह सब इनकी ही सोच थी इसके कारण ही आज बढ़िया- बढ़िया भवन बनकर जगह-जगह तैयार हुए हैं। देरी कहां होती है? देरी तब होती है जब आपके चीफ आरकिटेक्ट के पास कोई ठेकेदार जाता है तो उसे डिज़ाइन नहीं मिलता---(घण्टी)--- सबसे बड़ी चिंता जो यहां पर आई है मै इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपके समक्ष रखूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर गौर करेंगें। हमारे नये विधायकों की एक आशंका है वह यह है कि 90 करोड़ रूपये का जो है वह यह है कि विधायक प्राथमिकता में पुरानी ही स्किमें पड़ी हुई हैं जिनमें 70-70 और 80-80 करोड़ रूपये ऑलरेडी पेंडिंग है । जिस कारण हमारी आगे की योजनाएं आनी मुश्किल हो गई हैं। कल हमारे माननीय आई०पी०एच० मंत्री, श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने कहा था कि इतनी स्किमें नाबार्ड के पास पहुंच गई हैं कि उन्हें फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। उन्होने कहा कि हम वो स्किमें वापिस मांगेगे और फिर से विधायकों को पूछेंगे । वैसा ही मेरा अनुरोध आपसे है कि अगर ऐसी कोई योजनाएं हैं तो हमारा टर्म के हिसाब से ये बजट प्लानिंग में निर्धारित किया जाये । क्योंकि इस बार 24 नये विधायक चुन कर आये हैं । पहले की बात और थी। आज और तब की बातों में दिन रात का फर्क है । वो 18वीं सदी के की बात थी। अब 21वीं सदी आ गई है । आज के दिन में जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल चुकी है, कई जगह जहां ऑलरेडी अगर हाईवेज़ आ रहें है तो वहां कुछ और रोड्ज़ हमारी प्राइयोरिटिज़ रहेगी । मैं आपका ज़रूर ध्यान लाना चाहूंगा---(घण्टी)---- कि हमारा एम०एल०ए० प्राइयोरिटिज़ पर काम तेजी से हो । मेरा एक आखिरी अनुरोध है कि ये ऐसा

28.03.2018/1625/डी०टी०/एचके2

क्यों हो रहा है विशेषकर मैं कुल्लू में देख रहा हूं कि कुछ ठेकेदार जो एक इलाके में तो ब्लैक लिस्टिड हैं, लेकिन उन्हें दूसरे इलाके में काम मिल रहा है । ऐसा क्या डिविज़िन वाईज़ होता है कि अगर कोई व्यक्ति मनीकरण घाटी में ब्लैक लिस्टिड होता है तो वह मनाली में काम कर सकता है? सभी जगह उसके जो टैंडर्ज़ हैं उनपर उसी वक्त रोक लगानी चाहिए । उसका जवाब-तलब भी होनी चाहिए। हमने ऐसा देखा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यह डिपार्टमैंट द्वारा कैसा तरीका अपनाया जा रहा है कि जो सबसे निकम्मा ठेकेदार है ----(घण्टी)---

अध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी ने आपकी बात का उत्तर देना है ।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः अध्यक्ष जी, अगर उसकी लाइजनिंग अच्छी है और उसकी मदद आरबिट्रेशन और डिपार्टमैंट के जरिए हो रही है। कुल्लू में एक गौरसी कन्स्ट्रक्शन कंपनी है उसका मालिक अपने आप को बड़ा रसूकदार मानता है और उसे **लग्ग** वैली में ब्लैक लिस्ट किया गया है। लेकिन आज मणिकर्ण में शारणी -तिहणी रोड़ का जो कार्य चला हुआ है उस रोड के कार्य में भी उस ठेकेदार के कार्य का यही हाल है। उस पर **एक्शन** क्यों नहीं लिया जा रहा है? अध्यक्ष जी,आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी मांग संख्याः10 का उत्तर देंगे।

28.03.2018/1630/SLS-HK-1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या : 10 'लोक निर्माण, सड़क, पुल एवं भवन', इस पर जो कटौती प्रस्ताव हमारे विपक्ष के मित्रों के माध्यम से यहां इस माननीय सदन में उठाए गए थे, मैं उस पर हुई चर्चा का उत्तर देने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, सड़कें हमारी जीवन रेखाएं हैं। हिमाचल जैसे प्रदेश, जहां भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन और जटिल हैं, सदियों तक हमारे बुजुर्ग लोग पीठ पर बोझ उठाते रहे, पैदल चलते रहे और घोड़े-खच्चरों पर अपना सामान इधर से उधर ले जा करके जिस प्रकार से गुज़ारा करते रहे और जब हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया, सरकार बनी तो धीरे-धीरे सड़कों का काम होता गया। सरकार ये रही चाहे वो रही लेकिन सब लोगों ने लोगों की पीठ का बोझ उतारने के लिए काम किया है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सड़कों के मामले में बहुत आगे बढ़े हैं। 3226 पंचायतों में से 3123 पंचायतों को अभी तक की स्थिति में हमने सड़कों से जोड़ दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी स्थिति है और इसमें मैं प्रमुख रूप से यहां ज़िक्र करना चाहूंगा। हमारे लिए सचमुच में यह काम और भी कठिन होता लेकिन हमारे देश के पूर्व में प्रधान मंत्री रहे आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह यह सपना देखा कि गांव में रहने वाले लोगों की पीठ का बोझ अभी भी नहीं उतरा। यह देश तरक्की की राह पर बहुत आगे बढ़ चुका लेकिन उसके बावजूद जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी पीठ का बोझ उतारना हम सभी का दायित्व है। उस दृष्टि से उन्होंने उस बात को भी महसूस किया कि यह प्रदेशों में अपने स्तर पर संभव नहीं है क्योंकि बहुत से प्रदेशों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है उन सरकारों के पास इतना पैसा उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन्होंने बीड़ा उठाया कि अगर प्रदेश सरकार के संसाधनों के माध्यम से हम सड़कों को तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ा सकते तो हम केंद्र से उनकी मदद करेंगे। उसका परिणाम, अध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि केंद्र में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नई योजना शुरू की जिस योजना को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जाना जाता है। मैं बाकी जगह प्रदेश की बात तो बाद में करूंगा,

28.03.2018/1630/SLS-HK-2

मैं अगर अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहूं तो अध्यक्ष महोदय, इस योजना के आने से पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र की लगभग 27-28 पंचायतों को सड़की की सुविधा थी लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में 58 में से 56 पंचायतों को सड़कों से जोड़ा गया है जिसमें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसी योजना के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में यह परिस्थिति, जो मेरे सिराज विधान सभा क्षेत्र में हुई तो बाकी विधान सभा क्षेत्रों में भी हम इस बात को वहां पर ज़मीन पर देखते हैं। जब भी हम वहां जाते हैं। ठीक है बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से, दूसरी मदों से, नाबार्ड से, वर्ल्ड बैंक से और प्रदेश के अपने बजट के माध्यम से भी यह काम हुआ और कुछ सड़कें बनीं लेकिन बहुत तेज़ गति अगर इस दिशा में बढ़ी तो उसमें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से सफल हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आज की तारीख में इस बात को भी कहना है कि बहुत हुआ लेकिन उसके बावजूद भी जो हुआ उसमें संतोष की बात नहीं है; अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम उस दिशा में काम करने की कोशिश रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 में हमारा जो जनरल प्लॉन, शैड्यूल्ड कॉस्ट कंपोनैंट और..

28/03/2018/1635/RG/YK/1
मुख्य मंत्री--------जारी

ट्रायबल एरिया सब-प्लान तथा बैकवर्ड एरिया सब-प्लान का पैसा है, इन सबको मिलाकर 1049 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान हमने सड़कों, पुलों, भवनों और मशीनरी के लिए लोक निर्माण के अन्तर्गत रखा है। यदि इससे भी आगे बढ़कर हम देखें, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 250 और इससे ऊपर की आबादी

वाले ऐसे सभी गांवों को जो सड़क से जोड़ना शेष है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऐनुअल प्लानिंग की मीटिंग में भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि हरेक विधायक, विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत अपनी दो-दो प्राथमिकताएं हर वर्ष देते हैं। हम चाहते हैं कि उन सड़कों की जल्दी-से-जल्दी डी.पी.आर्ज. बनें और उन पर काम शुरू हो। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर दुःख है कि जिस भी व्यक्ति ने शुरू किया, अधिकांश लोगों ने शुरूआत वहीं से की। जहां सुबह का प्रश्न खड़ा हुआ था। आज सुबह जो नेशनल हाइवेज़ के बारे में बात कही गई। उसमें कहा गया कि ये सपनों की बातें हैं, यह बहुत मुश्किल है और इसमें कितना बजट प्रावधान है? ये सब कुछ जानते हैं और जान कर भी अनजान होना, यह सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरकार आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचना तो पड़ेगा। अगर सोचेंगे ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमने कम-से-कम सोचा तो सही और सोचा ही नहीं, उस दिशा में व्यवहारिक रूप से मजबूती के साथ कदम भी आगे बढ़ाया है। अब तीन महीने के कार्यकाल में आप हमसे कितना-कितना हिसाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं? सर्व श्री मुकेश जी, राम लाल जी और श्रीमती आशा कुमारी जी ने भी कहा कि ये सड़कें कब बनेंगी, यह सब कैसे होगा? मैं कहना चाहता हूं कि आप सब समय की गिनती में बहुत ज्यादा क्यों उलझ गए हैं कि यह कब तक होगा? यह सब कुछ होगा। मेरा इतना ही कहना है कि थोड़ा सा इन्तजार करिए।

अध्यक्ष महोदय, आज तक की वर्तमान स्थिति को देखकर अगर मैं नेशनल हाइवेज के बारे में बात कहूं, तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इसमें पूछा गया कि डी.पी.आर्ज. किसके माध्यम से और कौन-कौन सी बनेंगी? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 62 डी.पी.आर्ज. लोक निर्माण विभाग बनाएगा, 8 डी.पी.आर्ज. की ऑउटसोर्सिंग का काम जो इनके समय में हुआ जिसको लगभग सवा साल का समय लग गया और वर्तमान सरकार के समय में या हमारे तीन महीने के कार्यकाल में, मैं

28/03/2018/1635/RG/YK/2

इसमें थोड़ा सा करैक्शन भी करना चाह रहा हूं क्योंकि सुबह की फिगर और इस समय

की फिगर में थोड़ा सा फर्क है। अभी यह फैक्चुअल फिगर मेरे पास आई है। तो वर्तमान सरकार ने अभी तीन महीने के कार्यकाल में इसके लिए 38 कन्सलटेंट्स नियुक्त किए हैं और भारत सरकार की अप्रूवल के हमने भेजी हुई हैं जो वहां लम्बित हैं वे 12 हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे 6 ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं जिनके लिए अभी तक कंसलटेंट्स की प्रक्रिया चालू है। ये फैक्चुअल पोजीशन हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने सौ दिन की बात कही है, हमने कहा है कि सौ दिन में हम कोशिश करेंगे कि सारी डी.पी.आर्ज. की कन्सलटेंसी के टैण्डर्ज की प्रक्रिया पूरी हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यदि पूरी नहीं होती, तो हम 62 में से 58 डी.पी.आर्ज. की कंसलटेंसी के टैण्डर्ज की प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में हो पाएंगे। मुझे लगता है कि आप इस गति को धीमा मत मानिए। आपको शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन आप हमारे काम करने के तरीके पर थोड़ा विश्वास रखिए, मेरा आपसे यही निवेदन है।

28.03.2018/1640/जेके/एजी/1

मुख्य मंत्रीः----जारी------

मुकेश जी ने कहा कि डी0पी0आर0 की कन्सलटैंसी के साथ-साथ आगे भूमि अधिग्रहण और एफ0सी0ए0 की परमिशन, दूसरी जो एन0ओ0सी0 बगैरह होती है उन सारी चीजों में वक्त लगता है। डी0पी0आर0 के बारे में आपने पूछा कि डी0पी0आर0 कितने टाइम के अन्दर बननी चाहिए। इसमें आठ महीने का समय होता है। डी0पी0आर0 के लिए आठ महीने का वक्त देते हैं और डी0पी0आर0 की स्वीकृति के बाद उसकी नोटिफिकेशन की जाएगी तथा उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। बाकी बहुत सारी चीजों के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने कुछ जिक्र किए हैं लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि हमारे पास जितने भी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए, उनमें बहुत अच्छे सुझाव भी दिए मैं उन सुझावों का स्वागत भी करता हूं। सभी लोगों ने इस बात की आशंका की है कि हमारे पास बजट प्रोविज़न उतना नहीं है जितनी आपकी रिक्वायरमैंट है। मैं इस बात से सहमत भी हूं लेकिन मैं फिर भी इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर कुछ

लोगों ने कनैक्टिविटी के साथ-साथ इस बात पर भी फोकस किया है और अपनी बात कहने की कोशिश की है कि सड़कें बनें मगर सड़कों की क्वालिटी के साथ कम्प्रोमाइज़ न हो, अच्छी सड़कें बनें। उस दृष्टि से हमने मेंटिनैंस में जो इस बार फाईनैंशियली इन्क्रीज़ किया है वह आज तक की सबसे अधिक इन्क्रीज़ है। बजट में हमने 43 परसेंट इन्क्रीज़ किया है। फिज़िकल टारगेट मेंटिनैंस के लिए भी इस बार हमने बढ़ाए हैं। 40 परसेंट इन्क्रीज हैं और आज से पहले इतना नहीं होता था। ठीक है, थोड़ा-बहुत हमेशा होता था और थोड़ी इन्क्रीज़ होती थी लेकिन अब की बार हमने कहा है कि रोड़ अच्छे बनें, ये हमारी प्राथमिकता है। सड़कें बनें यह तो प्राथमिकता है ही लेकिन सड़कें अच्छी बनें यह हमारी प्राथमिकता निश्चित रूप से होनी चाहिए। उस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय, हमने यह काम करने की कोशिश की है। उसके बाद नाबार्ड की बात कही गई। नाबार्ड के बारे

28.03.2018/1640/जेके/एजी/2

में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी माननीय विधायक जो अपनी प्राथमिकता देते हैं उन सड़कों को नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत करने के लिए हम प्रोसैस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो दो सड़कें हों उनकी डी0पी0आर0 जल्दी बनें। यह सचमुच में हमारे लिए कठिनाई है जिसमें हमें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यह सारी क्लीयरैंसिज़ और क्लीयरैंसिज़ के साथ-साथ यहां पर इस बात का जिक्र अधिकांश माननीय सदस्यों ने किया कि हम विधायक प्राथमिकता में डालते हैं और विधायक प्राथमिकता में डालने के पश्चात् सड़क की स्वीकृति का इन्तज़ार करते हैं और वर्षों बीत जाते हैं लेकिन सड़कों की स्वीकृति नहीं हो पाती है। बाद में ज़वाब यह आता है कि डी0पी0आर0 बन रही है, डी0पी0आर0 बन कर तैयार हुई तो उसके बाद एफ0सी0ए0 की क्लीयरैंसिज़ का इशू आता है ।इस तरह से इसमें बहुत सारा वक्त चला जाता है। यह हमारे लिए भी चिन्ता का विषय है और अध्यक्ष महोदय, मैंने अब की बार एन्वल प्लानिंग की मीटिंग में भी कहा है कि हम इस बजट सत्र के पश्चात इसका

मैकेनिज़्म डवैल्प करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा और कम समय में सारी अप्रूवल, जितनी भी फोरैस्ट क्लीयरैंसिज़ से सम्बन्धित हैं और उसके साथ और भी जो क्लीयरैंसिज़ हैं, उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर इशूज़ होते हैं। प्राइवेट लैंड की सारी फोरमैलिटी भी एक लम्बा प्रोसैस होता है । कई बार वह जल्दी नहीं हो पाता लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि ऐसा मैकेनिज़्म करें। कम से कम फोरैस्ट की क्लीयरैंस जल्दी से जल्दी हो सके। इसके साथ-साथ हमारी जितनी भी प्राइवेट लैंड है, उसके एफिडेविट बगैरह ले करके उसकी फोरमैलिटी कम्पलीट करके उस ज़मीन को हम पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के पास ले कर उस पर काम जल्दी से जल्दी कर सके। अध्यक्ष महोदय, आर0आई0डी0एफ0 का जो हमारा सेकिंड फेज़ है

28.03.2018/1645/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

और उसके बाद 2017-18 तक कुल 1609 योजनाएं, जिसमें 1297 सड़कें तथा 312 पुल शामिल हैं ये स्वीकृत हुए हैं जिनकी कुल स्वीकृत राशि 3857.62 करोड़ रुपये है। लगभग सब माननीय सदस्यों ने नाबार्ड को छुआ है इसलिए मैं इस बात का ज़िक्र करने की कोशिश कर रहा हूं। जिनमें से 1149 योजनाएं और जिसमें 903 सड़कें तथा 256 पुल बन कर तैयार हो गए हैं तथा शेष का कार्य प्रगति पर है। जनवरी, 2018 तक नाबार्ड के तहत 2610.24 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। 2018-19 में माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 368 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान नाबार्ड कार्यों के लिए किया गया है जोकि पिछले वित्त वर्ष 2017-18 के बजट प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक है। इसमें भी हमने इंक्रीज किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि समय की बहुत कमी है अगर हम फिगर्ज़ के हिसाब से जायेंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा। उसी प्रकार से पी0एम0जी0एस0वाई0 और उसके साथ-साथ जो नेशनल हाईवेज़ के बजट प्रावधान हैं उनमें लगातार हर वर्ष बढ़ोत्तरी होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ विषयों को लेकर यहां पर बातें कही हैं। एक तो माननीय सदस्य, सिंघा जी ने बात कही है कि हम सड़कों के पैरापिट लगाते हैं। आज की तारीख में इसकी आवश्यकता नहीं है अगर हम इसकी जगह क्रैश बैरियर की तरफ जाएं तो वह ज्यादा उपयोगी होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन हमारे लिए मुश्किल यह है कि उसमें कॉस्ट का बहुत ज्यादा अन्तर है। उसके बावजूद भी जितना सम्भव हो पा रहा है उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे-धीरे फेज़ड मैनर में हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। खासतौर से जो ब्लैक सपोट्स हैं जहां पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं वे हमारी प्राथमिकता में हैं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने इन सारी चीज़ों के लिए जैसे कि क्रैश बैरियर, रोड सेफ्टी इत्यादि के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ का बजट प्रावधान रखा है। लेकिन मैं उसके बावजूद भी सहमत हूं कि इसमें जितने पैसे की आवश्यकता है उस हिसाब से यह काफी नहीं है। उस दृष्टि से हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि जल्दी-से-जल्दी सारी चीज़ें उस तरह से ठीक हों ताकि यह काम स्थाई रूप से पक्का हो। यह बात

28.03.2018/1645/SS-AG/2

हमारे ध्यान में है लेकिन आज की परिस्थिति में यह एक साल में ही सम्भव नहीं है। आने वाले समय में हम इस बात को करने की कोशिश करेंगे।

उसी प्रकार से माननीय राम जी ने कहा, मैं इनको कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंडिया सिर्फ फोरलेनिंग का काम करता है। फोरलेनिंग के प्रोजैक्टस उनके पास हैं और डबल लेन का काम हमारे पी0डब्ल्यू0डी0 के माध्यम से किया जाता है। आपने भी काम की गुणवत्ता के बारे में बात कही है और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि गुणवत्ता प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके लिए हमने पहली बार प्रावधान किया है कि हम अपने ही कार्यालय में एक मोनिटरिंग सिस्टम इवोल्व करेंगे। पहले एक प्रोविजन होता था कि चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल होते थे। चीफ इंजीनियर के साथ-साथ ई0एन0सी और अन्य अधिकारी होते थे लेकिन फिर भी हमको लगा और हमने बहुत सारे लोगों से इस बारे में बातचीत की तथा बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप डिपार्टमैंट के माध्यम से ही इसको मोनिटर करते हैं और इसमें फोकस उस तरह से नहीं हो पाता है। पारदर्शिता भी उसमें नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर उसी डिपार्टमैंट

के अधिकारी इंस्पैक्शन पर भेजते हैं तो जब वे सैम्पल वहां से उठाते हैं और देखते हैं कि क्वालिटी वर्क हुआ है या नहीं तो उन सारी बातों को लेकर बहुत सारे प्रश्नचिन्ह खड़े हो जाते हैं।

28.03.2018/1650/केएस/डीसी/1

मुख्य मंत्री जारी---

तो हमने कहा कि इस सारे सिस्टम को हटा देते हैं। हमने कहा कि इसके लिए अलग से एक सैल हम वहां पर कंस्टिट्यूट करेंगें और उसके अतंर्गत क्वालिटी कंट्रोल के लिए फ्लाइंग स्क्वैड अलग से कंस्टिट्यूट करेंगें जो सीधा अपने कार्यालय के अधीन होगा और उसके अंतर्गत जहां से भी हमको कोई शिकायत मिलती है, जहां भी हमें लगता है कि इस सड़क का, इस काम का हमको सैम्पल लेना है तो स्वतंत्र हो कर, किसी दवाब में न जा कर सैम्पल ले कर उसकी प्रॉपर इन्वैस्टिगेशन होगी और उसके बाद यह भी सुनिश्चित करेंगें कि अगर कोई क्वालिटी में कम्प्रोमाइज़ करता है तो उसमें जो कार्रवाई करने की बात होगी, उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगें। और अध्यक्ष महोदय, यह कदम हटकर है।

अध्यक्ष जी, बहुत सारे लोगों ने लेबर का इशू उठाया। यह हकीकत है क्योंकि आज के इस दौर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेबर वाला कम्पोनैंट हर डिपार्टमैंट में कम होता जा रहा है। खासतौर से अगर हम लोक निर्माण विभाग की बात करें तो लोक निर्माण विभाग में आज की तारीख में बहुत अच्छी मशीनरी आ गई है और लेबर का खर्चा भी बहुत ज्यादा जाता था और काम भी धीरे से होता था। एक जमाना था कि सड़क को बनाने के लिए गेंती और बेल्चा ही होते थे। आज मशीनें हैं और बहुत पावरफुल मशीनरीज़ हमारे पास हैं। उनके माध्यम से हम तेज गति से सड़कें बना रहे हैं। फिर बात की गई कि आपके पास मशीनों को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है, ऑप्रेटर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति नहीं है । कहीं अगर हमको आवश्यकता रहती है तो समय-समय पर हम विभाग के माध्यम से जे.सी.बी. और मशीनरी हायर करके भी काम कर सकते हैं ताकि सड़कों का काम जल्दी से जल्दी हो सके।

यह बात ठीक है कि लेबर में कमी आ रही है लेकिन स्वभाविक रूप से आज की तारीख में कमी होगी भी। कुल्लू के विधायक श्री सुन्दर सिंह जी ने अलाइनमैंट की बात की। यह बात ठीक है कि जब हम नेशनल हाईवेज़ का प्रोजैक्ट सेंक्शन कर रहे हैं उसमें हमारी कोशिश है कि डिस्टैंस कम हो। क्योंकि हिमाचल की ज्योग्राफिकल कंडिशन्ज़ ऐसी हैं कि यहां मोड़ को अवाइड करना कई जगह कठिन होता है लेकिन उसके बावजूद भी जहां किया जा सकता है, वहां करने की पूरी कोशिश रहेगी और हम सुनिश्चित करेंगें कि अगर

28.03.2018/1650/केएस/डीसी/2

नेशनल हाइवेज़ के माध्यम से फोर लेन के माध्यम से कोई भी सड़क का निर्माण हो तो उसमें ज्यादा मोड़ न हो, सीधी सड़क हो जिसमें चलने में हमें कठिनाई न हो और उसमें एक्सिडैंट भी कम हो, यह सुनिश्चित करने की हमारी कोशिश हमेशा रही है और इसको करेंगें भी।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती आशा कुमारी जी ने पठानकोट-चम्बा-भरमौर नेशनल हाइवे के रख-रखाव की भी बात कही है। इसका रख-रखाव किया भी जाता है लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जो बात कही है कि कुछ जगह स्थिति खराब है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगें। पर्टिकुलर नेशनल हाइवे डबल लेन का कार्य आर.डी-39 से 65 तक का मामला उठाया था वह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बीच में आपने इस बात का भी जिक्र किया कि वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी में से कुछ पोर्शन जाता है इसके फैलिंग ऑर्डर का मामला वन विभाग के साथ हम उठाएंगें और निश्चित रूप से इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगें। बाकी मशीनरी के सम्बन्ध में भी मैंने बात कही, जो आपने एक प्रश्न उठाया था । बहुत सारे सदस्यों ने रैस्ट हाउसिज़ की खराब हालत का भी ज़िक्र किया। यह हम सभी के सामने एक स्थिति है और आज की तारीख में हमारे पास जितनी तादाद में सर्किट हाउस और रैस्ट हाउस हैं, उनको अगर मेंटेंन करना है तो आसान काम नहीं है। वहां पर लेबर रखना जरूरी है क्योंकि वहां पर मशीनरी से तो काम नहीं हो सकता । लेबर रखना भी मंहगा पड़ रहा है । इसके साथ दूसरी और चीजों को भी, उसकी बिल्डिंग के इन्फ्रास्ट्रक्चर को इन्टैक्ट रखना, मेंटेन

रखना भी कठिन काम है।

28.3.2018/1655/av/dc/1

मुख्य मंत्री जारी

विभाग के माध्यम से इसको जितना-जितना किया जा सकता है हम उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। बहुत सारे माननीय सदस्यों की चिन्ताएं और सुझाव लगभग एक जैसे हैं, इनमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। सब चाहते हैं कि सड़कें तेज गति से बनें और यह सच्चाई है कि आज सड़क बनती है तो कल उसको पक्का करने के की मांग आ जाती है। सड़कों का पक्का होना बहुत जरूरी है क्योंकि सड़कें पक्की होने से ही हमें यातायात की अच्छी सुविधा मिल सकती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य होने के कारण हमारी यह प्राथमिकता निश्चित रूप से होनी चाहिए। विशेषकर हमारे जो रोड टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स की ओर जाते हैं वे तो कम-से-कम अच्छे होने चाहिए। कई जगह हमें फोर लेनिंग की वजह से एक-दो साल कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ेगा लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सड़कों को जल्दी-से-जल्दी प्राथमिकता में ले जाएं जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर करती है। इसमें अगर किसी सड़क में कर्व को इम्प्रूव करने की बात है तो उसमें इम्प्रूवमैंट की जाए। इसके अतिरिक्त सड़कों के रख-रखाव पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि यहां पर टूरिस्ट आराम से आए-जाए। हमारे पास टूरिस्ट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग के सिवाय यातायात का दूसरा कोई माध्यम नहीं है। इसलिए हमारे विभाग की इसके लिए निश्चित रूप से प्राथमिकता रहेगी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी सड़कें हमारी ऐसी हैं जहां पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा रहता है। इसमें कुछ सड़कें हमारी एम0डी0आर0 में आती है और कुछ सड़कें स्टेट हाई-वे में आती हैं। जिन सड़कों के माध्यम से लोगों का भारी संख्या में आना-जाना लगा रहता है उन सड़कों को क्वालिटी की दृष्टि से जितना भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता होगी हम उसको करेंगे।

मगर यह भी सच्चाई है कि बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और उनको सुधारने में समय लगेगा। हम उनको ठीक करने के लिए भी जल्दी-से-जल्दी प्रयास करेंगे। यहां पर सीजन को लेकर

28.3.2018/1655/av/dc/2

बात की गई कि टारिंग/मैटलिंग का काम कब शुरू करना चाहिए। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अपने वर्किंग सीजन में समय रहते सारे काम करेंगे। हमने अपने लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारियों को इस बारे में आदेश दे दिए हैं कि वर्किंग सीजन में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हमारे पास बिचुमन की कमी है, मैटीरियल की कमी है या टैंडर डीले हो गया। हम उस वर्किंग सीजन का ज्याद-से-ज्यादा लाभ लेंगे ताकि सड़कों को अच्छी हालत में ला सके। अभी यहां पर (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, एक मिनट। पांच बज गये हैं, अब इस मान्य सदन का कितना समय बढ़ाया जाए?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं दस मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सदस्यगण : मुख्य मंत्री जी का उत्तर आ जाए, मांग कल पारित कर लेंगे।

अध्यक्ष : तो फिर बचा हुआ उत्तर भी माननीय मुख्य मंत्री कल दे देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी, जब मांग कल पारित होनी है तो बचा हुआ उत्तर भी कल दीजिए।

श्री वीरभद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी का उत्तर आज ही आ जाना चाहिए क्योंकि आधा उत्तर कल देना परम्परा के विरुद्ध होगा।

मुख्य मंत्री : मुझे उत्तर देने में न आज दिक्कत है और न कल दिक्कत होगी लेकिन मेरा विषय केवल व्यवस्था से सम्बंधित है। अध्यक्ष जी ने समय की व्यवस्था दी थी इसलिए मैं

समझता हूं कि जो मैंने अभी तक उत्तर दिया है यह पर्याप्त है। अगर आप लोगों को मेरे उत्तर से संतोष है तो (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : नहीं, आप अपनी बात रखिए, मांग को कल पारित कर लेंगे। आप अपनी बात पूरी कर लो।

28.3.2018/1655/av/dc/3

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, कट मोशन में हाउस का समय नहीं बढ़ाया जाता।

अध्यक्ष : हम हाउस का समय नहीं बढ़ाना चाहते मगर माननीय वीरभद्र सिंह जी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और इनका कहना है कि मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर पूरा कर लें।

28.03.2018/1700/TCV/AG-1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, विषय हाउस की परम्परा और व्यवस्था से संबंधित है। मुझे किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज पूरा उत्तर देना है तो आज दे सकता हूं, यदि कल देना है तो कल भी दे सकता हूं। सिर्फ विषय यही है कि अगर हाउस को आगे एक्सटैंड करने की परम्परा नहीं है तो जो मैंने कह दिया, यदि आप इसी में संतुष्ट है तो मैं इसी को अपना उत्तर समझता हूं। आपको लगता है कि और भी लम्बी बात कहनी है तो मैं लम्बी बात भी कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे उत्तर को ध्यान में रखते हुए हमारे मित्र अपना ये कट मोशन वापिस लें।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे?

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने कह दिया कि

हम मुख्य मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हैं।

अध्यक्षः क्या माननीय सदन की अनुमति है कि श्री मुकेश अग्निहोत्री, श्री अनिरूद्ध सिंह, श्रीमती आशा कुमारी, श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री जगत सिंह नेगी, श्री राम लाल ठाकुर, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, श्री नन्द लाल, डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल, श्री राकेश सिंघा, श्री पवन कुमार काजल, श्री लखविन्द्र सिंह राणा, श्री विक्रमादित्य सिंह, श्री आशीष बुटेल और श्री सतपाल सिंह रायजादा के कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिए जायें।

जो इसके पक्ष में हैं, हां कहें,
जो इसके विरूद्ध हैं, न कहें,
हां की, हां की, हां में रही,
कटौती प्रस्ताव वापिस हुए ।

28.03.2018/1700/TCV/AG-2

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 10 'लोक निर्माण' सड़क,पुल एवं भवन के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त दर्शाई गई धनराशियां क्रमशः मु0 33,08,06,03,000/- रुपये (राजस्व) और मु0 12,16,28,02,000/- रुपये (पूंजी) संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार

मांग संख्याः 10 'लोक निर्माण' सड़क,पुल एवं भवन पूर्ण रूप से पारित हुई।

अब इस माननीय सदन की बैठक कल वीरवार दिनांक 29 मार्च, 2018 के 11.00 बज़े पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला- 171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक 28.3.2018 **सचिव।**

****